

कजाखस्तान-भारत संबंध,1991-2017

मास्टर ऑफ फिलासफी

की उपाधि के लिए

लघु शोध-प्रबन्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रस्तुत

हरिकेश बिजोरिया



आन्तरिक एशियाई अध्ययन केंद्र

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली-110067

2018



CENTRE FOR INNER ASIAN STUDIES
SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI-110067, INDIA

Tel.: 011-26704350

Date 20/07/2018

DECLARATION

I declare that the dissertation entitled “कजाखस्तान-भारत संबंध, 1991-2017” submitted by me for the award of the degree of **Master of Philosophy** of Jawaharlal Nehru University is my own work. The dissertation has not been submitted for any other degree of this University or any other university.


Harikesh Bijoria

CERTIFICATE


We recommend that this dissertation be placed before the examiners for evaluation.



Prof. Sharad Kumar Soni


Chairperson


अध्यक्ष / Chairperson
इनर एशियाई अध्ययन केन्द्र
Centre for Inner Asian Studies
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
School of International Studies
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली / New Delhi - 110067



Prof. Sangeeta Thapliyal

Supervisor


इनर एशियाई अध्ययन केन्द्र
Centre for Inner Asian Studies
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
School of International Studies
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली / New Delhi - 110067

समर्पण...

पूज्य माता- पिता

के चरणों में सादर

समर्पित

आभार

मैं अपने शोध निर्देशक प्रो. संगीता थपलियाल के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ जिनके दिशा निर्देशन में यह लघु शोध-प्रबन्ध लिखा गया | यह लघु शोध-प्रबन्ध उनके प्रोत्साहन और प्रेरणा का फल है | इस लघु शोध कार्य में विषय के चुनाव से लेकर समापन तक की कार्यावधि में प्रो. थपलियाल ने जिस तन्मयता से हमारा मार्गदर्शन किया, वह सराहनीय है | लघु शोध प्रबन्ध को हिन्दी में लिखने का निर्णय मेरे लिए कठिन नहीं था, लेकिन प्रो. थपलियाल के लिए कठिन निर्णय जरूर था | मैं कृतज्ञ हूँ कि प्रो. थपलियाल ने स्वाभाविकता से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हिन्दी में इस विषय को लिखने की महत्ता पर विशिष्ट जानकारी भी प्रदान की | प्रो. थपलियाल ने समय-समय पर बारीकी से लघु शोध-प्रबन्ध को बेहतर बनाने के सुझाव दिये | प्रो. थपलियाल से लघु शोध-प्रबन्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्नेह और सद्भाव मिला है | मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा |

आंतरिक एशियाई अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. शरद कुमार सोनी, प्रो मोंदिरा दत्ता, डॉ. अम्बरीष ढाका , डॉ महेश रंजन देवता, और डॉ छेतन नामग्याल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ | जिन्होंने हमेशा मुझे लघु शोध कार्य में प्रोत्साहित किया | प्रो. सोनी के स्नेह को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है |

में डॉ. भीमराव अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी जेएनयू , इडसा (आईडीएसए) लाइब्रेरी, तीनमूर्ति लाइब्रेरी , इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स लाइब्रेरी, कजाखस्तान दूतावास के अधिकारियों और पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनकी वजह से यह लघु शोध कार्य संभव हो पाया है ।

में मेरे सहपाठियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ , जिनके अनवरत साथ और सहयोग की वजह से मेरा यह कार्य बहुत आसान हो गया और मैं यह लघु शोध कार्य पूरा कर सका ।

में बीएचयू और जेएनयू के सभी मित्रों का , विशेषकर पूनम कुमारी प्रसाद और राज कुमार मौर्य का आभार इस दौरान जिनका अमूल्य सहयोग प्राप्त हो सका ।

अन्त में मेरे माता- पिता को यह लघु शोध-प्रबन्ध समर्पित करता हूँ जिनका मेरे प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है । जिन्होंने मुझे ईमानदारी से मेहनत करने का पथ दिखलाया ।

हरिकेश बिजोरिया

विषय-सूची

आभार	IV-V
अध्याय-1	1-17
कजाख़स्तान और भारत के बीच सम्बन्ध : एक समग्र दृष्टिकोण	
अध्याय-2	18-37
राजनीतिक संबंध	
अध्याय-3	38-59
आर्थिक संबंध	
अध्याय-4	60-78
रक्षा सहयोग	
अध्याय-5	79-89
निष्कर्ष	
परिशिष्ट	90-108
संदर्भ सूची	109-118

अध्याय-1

कजाखस्तान और भारत के बीच सम्बन्ध : एक समग्र
दृष्टिकोण

कजाखस्तान मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा भू-आबद्ध देश है तथा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह विश्व में 9वां स्थान रखता है | इसकी सीमाएं रूस, चीन जैसी महाशक्तियों तथा उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान जैसी मध्य एशियाई देशों के साथ लगती है तथा इन देशों के साथ ही साथ कजाखस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से भी सम्बद्ध है, जिससे कजाखस्तान को कैस्पियन सागर से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधन विशेषकर खनिज तेल प्राप्त होता है | कजाखस्तान एशिया और यूरोप के बीच संपर्क स्थल का कार्य भी करता है | इस प्रकार खनिज संसाधनों से संपन्न होने के साथ ही साथ अपनी महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति के कारण यह देश विश्व के भू-राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है | भूगोल का राजनीतिक कार्यों में उपयोग ही भू-राजनीति है | (Pidcock 2007: 1-48)

हेल्फोर्ड जॉन मैकिण्डर ने अपनी रचना “द ज्याॅग्रॉफिकल पिवाॅट ऑफ हिस्ट्री” के अंतर्गत अपने हृदय स्थल सिद्धांत (हर्ट लैंड थ्योरी) में यह प्रतिपादित किया है कि जिस तरह से मानव शरीर को अपने हृदय पर निर्भर रहना पड़ता है उसी प्रकार एक राष्ट्र को शक्तिशाली होने के लिए कुछ विशेष भौगोलिक दशाओं (खनिज संसाधनों की प्रचुरता, समुद्र से निकटता, जनसंख्या, महाद्वीपों के बीच संपर्क-स्थल इत्यादि) की आवश्यकता होती है | मैकिण्डर ने इन्हीं विशेष भौगोलिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए यूरेशियन क्षेत्र को हर्टलैंड की संज्ञा दी है | (Mackinder1904: 421-437)

कजाखस्तान जॉन मैकिण्डर के दिए हुए भू-राजनीति के सिद्धांत पर खरा उतरता है, क्योंकि यह खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और युरेनियम के भण्डार से युक्त है जिसकी आज विश्व के विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में भारी मांग है | इसके साथ ही साथ कजाखस्तान यूरोप और एशिया की संपर्कस्थली होने के अतिरिक्त भू-राजनीतिक रूप से

महत्वपूर्ण देशों जैसे अफगानिस्तान, चीन, रूस, भारत और पश्चिम एशियाई देशों के समीप स्थित है | (Cohen 2006:7-8)

प्राचीनकाल से ही स्टेपी घास के मैदानों में स्थित यह देश घुमक्कड़ स्वभाव वाले कजाक नृजाति के लोगों का निवासस्थल रहा है, जिनके अपने विशेष रीति-रिवाज और शासन के नियम रहे हैं | भले ही ये इस्लाम का पालन करते थे किन्तु इनके इस्लामिक रीति-रिवाजों में स्थानीय संस्कृति और सूफीवाद का भी प्रभाव रहा है | (Sultanova2011: 1-6)

प्रारंभ में इनकी शासन व्यवस्था का स्वरूप कबीलाई रहा था जिसे खानेती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इस व्यवस्था में शासन के प्रमुख को “खान” की उपाधि से संबोधित किया जाता था और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण भू-भाग को खानेती के रूप में जाना जाता था | (Grousset1988: 61-585)

18वीं शताब्दी से ही (रूसी अधिकारिक आकड़ों के अनुसार 1730) जार (रूसी शासकों की उपाधि) द्वारा कजाखस्तान में हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया गया | 19वीं शताब्दी के अंत तक यह देश जारवादी रूसी साम्राज्य का एक हिस्सा बन चुका था | जार के द्वारा कजाको के चले आ रहे परंपरागत शासन व्यवस्था (कबीला या खानेत व्यवस्था) को समाप्त कर दिया गया |¹ कजाखस्तान पर प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण रखने के लिए जारवादी रूस के गृह मन्त्रालय और युद्ध मन्त्रालय के द्वारा 1865 में “स्टेपी कमीशन” का निर्माण किया गया | इस कमीशन के द्वारा सम्पूर्ण कजाकी नृजातीय क्षेत्र को तीन प्रशासनिक भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग को एक गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया जो कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली के लिए सीधे जार के प्रति उत्तरदायी होते थे | जार के द्वारा कजाकों के सांस्कृतिक और धार्मिक

¹ Online Web “ Kazakhstan – India Relations in Historical Prospective” Available at : http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18330/7/07_chapter%201.pdf, Accessed on February 12 ,2018

मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया | स्टेपी कमीशन द्वारा स्थापित किया गया प्रशासन का यह स्वरूप रूस की “बोल्शेविक क्रान्ति” तक चलता रहा | ²

बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में जार के स्थान पर साम्यवादी पार्टी सत्ता में आई, और मध्य एशिया के क्षेत्र को “सोवियत सेंट्रल एशिया” के नाम से जाना गया | 1924 में स्तालिन के द्वारा पूर्ववर्ती जार साम्राज्य को राष्ट्रीयताओं (नृजातीयताओं) के आधार पर पुनर्गठन का निश्चय किया गया | मध्य एशिया के क्षेत्र को नृजातीय बहुलताओं के आधार पर पांच सोवियत समाजवादी गणराज्यों (कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान) में विभाजित किया गया | आरंभ में कजाखस्तान को किर्गीज स्वायत्तशासी गणराज्य के अंतर्गत रखा गया, किन्तु 1936 में कजाख स्वयत्तशासी गणराज्य की स्थापना की गई | (Vaidyanath1967:151)

कजाखस्तान गणराज्य की शासन व्यवस्था कजाख साम्यवादी पार्टी के द्वारा सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत के दिशा निर्देशानुसार किया जाता था | सोवियत समर्थक लेखकों के द्वारा भले ही साम्यवादी पार्टी के शासन को वास्तविक लोकतंत्र माना जाता था, परन्तु वास्तव में यहाँ “एक दल का अधिनायकत्व” विद्यमान था जिसमें कजाकी लोगों को साम्यवादी पार्टी के द्वारा नामांकित किए गए प्रत्याशी को ही निर्वाचित करना पड़ता था | इस तरह सोवियत संघ के दौर में कजाखस्तान में साम्यवादी पार्टी ही राज्य था और राज्य ही सोवियत संघ था | 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् यहाँ पश्चिमी मॉडल की लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई | वर्तमान समय में कजाखस्तान में 9 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जिनमें “नूर वतन पार्टी” सबसे बड़ा दल है | (Embassy of the Republic of the Kazakhstan 2015: 1-2)

² Ibid

वर्तमान समय में कजाखस्तान गणराज्य में राष्ट्रपति का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है | राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख माना जाता है तथा यह कजाखस्तान की सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर भी होता है | राष्ट्रपति को संविधान के तहत वीटो की भी शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग वह अपने विवेक के अनुसार कर सकता है | कजाखस्तान का प्रथम राष्ट्रपति नूर-सुल्तान नज़रबायेव थे जो कि वर्तमान समय में भी इस पद पर कार्यरत हैं | कजाखस्तान की संसद दिवसदनीय है जिसका निम्न सदन (मजिलिस) है तथा उच्च सदन (सीनेट) है | मजलिस में कुल 67 सीटें हैं तथा सीनेट में 39 सीटें हैं, दो सीनेटर का चयन प्रत्येक निर्वाचित विधानसभाओ (मास्लिखत) से किया जाता है | कजाखस्तान में 16 मुख्य प्रशासनिक प्रभाग हैं | (Constitution of the Republic of Kazakhstan 1996: 2-7)

भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व में 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या के आधार पर अपना द्वितीय स्थान पर है | इसके साथ ही साथ इसे विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश के रूप में भी सम्बोधित किया जाता है | इसकी सीमाएं दक्षिण में हिन्द महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती हैं | भारत की 7,517 किलोमीटर लम्बी तटीय रेखा इसके सामरिक और आर्थिक महत्व को दर्शाती है |³

भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और आर्थिक सम्पन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विशेष स्थान रखता है | भारत वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक और राजनैतिक प्रयासों के द्वारा एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कर्ता बनने की ओर अग्रसर है | शीतोत्तर विश्व में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत

³ "Introduction of India " Available at https://web.archive.org/web/20171010161225/http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/BMIntro-1011.pdf Accessed on 14 February, 2018.

बनाने का प्रयास किया जा रहा है | भारत में मौजूद उर्जा संसाधन भारत की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अतः उर्जा संसाधन (विशेषकर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम) भारत की विदेश नीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | 20वीं सदी के अंत तक भारत अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खनिज संसाधनों के परिपूर्ण पश्चिमी एशिया के देशों पर निर्भर रहा है, किन्तु भारत अपनी उर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक देशों की तलाश कर रहा है |⁴

भारत की इन उर्जा संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए कजाखस्तान महत्वपूर्ण देश सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कजाखस्तान खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के भण्डार से परिपूर्ण है | 2005 में, भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु समझौता हो जाने के पश्चात् भारत पूरे विश्व में कहीं से भी यूरेनियम प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और वहीं कजाखस्तान यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है| (Rajagopalan2008:14) इस तरह कजाखस्तान के यूरेनियम के भण्डार भारतीय नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं | वहीं दूसरी तरफ कजाखस्तान अपने ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल अपने देश की आर्थिक समृद्धि हेतु करना चाहता है, इसलिए वह ऊर्जा संसाधनों की उचित कीमतों को प्राप्त करने हेतु व अपने उद्योगों के लिए पूंजी और तकनीकी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है |

वर्तमान समय में भारत की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियाँ तकनीकी और वित्तीय रूप से विश्व में अग्रणी स्थान रखते हैं | अतः भारत कजाखस्तान को तकनीकी और पूंजी के क्षेत्र में कजाखस्तान का सहयोग दे सकता है | (Panchal 2017: 2-3)

⁴ "Report of the FICCI (2011") Available at [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Indias_energy_security/\\$FILE/India-s_energy_security.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Indias_energy_security/$FILE/India-s_energy_security.pdf) Accessed on 17 February, 2018

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कजाखस्तान और भारत के बीच संबंध प्राचीनकाल से ही विद्यमान है | भारत में की गई पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है, कि ये मध्य एशिया के कस्बों में पाये गये हस्तशिल्प तथा जवाहरात हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के समरूप हैं | अतः इन तथ्यों से पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों और मध्य एशिया के लोग एक दूसरे से परचित थे एवं उनके बीच व्यापार-वाणिज्य के कार्य भी संपन्न होते थे | (Abuseitova 2004:1-4)

भारत में शकों का आगमन कजाखस्तान से ही हुआ है, कजाखस्तान को शकों का मूल निवास स्थान माना जाता है | ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 इसवी में शक भारत आ गये थे | (Abdykarimo1994:17)

ऐतिहासिक पहलुओ को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि कजाखस्तान एवं भारत के बीच संपर्क मुख्य रूप से "सिल्क रोड" के द्वारा हुआ | यह रोड चीन से होकर मध्य एशिया के कजाखस्तान, तुरिया, शिमकेंट, तुर्कस्तैन एवं जाम्बुल क्षेत्रों को पार करते हुए यूरोप तक जाता था | इस रोड के कारण भी भारत मध्य एशिया के देशों के संपर्क में आया, जिससे विचारों और ज्ञान का आदान-प्रदान हुआ है | बौद्ध धर्म का प्रसार इसी सिल्क रोड से चीन से होता हुआ मध्य एशिया तक जा पहुँचा | इसी प्रकार सूफी विचारधारा का आगमन मध्य एशिया से भारत में हुआ | इस प्रकार व्यापार-वाणिज्य और धर्मों के आदान-प्रदान के साथ ही साथ गणित, चिकित्सा, औषधियों के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है | (Haidar 2004:42)

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक भारतीय क्रान्तिकारियों ने रूस जाने के लिए मध्य एशिया को सम्पर्क मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जैसे सुभाषचंद्र बोस इत्यादि | सोवियत संघ

के शासन काल में भी भारत और कजाखस्तान और भारत के बीच सम्बन्ध विद्यमान थे । स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1955 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इन्दिरा गाँधी के साथ कजाखस्तान की यात्रा पर गये, जिससे कजाखस्तान और भारत के संबंधों को नई दिशा मिली । सन् 1956 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कजाखस्तान की यात्रा की ।⁵

भारत वह पहला राष्ट्र था जिसने कजाखस्तान को सर्वप्रथम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की । कजाखस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की अपनी पहली यात्रा सन् 1992 में की और अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने कजाखस्तान की “मल्टी-वैक्टर” विदेश नीति पर बल देते हुए दोनों देशों के बीच मौजूद सम्बन्धों को और भी प्रगाढ़ करने की इच्छा व्यक्त की । जिसके परिणामस्वरूप भारत ने अपना दूतावास अलमाटी में स्थापित किया और इसके बाद कजाखस्तान ने 1993 में नई दिल्ली में अपना दूतावास आरम्भ किया ।⁶ कजाखस्तान और भारत के बीच संबंधों में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । भारत दुनिया में ऊर्जा संसाधनों का छठा सबसे बड़ा आयातक देश है तथा इसकी जरूरतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत की आर्थिक संवृद्धि इस बात पर निर्भर करती है, कि भारत को निर्बाध रूप से उर्जा संसाधन प्राप्त होते रहें । वर्तमान समय में भारत हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत अरब देशों और ईरान से प्राप्त करता है । (Dadwal 2006:653-670) कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों व अपने पास अधिक विकल्पों को रखने के लिए भारत उर्जा संसाधनों के वैकल्पिक स्रोतों की खोज कर रहा है ताकि वह किसी देश विशेष पर निर्भर न रहे । भारत कजाखस्तान को एक संभावित स्थान के रूप में देखता है जहाँ से कम कीमतों पर खनिज

⁵ “ India –Kazakhstan relations” Available at: http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Kazakhstan1__July_2016.pdf Accessed on: February 18, 2018.

⁶ Ibid.

तेल का आयात किया जा सकता है | भारतीय कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) कजाखस्तान के तेल खनन केन्द्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है | (Tong and Gill 2017:4304-4312)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व के कुछ शक्तिशाली राष्ट्र मध्य एशिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए “न्यू ग्रेट गेम” खेलने में लगे हुये हैं, ये देश स्वयं को लाभान्वित करने के लिए तेल और गैस पाइपलाइन मार्गों के स्थान को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं | यदि भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो चीन की सीमा मध्य एशिया के क्षेत्रों से लगी हुई है | चीन कजाखस्तान के साथ एक लम्बी सीमा रेखा साझा करता है | चीनी कम्पनियाँ कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था में अपनी गहरी पैठ बनाने का प्रयास कर रही हैं, किन्तु चीन के बारे में विभिन्न देशों की एक साझा समझ यह है कि जिन-जिन देशों की अर्थव्यवस्था पर चीन ने मजबूत पकड़ बनाई है वह वहां के आन्तरिक और राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगता है जैसे पाकिस्तान में | (Khaliq 2018:1-6) इसी तरह चीन ने श्रीलंका को आधारगत संरचना विकसित करने के लिए दिए गए अपने 1 अरब डालर के कर्ज को श्रीलंका द्वारा न चुका पाने की स्थिति में उसका (श्रीलंका) का हम्बनटोटा बन्दरगाह 99 वर्षों की पट्टे (लीज) पर ले लिया (Habib 2018: 1-19) | अतः चीन की भूमिका को लेकर कजाखस्तान में भी सन्देह विद्यमान है |

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत को लेकर विश्व के अधिकांश देशों में यह विश्वास है कि भारत किसी देश की आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है अर्थात् भारत अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए केवल “साफ्ट पावर” का ही प्रयोग करता है, जैसे भारत सैन्य क्षमता, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक आकार में भूटान से कई गुना बड़ा है, किन्तु फिर भी भारत भूटान के आन्तरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करता है | अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य एशियाई देशों ने भी भारत की रचनात्मक भूमिका का समर्थन किया है | इन देशों ने भारत की

गुटनिरपेक्ष नीति का भी समर्थन किया है | एक तरफ भारत जहाँ कजाखस्तान के साथ आर्थिक मामलों में सहयोग कर सकता है वहीं दूसरी तरफ कजाखस्तान भारत के सहयोग से चीन का प्रतिरोध भी कर सकता है | (Blarel 2012: 28-33)

कजाखस्तान और भारत के बीच जुलाई 2015 में 5000 टन यूरेनियम की आपूर्ति करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है | भारत जैसा विशाल राष्ट्र कजाखस्तान के लिए नई मार्केटिंग के रास्ते खोलता है जो कजाखस्तान के लिए काफी हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं | (Press trust of India 2015:1-2)

कजाखस्तान और भारत के बीच दो दशक पूर्व की गई द्विपक्षीय कर संधि को जनवरी 2017 में दोनों देशों की सरकारों ने एक नया संशोधित रूप देकर फिर से लागू किया है | पूर्व में इस संधि में दोनों देशों के मध्य दोहरे कर की रोकथाम के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, किन्तु संशोधित द्विपक्षीय कर संधि के अंतर्गत कानूनी सूचनाओं के आदान-प्रदान करने एवं प्रभावी विनिमय को ध्यान में रखते हुये समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देशों के बीच करों के संबंध में दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभ खंड की सीमा प्रदान करेंगी और जिससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक रूप से विश्वास जागने के आसार हैं | (Press trust of India 2017:1)

भारत द्वारा कजाखस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को और अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कजाखस्तान के साथ अपने यातायात संपर्क को बनाने के लिए अफगानिस्तान में जिराम-देलराम सड़क का निर्माण किया गया है |(The Hindu 2009) भारत द्वारा कजाखस्तान के साथ संबंधों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए नए कदम उठाने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें “कनेक्ट टु सेंट्रल एशिया पॉलिसी” के तहत 12

सूत्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने का उद्देश्य रखा है | इन दोनों देशों के अंतर्गत 2011-12 में कुल व्यापार 436.25 मिलियन डॉलर था और 2015-16 में कुल व्यापार 504 मिलियन डॉलर हुआ है | दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल-दिसंबर 2015 में 412.39 मिलियन डॉलर था | इस काल में भारत से कजाखस्तान को होने वाला कुल निर्यात 113.16 मिलियन डॉलर था और आयात 229.23 डॉलर था | भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में दवाइयाँ, चाय, मशीनरी उपकरण एवं तम्बाकू हैं | कजाखस्तान से आयात होने वाली वस्तुओं में तेल, यूरेनियम और टाइटेनियम है | कजाखस्तान में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है जैसे बैंकिंग, इंजीनियरिंग, खनन और सेवा क्षेत्र इत्यादि | इन सभी बातों से ज्ञात होता है कि भारत और कजाखस्तान के बीच आर्थिक रिश्ते विकासमान हैं | (Ministry of External Affairs 2016)

सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाखस्तान विश्व क्षितिज पर एक नए देश के रूप में उभरा | जिसको अपने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए विश्व के अन्य देशों से सहयोग की अपेक्षा थी | अतः कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया | भारत और कजाखस्तान के कूटनीतिक संबंध 1991 से तभी से आरंभ हो गए थे जब भारत ने कजाखस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी | 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कजाखस्तान की यात्रा की | इसके अलावा नजरबायेव ने 1996, 2002, 2009 में भारत की यात्रा की है | इन यात्राओं से कजाखस्तान-भारत के संबंधों को प्रोत्साहन मिला | इन दोनों देशों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाये रखना है | (Ibid)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के सम्मुख समान समस्याएँ विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं - विकास में असमानता, आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी इत्यादि | भारत और कजाखस्तान मिलकर बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं | इस संबंध में विभिन्न उदाहरण

देखे जा सकते हैं | कीका (C.I.C.A.) यह मध्य एशिया का एक फोरम है, जिसमें भारत को सदस्यता प्रदान की गई है तथा भारत इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है | इसके अतिरिक्त भारत संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.), संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि संगठनों में कजाखस्तान के साथ शामिल है | कजाखस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रमुख पक्षधर है | (Ibid)

भारत मध्य एशिया में फैल रहे इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध कजाखस्तान के साथ सहयोग कर रहा है | भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मध्य एशियाई देशों की यात्रा में इस संबंध में चिंता व्यक्त की और आतंकवाद के विरुद्ध साझे संघर्ष का आह्वान किया | (Ibid)

चूँकि मध्य एशियाई गणराज्य धर्मनिरपेक्ष है, अतः चरमपंथी इस्लामिक संगठनों जैसे “इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान” इत्यादि के द्वारा इन देशों की सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास किए जाते हैं | इसी तरह भारत के कश्मीर में इस्लामिक चरमपंथी संगठनों जैसे जमात-उद-दवा इत्यादि द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ जारी हैं जो देश को साम्प्रदायिक तनाव की तरफ ले जाने का कार्य करती हैं | भारत और मध्य एशियाई देशों में सक्रिय इन आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में अपनी जड़े मजबूत कर चुके अल-कायदा जैसे संगठनों से ट्रेनिंग और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के द्वारा आर्थिक और वैचारिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है | इस तरह इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा एशिया महाद्वीप के साथ ही साथ पूरे विश्व में अस्थिरता फैलाई जा रही है | इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष भारत और कजाखस्तान के बीच सैन्य सहयोग के एक नए क्षेत्र के रूप में उभरा है |

कजाखस्तान एवं भारत की सुरक्षा को देखते हुए कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाँच सूत्रीय समझौते के तहत जुलाई 2015 में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सैन्य सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं | (Ibid))

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य सैन्य बल को शक्तिशाली बनाना है वर्तमान समय में एक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यधिक महत्त्व है | भारत की रणनीति स्वायत्तता के साथ - साथ बाहरी सेना का सामना करके देश को सुरक्षा प्रदान करना है | इससे यह तात्पर्य है कि भारत को आंतरिक और गैर परंपरागत खतरों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा | इसके साथ-साथ राजनीतिक और राजनयिक साधनों की भी आवश्यकता है | इस उपलब्धि को पाने के लिए भारत को समयबद्ध तरीके से घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय रणनीति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कजाखस्तान जैसे विभिन्न राष्ट्रों के साथ सुरक्षा सहयोग करना अति उपयोगी है | (Stobdan 2008:1-7)

कजाखस्तान और भारत के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध प्राचीनकाल से ही जुड़े हुये है | कजाखस्तान से आए गए विभिन्न जातीय समूह भारत में कुषाण एवं शक इत्यादि नामों से जाने गये | मध्य एशिया में पाये गये बौद्ध स्तूप इस बात को प्रस्तुत करते है कि भारत-कजाखस्तान के संबंध काफी लम्बे समय से रहे है | सूफी धर्म जोकि इस्लाम की एक शाखा है, भारत में उसका आगमन मध्य एशिया से ही हुआ है | इसके साथ ही साथ यदि हम देखें तो भारत के प्रसिद्ध मुगल वंश के संस्थापक बाबर मध्य एशिया के फरगाना घाटी में स्थित अंदीजान के मूलनिवासी थे | इन सभी तथ्यों से यह ज्ञात होता है, कि भारत और कजाखस्तान के सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध किसी न किसी रूप में परस्पर जुड़े हुये हैं | (Roy 2002: 48-64)

कजाखस्तान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अलमाटी में मई 1994 में भारत और कजाखस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और कजाखस्तान के बीच आपसी सांस्कृतिक समझ को बढ़ाना है | कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में भारतीय दूतावास के सहयोग से सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं | कजाखस्तान के लोग भारतीय फिल्म और संगीत एवं योगा में रुचि रखते हैं इसीलिए वहाँ भारतीय दूतावास के द्वारा योग और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और भारतीय त्योहारों को कजाखस्तान में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है | (Ministry of External Affairs 2016) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2015 को जब कजाखस्तान की यात्रा पर गए थे, तब कजाखस्तान की सरकार के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था | कजाखस्तान में भारतीय फिल्मों काफी लोकप्रिय हैं | भारत द्वारा इस मध्य एशियाई देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया जाता है | भारत द्वारा कजाखस्तान के शोध छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है | भारत द्वारा कजाखस्तान के शोध छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती रही है जो कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स (ICCR) के द्वारा 1992 से प्रारम्भ की गई है जिसके तहत 200 विधार्थियों को भारत में शोध करने का अवसर दिया जाता है |(Ibid)

इसके अलावा, कई प्रतिष्ठित भारतीय विद्वानों ने कजाकिस्तान का दौरा किया और भारतीय संस्कृति एवं समकालीन मामलों पर व्याख्यान दिए हैं, इन महत्वपूर्ण लोगों में प्रोफेसरों की यात्रा शामिल है। जनवरी 1995 में अश्विनी कुमार रे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कजाखस्तान में बोलने वाले पहले भारतीय रिसर्च स्कॉलर है | उसी वर्ष निर्मला देशपांडे 125 वीं गाँधी जयंती के शुभ अवसर पर कजाखस्तान के एकेडमी ऑफ साइंसेज के दर्शन संस्थान में गांधीवाद पर कई व्याख्यान दिए हैं | (Sengupta,2000:189-183)

इस लघु शोध-प्रबंध के अंतर्गत हमने अपने शोध प्रारूप के मुख्य तथ्यों को उजागर किया है जो इस शोध के प्रारूप को परिलक्षित करते हैं, जिनमें उपयोग कि जाने वाली परिभाषा और प्रासंगिकता एवं क्षेत्र, शोध प्रश्न, शोध परिकल्पना शोध विधि, अध्यायीकरण की योजना को दर्शाया गया है |

कजाखस्तान 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में आस्तित्व में आया, इसके पूर्व यह सोवियत संघ का हिस्सा था कजाखस्तान में ऑयल गैस और संसाधन अतिरिक्त मात्रा में पाये जाते हैं | कजाखस्तान की विदेश नीति में ऊर्जा संसाधन प्रमुख स्थान रखता है | कजाखस्तान अपनी भौगोलिक व ऊर्जा संसाधनो में विशेषकर खनिज तेल और यूरेनियम के कारण विश्व की प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जोकि रूस, चीन व अमेरिका के बीच इसके खनिज संसाधनो के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धा है | वहीं भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है जोकि वर्तमान स्थिति में विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में प्रमुख है | भारत में अपनी औद्योगिक, नागरिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए पर्याप्त ऊर्जा संसाधनो का अभाव है, अतः भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है | भारत अपनी ऊर्जा संसाधनो की आपूर्ति के लिए किसी एक देश पर निर्भर न होकर कई देशों से ऊर्जा संसाधनो का आयात करता है |

भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाखस्तान महत्वपूर्ण देश सिद्ध हो सकता है, इसके लिए आर्थिक राजनीतिक संबंधो को और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास करने की आवश्यकता है | 2005 में भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु समझौता हो जाने के पश्चात् भारत पूरे विश्व से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, और कजाखस्तान में यूरेनियम के अपार भण्डार हैं, जो कि भारतीय नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं | कजाखस्तान के ऊर्जा संसाधन और भू-राजनीतिक स्थिति पर अब तक काफी शोध

कार्य हुए है किन्तु कजाखस्तान और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक, और रक्षा क्षेत्र में अभी भी संबंध मजबूत नहीं हुये है | आर्थिक ,राजनीतिक और रक्षा संबंधो को कैसे मजबूत किया जाए, इस संबंध में शोध कार्य का अभाव है |

शोध प्रश्नों को इस प्रकार से दर्शाया गया है | कजाखस्तान के साथ संबंधो को घनिष्ठ करने के लिए भारत द्वारा क्या-क्या उपाये किये जा रहे है?, क्या कजाखस्तान के यूरेनियम भण्डार भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे?, क्या कजाखस्तान सूचना-तकनीकी तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेगा?, भारत और कजाखस्तान के बीच यातायात संपर्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है?

प्रस्तावित शोध प्रारूप में परिकल्पना को इस प्रकार से रखा गया है, हमारी पहली शोध परिकल्पना भारत और कजाखस्तान के मध्य व्यापार 1991 से 2017 के बीच तेजी से बढ़ा है क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरक है और द्वितीय शोध परिकल्पना “कजाखस्तान एवं भारत दोनों ही देश आतंकवाद व नशीले पदार्थों की तस्करी से पीड़ित है जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ रहा है |

शोध के प्रारूप के अंतर्गत शोध विधि को इस प्रकार से परिलक्षित किया गया है, यह शोध कजाखस्तान और भारत के बीच संबंधों पर प्रस्तावित अध्ययन ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित होगा | इस प्रस्तावित शोध में कजाखस्तान और भारत के बीच विभिन्न नीतियों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाएगा | इस प्रस्तावित शोध में स्वतंत्र और आश्रित दोनों चरों का प्रयोग किया जायेगा | यह प्रस्तावित शोध प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होगा | प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, रिपोर्टों जो कजाखस्तान एवं भारत के संगठनों के द्वारा किया गया होगा और इसी के साथ-साथ

अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के प्रस्ताव, संधियाँ, घोषणापत्रों, सर्वे, तथा अन्य तथ्यों की सहायता लिया जाएगा | द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सन्दर्भ किताबों, जर्नल, आर्टिकल, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और इन्टरनेट सामाग्री को प्रयोग में लाया जाएगा और सेमिनार, वर्कशॉप की सूचनाओं द्वारा शोध को सम्पुष्ट किया जाएगा |

प्रस्तावित अध्ययन के अध्यायीकरण के लिए योजना को हमने पाँच अध्यायों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से हैं, प्रथम अध्याय कजाखस्तान और भारत के बीच सम्बन्ध: एक समग्र दृष्टिकोण, इस अध्याय में कजाखस्तान और भारत के बीच विद्यमान सम्बन्धों का समग्र विश्लेषण किया जाएगा | इसके अतिरिक्त विषयवस्तु और शोध संरचना पर प्रकाश डाला जाएगा |

अध्याय द्वितीय राजनीतिक संबंध, इस अध्याय में कजाखस्तान एवं भारत के राजनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा | इस अध्याय में कजाखस्तान एवं भारत के राजनीतिक संबंध कैसे हैं ? भारत के प्रति कजाखस्तान के राजनीतिक संबंध कितने उपयोगी हैं | इस पर विमर्श किया जाएगा |

अध्याय तृतीय आर्थिक संबंध, इस अध्याय में 1991 से वर्तमान तक के कजाखस्तान की भारत के प्रति आर्थिक नीतियों का वर्णन किया जाएगा | भारत और कजाखस्तान के बीच व्यापारिक सहयोग कितना महत्व रखता है आकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाएगा | भारत की कजाखस्तान के प्रति आर्थिक रूप से क्या प्रतिक्रिया है इस पर भी विमर्श किया जाएगा |

अध्याय चतुर्थ रक्षा सहयोग, इस अध्याय में यह चर्चा की जाएगी कि कजाखस्तान एवं भारत के बीच रक्षा संबन्धित नीतियों का कितना महत्व है और दोनों देशों की सरकारों द्वारा क्या-क्या नये कदम उठाए गये हैं |

पंचम अध्याय निष्कर्ष, इस अंतिम अध्याय में शोधार्थी द्वारा सम्पूर्ण शोध कार्य के निष्कर्षों पर चर्चा की जाएगी ।

अध्याय-2

राजनीतिक संबंध

कजाखस्तान और भारत के राजनीतिक संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में कजाखस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने के पश्चात् कजाखस्तान एक नए स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया, इसके पश्चात् कजाखस्तान अपनी राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार करने लगा एवं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कजाखस्तान ने राजनीतिक संबंधों का विस्तार किया जिसके फलस्वरूप कजाखस्तान ने भारत जैसे देशों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। कजाखस्तान की भू-रणनीतिक स्थिति एकमात्र ऐसी कुंजी है, जिसके कारण विभिन्न राष्ट्र (भारत, चीन, रूस इत्यादि) आकर्षित होते हैं। (Dave 2007: 248-255)

कजाखस्तान की भू-रणनीति स्थिति को परिलक्षित करते हुए भारत ने कजाखस्तान को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा। इसके फलस्वरूप भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कजाखस्तान को सर्वप्रथम स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, तथा इन देशों के राजनीतिक संबंधों की शुरुआत यहीं से होने लगी। 1991 के बाद कजाखस्तान और भारत के राजनीतिक संबंध विकसित होने लगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और कजाखस्तान राजनीतिक रूप से परस्पर सहयोगी हैं एवं कजाखस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण निरन्तर सकारात्मक रहा है। भारत द्वारा 1992 में कजाखस्तान दूतावास की स्थापना की गई थी, एवं कजाखस्तान ने 1993 में कजाक दूतावास की स्थापना भारत की राजधानी नई दिल्ली में की है। यह राजनीतिक संबंधों के विकास की नई शुरुआत थी। (Sharma 2009: 182-200)

1992 में राष्ट्रपति नज़रबाएव ने पहली बार भारत में विदेशी दौरा किया, जिन्होंने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात रखी। यह यात्रा निर्देशित करती है कि भारत कजाखस्तान के लिए राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। इसके उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1993 में कजाखस्तान की यात्रा किया और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने

के लिए कजाखस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर बल दिया | राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जून 2002 में कीका (C.I.C.A.) शिखर सम्मेलन में भाग लिया एवं कजाखस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की वार्ता की, और वैश्विक स्तर पर शांति एवं सद्भावना बनाए रखने की अपील किया | (Ibid)

कजाखस्तान और भारत के मध्य इस प्रकार की महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान की गयी विभिन्न प्रकार की घोषणाएं, दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने में सहयोगी है | इन यात्राओं के दौरान दोनों देशों के मध्य आर्थिक, व्यापारिक, विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों पर हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिनमें दोनों देशों की भागीदारी है, इसके अलावा विभिन्न ऐसे क्षेत्रों पर वार्ता हुई है, ये क्षेत्र कला, शिक्षा, विज्ञान, खेल, जनसम्पर्क का माध्यम, हवाई परिवहन इत्यादि है, इन सभी विषयों पर दोनों देशों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं | ऐसे दस्तावेज दोनों देशों की राजनीतिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने में सहयोगी है, जोकि दोनों देशों के लिए परस्पर सहयोगी है | (Ibid)

कजाखस्तान और भारत के मध्य राजनीतिक रूप से परस्पर सहयोगी संबंध है | कजाखस्तान ने भारत का बार-बार संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने के लिए समर्थन किया है | दोनों देशों की मुख्य आवश्यकताएं सुरक्षा बनाए रखना है | दोनों देशों द्वारा बहुपक्षीय संगठनों में परस्पर भागीदारी निभाई जा रही है, जैसे कीका (C.I.C.A.) और शंघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) है |

कीका (C.I.C.A)

कीका का प्रस्ताव कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव द्वारा 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रखा गया था | इस संगठन के मूल सिद्धांत सार्वभौम समानता, संप्रभुता में निहित

अधिकारों का सम्मान, सदस्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता है | कीका का प्रथम शिखर सम्मेलन जून 2002 में कजाखस्तान के अलमाती शहर में आयोजित किया गया था, इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, कंबोडिया, चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कोरिया गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उजबेकिस्तान, वियतनाम है | इस संगठन की स्थापना के पश्चात नौ और देशों ने सदस्यता ग्रहण की है, जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, कतर, श्रीलंका, यूक्रेन और अमेरिका और तीन अंतरराष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र, ओएससीई और अरब राज्यों का संघ) है |¹

इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य देशों की सार्वजनिक समस्याओं का निवारण किया जाएगा | भारत द्वारा कीका (C.I.C.A.) के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सदस्य देशों के साथ आपसी भाईचारा एवं सद्भावना बनाए रखने का प्रयास करेंगे एवं वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही साथ कजाक राष्ट्रपति द्वारा एशियाई देशों के साथ आपसी सहयोग बनाए रखने बनाए रखने की बात की गई |²

शंघाई सहयोग संगठन

¹ PM's Statement Prior to his departure for Kazakhstan to attend the CICA Summit 2 June 2002, Available at: <http://pibarchive.nic.in/archive/releases98/lyr2002/rjun2002/02062002/r020620021.html> Accessed on: 23 May 2018.

² Ibid

शंघाई सहयोग संगठन छह मध्य एशियाई देशों द्वारा गठित एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है । इस संगठन की स्थापना 1996 में की गई थी । शुरुआत में इसके सदस्य देश चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान थे एवं इसके पर्यवेक्षक देश भारत, ईरान, मंगोलिया, एवं पाकिस्तान था । इस संगठन का गठन शंघाई (चीन) में और चार सोवियत संघ गणराज्यों के (कजाखस्तान, किरगिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान) के सीमा विवादों को सुलझाने के लिये एक संधि के रूप में हुआ था । इस संगठन में उज्बेकिस्तान को 2001 में शामिल किया गया था । भारत को शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक देश के रूप में 2005 के शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कजाखस्तान ने की ।³

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सीमा पर अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओं की संख्या को कम करना, एक-दूसरे के विरुद्ध बल-प्रयोग से दूर रहना, तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले तत्वों (नस्लवादी और धार्मिक अलगाववादी सहित) के विरुद्ध लड़ने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है । इस संगठन के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें आतंकवाद तथा सुरक्षा की चुनौतियों के साथ आर्थिक सहयोग की गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया । वास्तव में शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् उत्तर शीत युद्ध काल में सुरक्षा व राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संगठन है । इसका कारण यह भी है कि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों शक्तियां चीन व रूस शामिल हैं। फिर भी वर्तमान में इस संगठन का मुख्य ध्यान आतंकवाद की समस्या को निवारण करना है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता व

³ Declaration on the establishment of the Shanghai Cooperation organization 2001. Available at: <http://eng.sectsc.org/documents/> Accessed on 25 May 2018.

अफगानिस्तान की समस्या के चलते या क्षेत्रीय आतंकवाद के खतरे के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है ।

आरंभ में शंघाई- पांच सामूहिक सीमा विवादों को सुलझाने पर केंद्रित रहा । शंघाई (1996) और मास्को (1997) में हुई संधियों के अंतर्गत सामूहिक सीमा पर सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और सैनिक गतिविधियां सीमित कर दिया गया अन्य सैनिक विश्वासोत्पादक उपायों पर भी सहमति हुई, जैसे- एक-दूसरे के विरुद्ध सैनिक अभ्यास करने पर रोक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक गतिविधियों (सैन्य अभ्यास और तैनाती सहित) के संबंध में आँकड़ों का वार्षिक आदान-प्रदान, आदि। लेकिन बाद में शंघाई-पाँच का लक्ष्य सीमा विवाद को सुलझाने से हटकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग हो गया था । 1998 में हुई अल्माटी बैठक में सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अवैध होकर लड़ने का निर्णय लिया। क्षेत्रों में पनप रहे धार्मिक अतिवाद पर चिंता व्यक्त की गयी। सदस्य देशों ने पारस्परिक निवेश, क्षेत्रीय व्यापार, परिवहन, पाइप लाइनों और पॉवर ग्रिडों के सामूहिक निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। (Roy 2014:42-52)

शंघाई सहयोग का चार्टर जून 2002 के सेण्ट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस संगठन के 6 सदस्य देशों का भू-क्षेत्रफल यूरेशिया के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत है। विश्व की कुल जनसंख्या में इसके सदस्यों की जनसंख्या 25 प्रतिशत है। अतः यह मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। शंघाई सहयोग संगठन में चार संगठनात्मक संस्थाएं हैं। प्रथम, सदस्य देशों के राष्ट्रध्यक्षों की परिषद्, जोकि इसकी सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। दूसरा, सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद् जो दूसरी शीर्ष संस्था है तथा सहयोग को कार्यक्रमों का निर्धारण करने के साथ-साथ संगठन का बजट भी पारित करती है। इन दोनों परिषदों के शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष संपन्न होते हैं। निष्कर्षतः इसके शीर्ष नेता वर्ष में दो बार अलग-अलग शिखर

सम्मेलनों में विचार-विमर्श करते हैं। तीसरी संस्था विदेश मंत्रियों की है, जिसके सम्मेलन आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। चौथी संस्था राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद् है, जिसमें सदस्य देशों के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य सहयोग के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सदस्य देशों के मध्य समन्वय स्थापित करना है।(Ibid)

शंघाई सहयोग संगठन द्वारा अन्य पड़ोसी देशों को भी इसकी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके लिए पांच देशों - अफगानिस्तान, भारत, ईरान, मंगोलिया तथा पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही तीन देशों - बेलारूस, श्रीलंका तथा तुर्की को वार्ताकार भागीदार देश का दर्जा प्रदान किया गया है। ये दोनों श्रेणी के देश भी इसके सम्मेलनों व बैठकों में भाग लेते हैं। आरम्भ में शंघाई सहयोग संगठन का ध्यान मुख्यतः सुरक्षा संबंधी मुद्दों तक ही सीमित था। सुरक्षा में भी यह आतंकवादरोधी गतिविधियों पर केंद्रित था। जून 2004 में ताशकंद में हुए सम्मेलन में एक क्षेत्रीय आतंकवादरोधी ढांचे (रीजनल एंटी टेरोरिज्म स्ट्रक्चर) की स्थापना का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में इस संगठन में यह ढांचा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक शीर्ष व्यवस्था है। अप्रैल 2006 में इस क्षेत्र में दवाओं के अवैध व्यापार से संबंधित अपराधों से निबटने के लिए एक कार्यवाही योजना की घोषणा की गई। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की तैयार हेतु सदस्य देशों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यासों की भी व्यवस्था की गई है। अब तक इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास 2003, 2005, 2007, 2009 व 2011 में आयोजित किए जा चुके हैं। (Ibid)

सितंबर, 2003 में सम्पन्न हुए सम्मेलन में पहली बार आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के मध्य एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब से यह संगठन सुरक्षा संबंधी मुद्दों के साथ-साथ आर्थिक सहयोग की दिशा में भी कार्य कर रहा है। इसी सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ द्वारा सदस्यों के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना

का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन अन्य सदस्य इस बात से आशंकित है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना से व्यापार में चीन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इसलिए मुक्त व्यापार क्षेत्र की दिशा में अभी तक प्रगति नहीं हो पाई है। आर्थिक सहयोग के उक्त प्रयासों के बावजूद शंघाई सहयोग संगठन अब भी मुख्य रूप से सुरक्षा तथा आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। (Fredholm 2013:1-17)

भारत को 2005 में शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त हो गया था। तभी से भारत शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग ले रहा है। यद्यपि इसके सम्मेलनों में भारत की भागीदारी विदेश मंत्री के स्तर की रही हैं, लेकिन 2009 में संपन्न हुए यैकैटरिनबर्ग शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त भारत के गृहमंत्री, परिवहन मंत्री, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री, व्यापार मंत्री आदि भी इसके सम्मेलनों व विचार-विमर्श में भाग लेते रहे हैं। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले गठित व्यापार मंच तथा ऊर्जा क्लब आदि की गतिविधियों में भी रुचि दिखाई है। फिर भी आरंभिक दौर में भारत की रुचि इसकी आतंकवादरोधी गतिविधियों में ही मुख्यतः केंद्रित रही है। (Singh 2012:1-2)

शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया का क्षेत्रीय सहयोग व सुरक्षा संगठन है। भारत इस क्षेत्र के पांच देशों- कजाखस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंधों को विकसित करने का पक्षधर है। भारत ने विगत 20 वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयास भी किए हैं। लेकिन 2017 में भारत अब पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन का नियमित सदस्य देश है। (Roy,2014:52)

आतंकवाद

आतंकवाद का भय आज के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है | विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कजाखस्तान और भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का विरोध निरन्तर किया है | मध्य एशियाई क्षेत्र में तालिबान जैसे आतंकी संगठन का भय बना हुआ है | मध्य एशियाई क्षेत्र में अफगानिस्तान द्वारा आतंकवाद के फैले जाने कि वजह से कजाखस्तान के व्यापारिक मार्गों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है | कजाखस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगी हुई हैं | अफगानिस्तान अपने व्यापार बढ़ाने के लिए कजाखस्तान के मार्गों द्वारा मध्य एशियाई देशों से संपर्क स्थापित करना चाहता है, किन्तु आतंकवाद से प्रवाहित होने के कारण व्यापार नहीं हो पा रहा है | (Primbetov and Mukashev, 2016:1-5)

वर्ष 2002 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कजाखस्तान की यात्रा की | इस यात्रा का मुख्य ध्येय ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) स्थापित करना था | जिसमें दोनों देशों की सामरिक भागीदारी के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए नए कदम उठाने की पहल की गई | उन्होंने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए गुजारिश की है | इस प्रकार से (JWG) ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से दोनों देश सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, इसके उपरांत 2006 में कीका शिखर सम्मेलन में कीका के सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होने की बात सामने रखी और ये देश आतंकवाद से निपटने के लिए अलग-अलग रूप में काम करने लगे | आतंकवाद से निपटने के लिए कजाखस्तान और भारत इन दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने के पक्ष में साँझा सैन्य अभ्यास भी किए हैं, सैन्य और राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और कजाखस्तान की सेनाएँ संयुक्त रूप से प्रबल दोस्तकी अभ्यास कर चुकी है | जिससे भारत और कजाखस्तान के बीच मनोबल बढ़ा है | Sharma 2010: 25-33)

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्ताना में आयोजित जून 2017 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखस्तान में शंघाई सहयोग सम्मेलन (SCO) को संबोधित करते हुए सभी देशों के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक बताते हुए भारत को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिलने पर सभी देशों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि "आतंक मानव मूल्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आतंकवाद की लड़ाई में सभी देशों का सहयोग जरूरी है। आतंकवाद की फंडिंग बंद होनी चाहिए, एवं शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सहयोग भारत के लिए प्राथमिकता है, देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता महत्वपूर्ण कारक होने चाहिए"। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी भारत को बधाई देते हुए कहा कि इससे शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। शंघाई सहयोग सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ काम करेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति की विरासत छोड़नी चाहिए, ना कि विरोधाभास और संघर्ष की"। कजाखस्तान और भारत दोनों देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है, क्योंकि अफगानिस्तान के द्वारा दोनों देशों को लाभ होने की संभावना है, जिससे कि कजाखस्तान को भी व्यापारिक मार्गों में होने वाली समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। (PTI 2017)

अंतर्राष्ट्रीय नीति

कजाखस्तान वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार देश के रूप में देखा गया है। कजाखस्तान की विश्वनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह राष्ट्र वैश्विक समुदाय के राजनीतिक हितों को महत्व देता रहा है। कजाखस्तान ने भारत जैसे प्रत्येक देश का विकास करने में सहयोग किया है। वैश्विक घटनाक्रमों के अनुसार जहां अस्पष्टता के साथ जुड़ी घातक त्रुटियों और डबल मानकों ने वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया को गंभीर संकट में डाल दिया है। गैर-प्रसार व्यवस्था एक "पेंडोरा का बॉक्स" की भांति खोला गया

है, लेकिन यह गेम खेला जा रहा है | एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इस महत्वपूर्ण स्थिति को दूर करने के लिए सही समाधान खोजने के लिए मूलभूत संधियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गैर-प्रसार के क्षेत्र को अनिवार्य कर दिया है | इसके लिए सितंबर 2006 में संमितातिस्क संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मध्य एशिया को एक परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बना दिया गया जोकि यह अनुकरणीय कार्यवाही थी। विश्व के प्रथम देश के रूप में कजाखस्तान उभर के सामने आया जिसने परमाणु परीक्षण साइट को बंद कर दिया था, और सामूहिक विनाश के हथियारों के अप्रसार पर निरंतर स्थिति रखने में अपनी भागीदारी निभाई है |⁴

निःशस्त्रीकरण और गैर-प्रसार के क्षेत्र में कजाखस्तान द्वारा नीति बनाई गई इस नीति को विदेश नीति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समग्र विकास एवं सुरक्षा प्रदान करना है, एवं वैश्विक स्तर पर पाई गई समस्याओं का समाधान करना है |

कजाखस्तान अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों को ठोस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कूटनीतिक वार्तालाप कर चुका है | इस वार्तालाप में यह संभावना भी प्रकट कर चुका है, कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेगा एवं क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेगा | कजाखस्तान निरंतर सहिष्णुता और सामंजस्य को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है | कजाखस्तान में निवास करने वाली सभी जातियों, संस्कृतियों और धर्मों को विशाल यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहेगा | विशाल

⁴CTBTO 2007, Kazakhstan Ratifies Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty, Available at:<https://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2002/kazakhstan-ratifies-comprehensive-nuclear-test-ban-treaty/> Accessed on 29 May 2018.

यूरेशियन क्षेत्र में पिछले 15 सालों में विदेश नीति में रचनात्मक कार्य हुआ है | कजाखस्तान ने यूरेशिया के अंतर्गत एकीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाता आया है | जोकि एक रणनीतिक विकल्प है, जो व्यावहारिकता और राष्ट्रीय रुचि के रूप में देखा जा सकता है | ⁵

यूरेशियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी

यूरेशियन एकीकरण यह अंतरराज्यीय संगठन की व्यवस्था है | यह सोवियत क्षेत्र की यूरेशियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो तेज गति से पिछले पंद्रह वर्षों से कार्य कर रहा है जिसमें कजाखस्तान को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि कजाखस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति बेहतर है | एकीकरण के लिए स्वतंत्र देशों का समूह मिलकर एक राष्ट्रमंडल की स्थापना करते हैं तथा राष्ट्रमंडल देश निर्णय लेने का कार्य करते हैं, इनके द्वारा विकास में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने के निर्णय लिए जाते हैं और विकास की गति को तेज करते हैं, जो सभी राष्ट्रों को एकीकरण का मंच स्थापित करता है सीआईएस (C.I.S.) समूह आर्थिक और व्यावहारिक रूप से लंबे समय से कार्य करता आया है | सीआईएस (C.I.S.) देशों की अध्यक्षता करते हुए कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव ने कहा कि “हमें सीआईएस (C.I.S.) देशों से संबन्धित मुद्दों को हल करने के लिए नए कार्यक्रम चलाने होंगे एवं राष्ट्रों के विकास को प्रगतिशील बनाना होगा |” (Nazarbaev,2006)

इन वर्षों में कजाखस्तान मध्य एशियाई देशों के एकीकरण के लिए मजबूती से खड़ा हुआ है | इस के साथ यूनियन ऑफ सेंट्रल स्टेट्स को भी अपने साथ लाकर समर्थन लिया है | आज के परिप्रेक्ष्य में कजाखस्तान आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं में भूमिका अदा कर रहा है जो सभी सीआईएस (C.I.S.) देशों के विकास में सहायक है | मध्य एशियाई देशों में बाजार का

⁵ Ibid

एकीकरण की स्थापना करने में सहयोग देता रहा है | कजाखस्तान ने मुख्य रूप से सीमा क्षेत्र का विस्तार व्यापार के लिए किया है, जिससे कि संयुक्त रूप से निवेश किया जा सकता हो इसके विस्तार का एक और उद्देश्य यह था, कि कजाखस्तान के पास ऊर्जा के स्रोत होने का लाभ सभी देशों को मिल पाये | मूलरूप से कजाखस्तान की विदेश नीति का विस्तार विभिन्न दिशाओं में, आर्थिक नीति का विस्तार करना है जो कजाखस्तान की विभिन्न कूटनीतिक उपलब्धियों को दर्शाती है | कजाखस्तान का एकीकरण करने के पीछे कई कारण भी हैं | जिसमें कजाखस्तान यह नहीं करना चाहता कि इसकी विदेश नीति एक तरफा हो, यह सभी देशों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता है यह वैश्विक स्तर पर कजाखस्तान मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, रूस जैसे देशों से संपर्क स्थापित करना चाहता है और भारत को भी इन क्षेत्रों में प्राथमिकता देता है | (Ibid)

मुख्य रूप से कजाखस्तान के संबंधों को रूस के साथ मिलकर देखा जाए तो अस्ताना और क्रेमलिन ने मिलकर एक बड़ी बिजली परियोजना पर कार्य किया है | हालांकि कजाखस्तान स्वयं पर निर्भर नहीं है यह पड़ोसी देशों के साथ तेल परिवहन परियोजना में शामिल हुआ है | अमेरिका द्वारा स्थापित “बाकू-त्बलीसी-सेहान” पाइपलाइन अभी भी तेल परिवहन का कार्य सहयोगी रूप से कर रही है | कजाखस्तान में अतिरिक्त उदाहरण को देखे तो रूस के साथ कजाखस्तान ने अन्तरिक्ष परियोजनाओं पर कार्य किया है | रूस ने कजाखस्तान का साथ आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सहयोग दिया है | जून 2006 में कजाखस्तान ने अपनी प्रथम व्यावसायिक उपग्रह “काज़सैट एल” का शुभारंभ किया जोकि रूसी निर्मित “बूस्टर रॉकेट पर बैयकॉनुर कॉस्मोड्रोम” के समान है | यह कजाखस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दर्शाती है | आज भी कजाखस्तान के संबंध अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हुये हैं | कजाखस्तान अमेरिका के साथ आतंकवाद के विरोध में हमेशा समर्थन करता रहा है | जबकि

उज़बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने अमेरिकी ठिकानों के लिए अपने क्षेत्र देने से इनकार कर दिया है | (Ashgar Interview 2006)

विदेश नीति

कजाखस्तान द्वारा सीआईएस (C.I.S.) देशों में देखा जाने वाला संघर्ष “ मल्टी वेक्टर” विदेश नीति को जन्म देता है | कजाखस्तान ही एक मात्र ऐसा देश जो सीआईएस (C.I.S.) देशों में तीव्रगति से आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है | कजाखस्तान ने आर्थिक विकास के लिए “मल्टी वेक्टर” विदेश नीति को अपनाने पर बल दिया है | (Umarov 2005)

इस नीति के तहत कजाखस्तान अपने सीमांतर देशों के साथ स्थिरता रखते हुये अन्य राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता है, अन्य देशों में लगभग 120 देश है, जिनमें से लगभग 67 देश विभिन्न संगठनों में सम्मिलित है | संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोप का सुरक्षा सहयोगी संगठन, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप परिषद, इस्लामी सम्मेलन संगठन, नाटों, आर्थिक सहयोगी संगठन, एससीओ जैसे संगठनों के साथ ही साथ रूस, चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान इत्यादि देश भी आते है | इन सभी देशों के साथ कजाखस्तान वाणिज्य रूप से एक सीमा शुल्क के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना चाहता है, इन तथ्यों के अनुसार यह कह सकते है, कि कजाखस्तान की विदेश नीति वैश्विक स्तर पर शांति सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है | कजाखस्तान सभी देशो के साथ संतुलन बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना चाहता है | (Ibid)

कजाखस्तान की “मल्टी वेक्टर” विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को संतुलन बनाए रखना है, ताकि कजाखस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रूस और चीन जैसे देशों के साथ लगी हुई सीमा के कारण सुरक्षित रहा जा सकता हो |

कजाखस्तान के लिए राजनीतिक संबंधों का मुख्य कारण यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास नाटो जैसे महत्वपूर्ण संगठन होने के कारण “मल्टी वेक्टर” नीति का विस्तार जरूरी है । यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कि कजाखस्तान चीन और रूस का विरोध कर के अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बना सकता है । कजाखस्तान द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुये सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर “मल्टी वेक्टर” नीति के तहत अपने राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को और अधिक बेहतर बना सकता है, जो वैश्विक स्तर पर भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है । भारत के साथ भी कजाखस्तान “मल्टी वेक्टर विदेश” नीति के तहत संबंधों को संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोग देता रहा है । भारत की “कनैक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” भी इसी तरह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए बनाई है, जो पारस्परिक लाभदायक है । (Hanks 2009:257-267)

मध्य एशिया और भारत के संबंधों को और अधिक गहराई से देखें तो 2012 में “कनैक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” की शुरुआत की, इस के तहत मोदी सरकार के शासनकाल में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति ने मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत से जोड़ने का निश्चय किया है । इस नीति को लागू करने के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है, कि राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाना है तथा एक दूसरे देश की सुरक्षा को बनाए रखना है, मध्य एशियाई क्षेत्र को भारत के साथ जोड़ने वाले मुख्य देश कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उजबेकिस्तान हैं । 1991 में सोवियत विघटन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे । ये देश जब सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे तभी से भारत के संबंध इन देशों से अच्छे रहे हैं । मित्रता के संबंध आज तक बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने इस नीति की शुरुआत की है । भारत का मध्य एशिया के साथ इस तरह की नीति

को कूटनीतिक रूप से देखा जाए तो यह भारत के राष्ट्रीय हितों को किसी न किसी रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकती है ।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् ऐसा लगता था कि भारत के संबंध भी इस क्षेत्र में खत्म हो जाएंगे परंतु इस नीति ने फिर से मध्य एशिया क्षेत्र को भारत के निकट ला दिया है, इस प्रकार यह “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” काफी तेजी से कार्य कर रही है । कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत भारत अपने सम्मुख उभरती हुई चीन की अर्थव्यवस्था का सामना कर सकता है । चीन भारत के सामने विरोध प्रकट करता रहा है, इसे रोकने के लिए भी “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” लागू होती है । पिछले कई दशकों से मध्य एशिया क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुये ऊर्जा संसाधन बहुतायत में पाये जाने के कारण भारत इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है । (Diwivedi 2006:140-150)

भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” की महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे पूरा विश्व परिचित हो चुका है । भारत का पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों में खटास आ जाने के कारण एक दूसरे राष्ट्र के प्रति राजनीतिक संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं । भारत के अतिरिक्त मामलों के मंत्री ई. अहमद द्वारा पहली बैठक में जून 2012 में “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” की नींव रखी गई, जिसमें सभी मध्य एशियाई देशों ने भाग लिया गया, जिसके तहत बारह सूत्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने का फैसला किया है । कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत बारह सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित हैं जो एक दूसरे को कैसे पूरा करेंगे । (Jha 2016 2-5)

भारत उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से अपने राजनीतिक संबंधों का निर्माण जारी रखेगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों दोनों देशों के नेता एक साथ मिलकर बातचीत

करना जारी रखेंगे। भारत अपने सामरिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। भारत का पहले से ही कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ सामरिक भागीदारी रही है। जैसे कि सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान, आतंकवाद का सामना, समन्वय और अफगानिस्तान पर करीबी से विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत, मध्य एशियाई भागीदारों के साथ बहुपक्षीय भागीदारी बढ़ाएगा, जो शंघाई सहयोग संगठन, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) और कस्टम यूनियन जैसे मौजूदा मंचों के माध्यम से संयुक्त प्रयासों के तालमेल का उपयोग करेगा ।, भारत ने पहले ही एकीकृत यूरेशियन अंतरिक्ष के साथ अपने बाजार को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का प्रस्ताव किया है। (Brunet, Anitipov and Lobkovsky 1999: 88-105)

भारत ऊर्जा, और प्राकृतिक संसाधनों में दीर्घकालिक साझेदार के रूप में मध्य एशिया को देखता है। मध्य एशिया के बड़े भूमि कृषि योग्य इलाकों को यह संभावित रूप में देखता है भारत मूल्य संवर्धन के साथ लाभदायक फसलों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए रहेगा |, चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सहयोग के लिए बड़ी क्षमता प्रदान करता है। मध्य एशिया में सिविल अस्पताल / क्लीनिक स्थापित करके भारत सहयोग के लिए तैयार है, पश्चिमी विश्वविद्यालयों द्वारा शुल्क लगाए गए शुल्क के एक अंश पर भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली बचाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत बिश्केक में एक केंद्रीय एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता करना चाहता है जो सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, दर्शन और भाषाओं जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन सकता है।

भारत ने मध्य एशिया के साथ अपना ई-नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक केंद्र को स्थापित किया है जिससे कि दूर-शिक्षा और टेली-औषध कनेक्टिविटी स्थापित हो सकें और सभी पांच मध्य एशियाई राज्यों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है।, भारतीय अपनी कंपनियों का निर्माण

करके मध्य एशियाई क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है और प्रतिस्पर्धी दरों पर विश्व स्तर की संरचनाओं का निर्माण कर सकता है। मध्य एशियाई देशों में, विशेष रूप से कजाखस्तान में लौह अयस्क और कोयले के लगभग असीमित भंडार होने के कारण प्रचुर मात्रा में सस्ते दामों पर बिजली प्राप्त कर सके | भारत कई मध्यम आकार की स्टील रोलिंग मिलों को सेट करने में मदद कर सकता है, जिससे कि विशिष्ट उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है |, भूमि कनेक्टिविटी के लिए भारत ने इंडिया इंटरनेशनल उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (I.N.S.T.C.) के रूप में पुनः सक्रिय हो गया है। भारत और मध्य एशियाई देशों को जल्द से जल्द कॉरिडोर में लापता लिंक को पाटने के लिए और अन्य मार्ग के साथ जोड़ने पर काम करने के हमारे प्रयासों में शामिल होने की जरूरत है, इस क्षेत्र में व्यवहार्य बैंकिंग ढांचे की अनुपस्थिति होने के कारण व्यापार और निवेश के लिए एक बड़ी बाधा है। (Ibid)

भारत 2011 कई देशों में 21 अरब अमरीकी डालर होने का अनुमान आउटबाउंड यात्रियों के लिए सबसे बड़े बाजारों में एक है भारत में पर्यटन कार्यालय खोले गए हैं भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए मध्य एशियाई देशों में पर्यटकों के लिए छुट्टियों के अवसरों के रूप में उभर सकता है और यहाँ तक कि भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भी जो अपनी फिल्मों में विदेशी हिंदी संगीत को चित्रित करना पसंद कर रहे हैं, हमारे लोगों के बीच कनेक्शन गहरी मित्रता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं । मैं विशेष रूप से युवाओं और भारत और मध्य एशिया के भविष्य के नेताओं के बीच आदान-प्रदान पर जोर देना चाहता हूँ। भारत में छात्रों का एक मजबूत आदान-प्रदान पहले से ही है। भारत एक दूसरे की संस्कृतियों में गहरी अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए विद्वानों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और युवा प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पाँच मध्य एशियाई देशों की यात्रा के दौरान आतंकवाद और कट्टरपंथी उग्रवादी हवाओं के बहने वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए

अपील प्रस्तुत की, इस क्षेत्र में इन सभी से निपटने के लिए भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करने के लिए आवश्यकता समझा है | उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के समय से ही भारतीय सांस्कृतिक उत्पादों में बेहद लोकप्रिय हैं। इस क्षेत्र के लोग वहां हिंदी संगीत सुनते हैं और बॉलीवुड से भारतीय सिनेमा देखते हैं। भारत को इसके पक्ष में फायदा उठाने की जरूरत है | भारत क्षेत्रीय देशों में अपने प्रभाव को और अधिक प्रभावी ढंग से किसी अन्य माध्यम से बढ़ा सकता है। “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” एक समग्र नीति है | जो न केवल ऊर्जा, तेल और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ही नहीं है बल्कि राजनीति, संस्कृति और रक्षा सहित हर क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में है। (Jha 2016: 1-3)

ब्रिटिश शासनकाल में सूरज सूर्यास्त कभी नहीं होता था, अंग्रेजों की इस विचित्र प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण था व्यापारिक मार्गों की शोध करने की क्षमता | अब 21 वीं सदी में चीन भी अंग्रेजों के कदमों पर चल रहा है गौर करने वाली बात है कि चीन “अपने वन बेल्ट वन रोड” के जरिये सम्पूर्ण विश्व को कब्जा में करना चाहता है | चीन ने भारत को इस पहल में शामिल करने के लिए बार बार उकसा रहा है, परंतु भारत ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया है | और अमेरिका भी इसके प्रति चिंता जताने लगा है |

वन रोड वन बेल्ट की शुरुआत सितंबर 2013 में की गई, इसके तहत रेशम सड़क आर्थिक पट्टी एवं 12 वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था | संसार की 55 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद, 70 प्रतिशत आबादी एवं 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा संसाधनों को समेटने की यह योजना चीन द्वारा भूमि एवं समुद्र परिवहन का रास्ता बनाने का कार्यक्रम है, जिससे चीन अपने बाजार को संसार भर में विस्तारित कर सकें | इससे चीन की अर्थव्यवस्था - श्रमशक्ति, बुनियादी ढांचा एवं तकनीकी भंडारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सकें | भारत को इससे खतरा होने की संभावना है यदि चीन का यह

वन रोड वन बेल्ट का कार्य सफल हुआ तो चीन सम्पूर्ण एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा और जिससे भारत की महत्त्वकांक्षाओं को धक्का लग सकता है | लेकिन चीन यह चाहता है कि भारत भी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने परंतु भारत इसका विरोध कर रहा है इसकी यह वजह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन - पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर (C.P.E.C.) भी ओबीओआर का हिस्सा है | भारत की नज़र में यह कॉरीडोर इसकी संप्रभुता को चुनौती प्रकट करता है | इससे एक और खतरा नज़र आता है कि यह मार्ग मध्य एशिया के संबंधों को भी बाधित करता है | ⁶

कजाखस्तान की विदेश नीति की दिशा कजाखस्तान और भारत के संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है | जब से कजाखस्तान की विदेश नीति की शुरुआत हुई है, उस समय से ही कजाखस्तान भारत के प्रति मानव महत्त्व के लिए भारतीय समाज के लिए कल्याणकारी नीतियों को अपनाता रहा है | चाहे वैज्ञानिक-तकनीकी भंडार हो या लोकतांत्रिक में सफलता के लिए समाज का निर्माण करना हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कजाखस्तान ने भारत को हमेशा प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा है | कजाखस्तान ने भारत के साथ सैन्य अभ्यास करके यह साबित कर दिया है कि दोनों देश अपनी राजनीतिक और आर्थिक भूमिका में वृद्धि करने के लिए परस्पर सहयोगी है | कजाखस्तान यहा तक ही सीमित नहीं है बल्कि केवल दक्षिण एशिया के लिए भी अपनी विदेश नीति को सीमित रखता है कजाखस्तान सम्पूर्ण विश्व के साथ भी इस तरह का व्यवहार रखता है |

भारत भी कजाखस्तान के लिए एक विशेष स्थान रखता है भारत कजाखस्तान की भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुये कजाखस्तान के साथ संबंधों को अनुकूल बनाए रखता है, जिससे मध्य

⁶ Policy brief, "China Pakistan Economic Corridor, A Chinese Dream Being Materialized through Pakistan Available at [https://sdpi.org/publications/files/China-Pakistan-Economic-Corridor-\(Shakeel-Ahmad-Ramay\).pdf](https://sdpi.org/publications/files/China-Pakistan-Economic-Corridor-(Shakeel-Ahmad-Ramay).pdf) Accessed 4 June 2018.

एशिया क्षेत्र और दुनिया में अपना कद ऊँचा रख सकें | भारत भी अपने राजनीतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए निवेश और बाज़ार को आकृष्ट करता रहा है, जिससे एक व्यापार मण्डल स्थापित हो सकें और अपने राजनीति हितों की पूर्ति हो सकें | (Rudenka 2006:12)

कजाखस्तान और भारत के ऐतिहासिक संबंधों का अवलोकन करें तो, 23 फरवरी 1992 को कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएब द्वारा अधिकारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजनयिक संबंध स्थापित करना था | कजाखस्तान की आजादी के तुरंत बाद की यात्रा ने भारत के महत्त्व को बल दिया था, कजाखस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा ने अपनी विदेश नीति का विकास करने के लिए भारत को प्राथमिकता दी थी | कजाखस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कजाखस्तान और भारत ने मूल दस्तावेज़ पर म्युचुअल रिलेशंस के सिद्धांतों के बारे में घोषणा और विभिन्न विषय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, व्यापार और आर्थिक संबंधों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कला के क्षेत्र में, शिक्षा, जन मीडिया आदि पर चर्चा की थी |

कजाखस्तान ने भारत के साथ अन्य प्रमुख पहलुओं का भी समर्थन किया है | अस्ताना में विश्व और पारंपरिक धर्म के नेताओं का सम्मान किया है | सितंबर 2006 को आयोजित धर्मविज्ञानवादी शांतिलाल ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उनके द्वारा कजाखस्तान के संबंधों में भारत के साथ नीति पूर्वक कार्य किया गया |

अध्याय-3

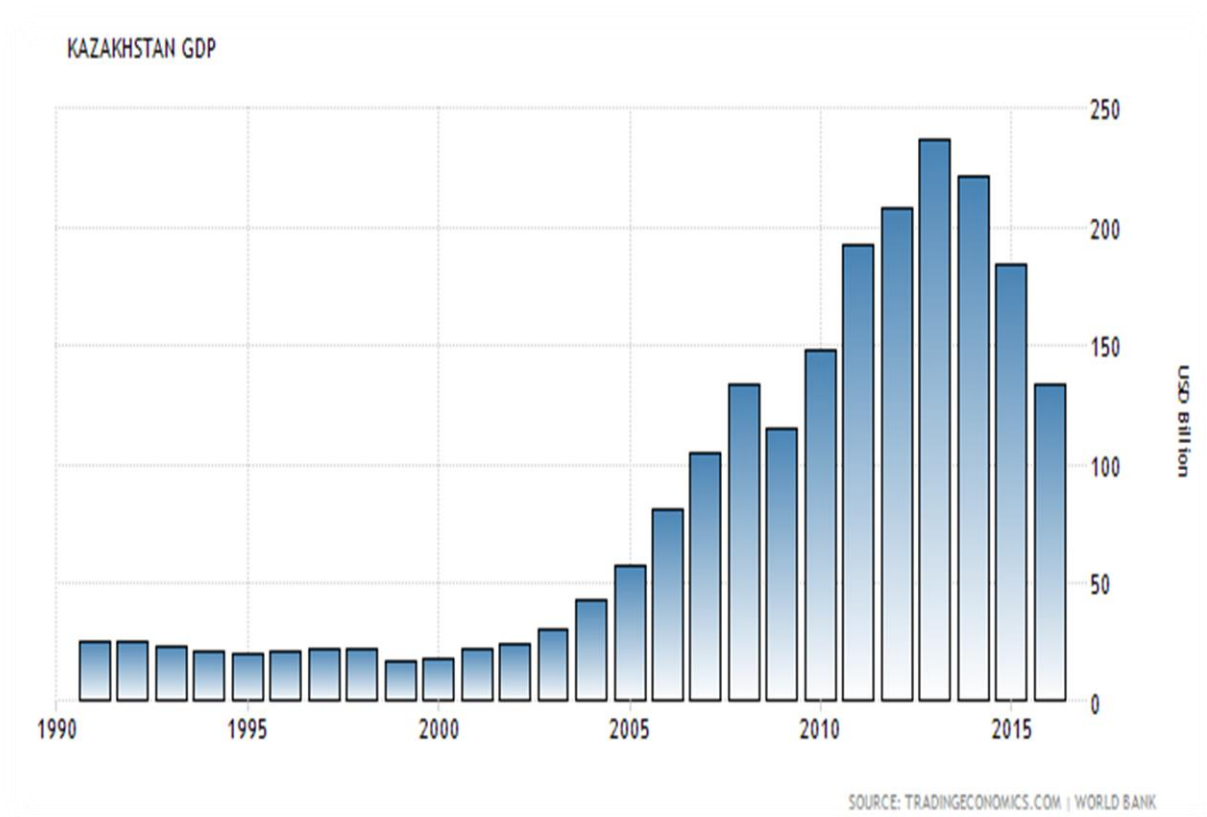
आर्थिक संबंध

कजाखस्तान और भारत के विकास में आर्थिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण योगदान है | कजाखस्तान की विदेश नीति में भारत (तकनीकी, आर्थिक और सैन्य शक्ति से संपन्न) को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है | उर्जा संसाधनों से युक्त और अपनी महत्वपूर्ण भू-सामरिक स्थिति के कारण कजाखस्तान भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है | इन सभी कारणों से दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं | 1991 से कजाखस्तान के एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से इन दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि (2017 तक) हुई है |

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति की वजह से कजाखस्तान भारत सहित अन्य विश्व शक्तियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है | कजाखस्तान के खनिज संसाधनों (विशेषकर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और युरेनियम के भण्डार) के क्षेत्र में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं | सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ गई, क्योंकि यहाँ तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले कुशल विशेषज्ञ रुसी थे | अतः सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात् वे रूस चले गए इसी के साथ यहाँ पूंजी की कमी का भी संकट उत्पन्न हुआ | इन्हीं कारणों से कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी दयनीय हो गयी | सन् 2004 में कजाखस्तान की वृद्धि दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष था, जबकि सोवियत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसकी वृद्धि दर 60 फीसदी प्रति वर्ष थी | अतः कजाखस्तान को अपनी कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नये कदम उठाने पड़े | (Patnaik 2004: 430-433)

पिछले दस वर्षों के आकड़ों (1995-2005) के अनुसार कजाखस्तान में कुल 40 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ | इस निवेश के अंतर्गत बैंकिंग और बीमा क्षेत्र भी सम्मिलित थे |

(Laumulin 2005: 25-50) कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था में कई उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं | कजाखस्तान की सकल घरेलू उत्पाद का यदि आकलन नीचे दिये गए डायग्राम के अनुसार किया जाए तो यह स्पष्ट है, कि कजाखस्तान की जीडीपी किस तरह से आरोही क्रम से अवरोही क्रम में है |



Kazakhstan's Gross Domestic Product

Source:-<https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp>

यह डायग्राम दर्शाता है कि कजाखस्तान का सकल घरेलू उत्पाद 1991 से 2017 के मध्य किस प्रकार से अपनी आर्थिक गति में वृद्धि करता रहा | 1991 से 1995 के बीच इसकी अर्थव्यवस्था 50 बिलियन डॉलर से भी निम्न रही है | इसके पश्चात वर्ष 2000 से कजाखस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हुई है, 2013 में कजाखस्तान का सकल

घरेलू उत्पाद लगभग 225 बिलियन डॉलर को पार करता हुआ नजर आता है | इसके पश्चात् 2013 में कजाखस्तान की सकल घरेलू उत्पाद लगातार निम्न स्थिति में दिखता है | इस डायग्राम के अनुसार 2017 में कजाखस्तान का सकल घरेलू उत्पाद 150 बिलियन डॉलर से भी कम है | इससे स्पष्ट होता है कि कजाखस्तान की आर्थिक वृद्धि में निरंतर कमी आ रही है | कजाखस्तान को अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में रखने के लिए, यहाँ विदेशी निवेश की आवश्यकता है | यदि हम वर्तमान कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था को देखें तो यह 1990 की तुलना में कई गुणा आगे निकल गया है | कजाखस्तान के पास प्रचुर मात्रा में कच्चे माल के भंडार है तथा यहाँ की भूमि कृषि योग्य है और आईटी के क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ विद्यमान हैं | कजाखस्तान अपने यूरेनियम के भंडार को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा संभावना के रूप में देखता है |¹

यदि हम 1990 के आकड़ों का आकलन करें तो हम पाते हैं कि विश्व आर्थिक मंच पर कजाखस्तान 109वें स्थान पर था, परंतु 2006 - 2007 में कजाखस्तान 56वें स्थान पर था | वहीं कजाखस्तान के पड़ोसी देश रूस और सीआईएस (C.I.S.) देशों का स्थान इससे निम्न था | कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव के अनुसार कजाखस्तान अब हम विश्व के मुख्य 50 देशों की स्पर्धा की श्रृंखला में होगा और हम अपने आप को विकसित रूप में पायेंगे² |

कजाखस्तान में धातु एवं अन्य वस्तुओं का निर्माण

कजाखस्तान में औद्योगिक उत्पादन में गैर-लौह धातुओं का योगदान 12 प्रतिशत से अधिक का है, जिनमें तांबा, सीसा, जस्ता, टाइटेन, मैग्नीशियम, जैसे दुर्लभ धातु सम्मिलित हैं | ये धातु उद्योग कजाखस्तान की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं | विश्व में तांबे

¹ "Trading Economics", Available at : <https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp> Accessed on 20 March 2018

² Ibid

के उत्पादन में कजाखस्तान का हिस्सा 5.3 प्रतिशत है, जिसका निर्यात इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्रों में किया जाता है | कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था में स्वर्ण उद्योग की भी अहम् भूमिका है तथा इसके उत्पादन में प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हो रही है | (Khazhmuratova 2010: 85-94)

लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में कजाखस्तान का विश्व में आठवाँ स्थान है | विश्व में भंडारित लौह अयस्क का 6 प्रतिशत भाग कजाखस्तान में विद्यमान है | कजाखस्तान में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह-अयस्क पाया जाता है | कजाखस्तान द्वारा अपने उत्पादन का 70 प्रतिशत लौह अयस्क विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है | कजाखस्तान अपने लौह निर्यात में प्रतिवर्ष वृद्धि करता जा रहा है | 1999 में कजाखस्तान का कुल निर्यात में क्रोमियम और मेंगनीज़ का योगदान 4 प्रतिशत था | कजाखस्तान अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लौह प्लेट और पाइप आदि का निर्यात पूर्व सोवियत गणराज्यों में भी करता है | (Ibid 2010: 85-94)

तेल शोधन और एवं पेट्रो रसायन उद्योग :

तेलशोधन के लिए यहाँ पर विभिन्न रिफ़ाइनिंग कारखानों को स्थापित किया गया है, इनके द्वारा विभिन्न पेट्रो पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जैसे डीजल, बॉयलर ईंधन, विमानन ईंधन, पेट्रोवित्यूमंस और अन्य खनिज तेल पदार्थों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है | इसके अतिरिक्त यहाँ पेट्रो रसायन पर आधारित कई उद्योग-धन्धे पाए जाते हैं, जिनमें प्लास्टिक, रासायनिक फाइबर, तार, ऑटोमोबाइल तेल (मोबिल) और रबर उत्पाद (ट्रक इत्यादि के पहिये के लिए), क्रोमियम, कार्बाइड कैल्शियम आदि का उत्पादन किया जाता है | (Yenikeeff 2008: 25)

रसायनों पर आधारित उद्योग:

कजाखस्तान के द्वारा भारी मात्रा में कॉम्प्लेक्स फॉस्फोरिक अयस्क प्रसंस्करण किया जाता है | जो कृषि-क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है (C.I.S. देशों के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स फॉस्फोरिक अयस्क के उत्पादन में कजाखस्तान का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत है) | इसके अलावा खनिज उर्वरक जैसे सिंथेटिक वॉशिंग-अप आदि का उत्पादन भी कजाखस्तान के द्वारा किया जाता है (Ibid 2008: 25-30) |

उपकरण निर्माण प्रणाली :

कजाखस्तान में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण भी किया जाता है | कजाखस्तान के औद्योगिक उत्पादन में मशीन निर्माण उद्योगों का स्थान 8 प्रतिशत है | कजाखस्तान में फोर्जप्रेस उपकरण (शाइमकंट), धातु काटने मशीन टूल्स (अल्माटी), जमाकर्ताओं (टैल्ड-कोरगन), केन्द्रापसारक पंप (अस्ताना), एक्स-रे उपकरण (एल्टकोब) इत्यादि का निर्माण किया जाता है | इन उद्योगों से कजाखस्तान के आर्थिक विकास में काफी सहायता प्राप्त हुई है | कजाखस्तान के इन उद्योगों में काफी मात्रा में विदेशी निवेश हुआ है | इन उद्योगों से कजाखस्तान में रोजगार में वृद्धि हुई है | कजाखस्तान में चिकित्सा-उपकरणों का भी निर्माण किया जाता है | कृषि की मशीनरी का उत्पादन के कारण कृषि के क्षेत्र में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है | कृषि संबन्धित उपकरणों के साथ-साथ डीजल इंजन उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित मशीनें, इलेक्ट्रिक मोटर्स का निर्माण भी कजाखस्तान में किया जाता है | कजाखस्तान में उपकरण निर्माण उद्योगों में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है | (Ibid 2008: 40)

विनिर्माण सामग्री पर आधारित उद्योग :

कजाखस्तान में विनिर्माण सामग्री पर आधारित उद्योग भी उन्नत अवस्था में पाए जाते हैं | कजाखस्तान का कुल औद्योगिक उत्पादन में इन उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत है |

इन उद्योगों के अंतर्गत सीमेंट पाइप, लिनोलियम, सेनेटरी बिल्डिंग फ़ैनेस, सिरेमिक बार सीमेंट आदि का निर्माण किया जाता है | इन सामग्रियों का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया जाता है | यहाँ पर कागज उद्योग के लिए विभिन्न सामग्रियों का भी उत्पादन किया जाता है जैसे काओलिन, रेडिएटर इत्यादि | इसके अतिरिक्त कजाखस्तान में औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को शोधित करने का कार्य भी किया जाता है | (ibid 2008: 28-33)

यातायात :

कजाखस्तान की भौगोलिक स्थिति यूरेशिया के मध्य में स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है | यहाँ की भौगोलिक स्थिति यातायात के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती है | यहाँ पर 2003 में 106 हज़ार किलोमीटर स्थल परिवहन (राजमार्ग) का निर्माण किया गया, जिससे कि आवागमन आसानी से हो सके | सड़क परिवहन को रेल मार्गों के साथ जोड़ने के लिए कजाखस्तान की सरकार प्रयासरत है | रेल मार्गों का लगातार विकास किया जा रहा है | अभी तक लगभग 13.5 हज़ार किलोमीटर रेल मार्गों का निर्माण किया गया है, इन राजमार्गों से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का आवागमन होता है | कजाखस्तान ने लगभग 4 हज़ार किलोमीटर अंतर्देशीय जल-मार्गों का भी निर्माण किया है | कजाखस्तान सीमावर्ती देशों से अपने आप को जोड़ने के लिए भी प्रयासरत है | कजाखस्तान द्वारा चीन से संपर्क के लिए ड्रिज्बा और अलाशंको के बीच रेलमार्ग का निर्माण किया गया है | एक दूसरे रेलवे लिंक सारख - तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बीच से “नया रेशम मार्ग” के जरिए ट्रांजिट कॉरिडोर, चीन के प्रशांत बंदरगाहों से सिंडो, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, तुर्की, भूमध्य और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों को जोड़ा जा सके | इन मार्गों से कजाखस्तान रूस और पूर्व सोवियत संघ के अन्य देशों से भी जुड़ता है | कजाखस्तान इन मार्गों पर तेजी गति से कार्य कर रहा है जिससे कजाखस्तान द्वारा अपने व्यापार को सम्पूर्ण विश्व के साथ जोड़ा जा

सके | भूमध्यसागर और भारतीय महासागर के रास्तों के द्वारा भी कजाखस्तान अपने व्यापार में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है | (Roy 2002: 48-64)

राष्ट्रीय एयरलाइंस "एयर कजाखस्तान" 40 से अधिक वायु-मार्गों के द्वारा उड़ान भरती है | कजाकिस्तान की यह विमान सेवा कंपनी सीआईएस (C.I.S.) देशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य प्रमुख देशों के लिए भी उड़ाने भरती है | कजाखस्तान में "एयर कजाखस्तान" के अतिरिक्त अन्य विदेशी कम्पनियाँ जैसे ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा, केएलएम, ट्रांसएरो, पीआईए, तुर्की एयरलाइंस, ईरान एयर इत्यादि भी नागरिक विमानन क्षेत्र में सेवा प्रदान करती हैं (Ibid 2002 48-64) |

कृषि :

कृषि कजाखस्तान की राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है | उत्तरी कजाखस्तान में जलवायु कृषि योग्य होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है | यहाँ वसंत ऋतु में गेहूँ और जई की खेती की जाती है एवं विभिन्न अनाजों का भी उत्पादन किया जाता है | इसके अलावा कजाखस्तान में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसमें तरबूज प्रमुख है | यहाँ जौ नामक खाद्यान्न का उत्पादन भारी मात्रा किया जाता है | कजाखस्तान नकदी फसलों का भी उत्पादन करता आया है जैसे - सूरजमुखी, सन, तंबाकू आदि | दक्षिण कजाखस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में शुष्क जलवायु होने के कारण कपास की खेती की जाती है, इसकी सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती है | इसके अलावा इस क्षेत्र में चुकंदर, तंबाकू, चावल आदि का भी उत्पादन किया जाता है | यहाँ बगीचों में विभिन्न प्रकार के दाख (मुन्नका) भी पैदा किए जाते हैं | कृषि उत्पादों के मामलों में कजाखस्तान सीआईएस देशों में रूस और यूक्रेन के बाद तीसरे स्थान पर आता है | कजाखस्तान ने वर्ष 1991 से 2017 के मध्य कृषि क्षेत्र में

कई गुणा विकास किया है | कजाखस्तान के पास भारी मात्रा में कृषि उत्पादों के भण्डार हैं, जिसका उपयोग देश में अन्न संकट के समय किया जा सकता है | यहाँ कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों का 1991 के बाद तीव्र गति से विकास हुआ है | कजाखस्तान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र (विशेषकर मध्य और दक्षिण-पश्चिम भागों) में व्यापक स्तर पर मवेशियों की चराई की जाती है | यहाँ के लोग परंपरागत पशुपालन भी करते हैं इनमें भेड़, घोड़ा, ऊंट इत्यादि मवेशियों का पालन (यहाँ पर मवेशियों को पशुधन के रूप में जाना जाता है) किया जाता है, जो यहाँ के खाद्यान्न-सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | (Panasyuk, Gafurov, and Novenkova, 2013:102-150)

विदेशी व्यापार :

वर्तमान समय में कजाखस्तान ने अपनी निर्यात क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि किया है | कच्चे माल का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है | कजाखस्तान मुख्य रूप से ईंधन, धातु व रासायनिक सामग्रियों का भारी मात्रा में निर्यात करता है | कजाखस्तान अपने खनिज तेल उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत विदेशों को निर्यात करता है | यह अपने गैर-लौहधातुओं के उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत निर्यात विदेशों में करता है | इसके विदेशी निर्यातों में लौह धातुओं की भागीदारी 16 प्रतिशत तथा कृषि उत्पादों का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है | कजाखस्तान द्वारा मूलरूप से आयातित वस्तुओं में मशीनें और उपकरण प्रमुख हैं | इसके अलावा कजाखस्तान ऑटोमोबाइल, स्वचालित उपकरण, रासायनिक उत्पाद तथा कुछ ईंधन खनिज पदार्थों इत्यादि का आयात भी करता है | कजाखस्तान के आयात-निर्यात में परिवर्तन के कारण आँकड़े प्रति वर्ष बदलते रहते हैं | अभी भी कजाखस्तान के व्यापारिक संबंध सीआईएस (C.I.S.) देशों के साथ अच्छे हैं | इन देशों के साथ कजाखस्तान अपने विदेशी व्यापार का लगभग 59 प्रतिशत निर्यात और 64 प्रतिशत आयात करता है | आज भी रूस के साथ कजाखस्तान की

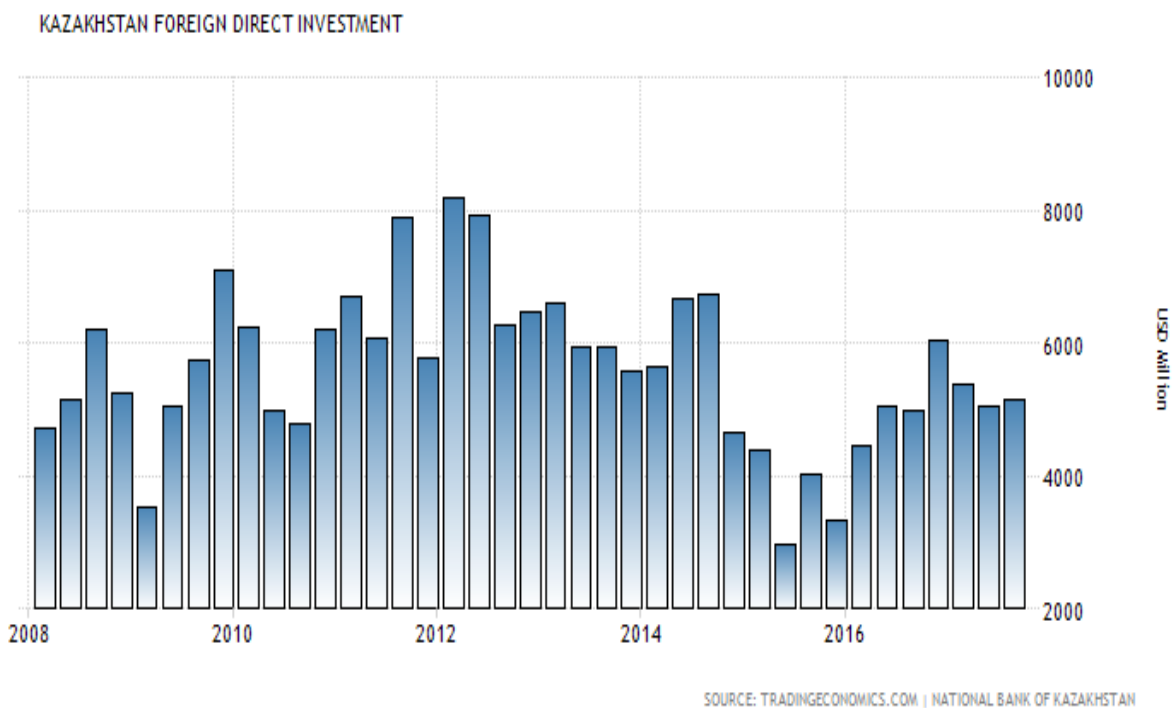
व्यापारिक भागीदारी बहुत अच्छी है | अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अपने उद्योगों में विदेशी निवेश और तकनीकी की प्राप्ति के लिए कजाखस्तान प्रयासरत है | कजाखस्तान के व्यापारिक संबंध जर्मनी, तुर्की, स्विटजरलैंड, इटली, चीन, अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया से भी हैं तथा इन देशों के साथ वह सफलतापूर्वक व्यापार कर रहा है | कजाखस्तान अपने व्यापार के निरन्तर विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सभी देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहता है | (Yenikeeff 2008: 5-78)

कजाखस्तान में निवेश के अवसर :

कजाखस्तान विदेशी निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है | यहाँ पर पाए जाने वाले विशाल मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के कारण संसार के विभिन्न देश निवेश के लिए तत्पर रहते हैं | कजाखस्तान के इस विशाल बाज़ार का रणनीतिक महत्व भी है | कजाखस्तान ने 1991 से 2006 के मध्य लगभग 30 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया है, परंतु विदेशी निवेश कजाखस्तान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कजाखस्तान अभी भी विदेशी निवेश के लिए काफी प्रयास कर रहा है | कजाखस्तान विदेशी निवेश के द्वारा अपने बुनियादी आर्थिक ढांचे को बनाये रखना चाहता है | वर्तमान समय में कजाखस्तान में विभिन्न विदेशी कम्पनियों के द्वारा (कजाखस्तान) सरकारी उद्योगों में सहभागिता की जा रही है | (Sarkar and Din, 2003: 39-42)

कजाखस्तान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यदि बात करें तो आलेखित चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, कि कजाखस्तान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2008 के बाद कुछ समय के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ा है किन्तु इसके दो वर्ष पश्चात् एकदम निम्न स्तर पर बना हुआ है | इस प्रकार कजाखस्तान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में उतार-चढ़ाव होता रहा है | वर्ष 2012

में हम पाते हैं कि कजाखस्तान में लगभग 8 हज़ार अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है | यह अब तक कजाखस्तान में हुआ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है | इसके पश्चात् कजाखस्तान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में फिर गिरावट आई है, जो कि कजाखस्तान के लिए चिंता का विषय है | इस विदेशी निवेश की गिरावट के कारण कजाखस्तान की राष्ट्रीय आय में कमी आई है | इस चित्र में हम देखते हैं कि वर्ष 2016 से 2017 के बाद कजाखस्तान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ने के आसार दिखाई देते हैं, जो कि भविष्य की संभावनाओं की ओर इंगित करता है | कजाखस्तान में निवेश के बहुत अवसर हैं | यहाँ पाए जाने वाले तेल और यूरेनियम पर विश्व के सभी देशों की नज़र है, जिससे यहाँ पर भारी मात्रा में विदेशी निवेश की संभावनाओं को बल मिलता है | (Forecast News 2017)



Kazakhstan's Foreign Direct Investment.

Source:-<https://tradingeconomics.com/kazakhstan/foreign-direct-investment>

क्षेत्रीय सहयोग:

कजाखस्तान द्वारा अपने राष्ट्रीय कोष को स्थिर बनाए रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में विविधिकरण के उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं | कजाखस्तान द्वारा आने वाले वर्षों में तेल के निर्यात से प्राप्त होने वाले धन से अपनी निर्भरता को बचाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए गए हैं | कजाखस्तान ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए तुसमगेटोव द्वारा “यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी” में भागीदारी करके अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है | कजाखस्तान द्वारा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (E.E.U.) के समूह में बेलारूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इत्यादि देशों के साथ मिलकर अपनी (यूरेशियन देशों की) आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है | इसकी स्थापना वर्ष 2000 में रूस में की गई थी, मई 2001 में इस समूह के द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था | यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर्थिक गतिविधियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है | क्षेत्रीय एकीकरण के मामले में रूस कजाखस्तान का हमेशा से साथ देता रहा है | (Gleason,2003:32-38)

जनवरी 2006 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक क्षेत्रीय योजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत यह बात रखी गई थी कि इन देशों (यूरेशियन देशों) के बीच एक ऐसा क्षेत्रीय गैस उत्पादक समूह स्थापित किया जाये जो सीआईएस (C.I.S.) देशों में समान रूप से कार्य कर सके (जिस प्रकार से खाड़ी देशों में ओपेक नाम का समूह कार्य कर रहा है) | मध्य एशियाई देशों में से सर्वप्रथम कजाखस्तान के द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया | इसके पश्चात् ही अन्य मध्य एशियाई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था | इस तरह

कजाखस्तान के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ही अन्य मध्य एशियाई देशों के आर्थिक लाभ के लिए भी क्षेत्रीय सहयोग का हमेशा से समर्थन दिया गया | (Ibid 2002: 34-40)

शंघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) एक उभरता हुआ संगठन है | यह “शंघाई पाँच” के रूप में भी जाना जाता है | प्रारंभ में इस संगठन में रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ही सम्मिलित थे | कजाखस्तान अपने कच्चे माल का निर्यात मुख्य रूप से चीन और मध्य एशिया के विभिन्न राज्यों के साथ करता आया है | कजाखस्तान के अलावा मध्य एशिया के वे देश जो शंघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) में आते हैं, उनके साथ कजाखस्तान उस समय (1996 में) लगभग 3 प्रतिशत निर्यात करता था, परंतु अब वर्तमान समय में कजाखस्तान के निर्यात की क्षमता निरन्तर वृद्धि परिलक्षित होती है | इस संगठन के आर्थिक गतिविधियों में चीन और रूस की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है | (Kozhokin 2001 : 885)

कजाखस्तान को पड़ोसी देशों के साथ सीमा सम्बन्धी विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है | इन बाधाओं के बावजूद भी कजाखस्तान अपने व्यापार को निरन्तर प्रोत्साहित करता रहा है | इस संगठन में रूस और चीन के विद्यमान होने के कारण कजाखस्तान की अर्थव्यवस्था सकारात्मक लाभ होने के आसार लगते हैं, क्योंकि कजाखस्तान के पास भरपूर मात्रा में तेल और गैस तथा यूरेनियम के भंडार हैं | शंघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) के अंतर्गत एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) का भी निर्माण किया गया है, ताकि इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच बिना किसी रूकावट के परस्पर व्यापार हो सके | (Ibid 2001: 870-885)

कजाखस्तान ऐसे बहुपक्षीय संगठनों के अलावा विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों का विस्तार कर रहा है | इन देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, तुर्की ईरान, और

भारत सम्मिलित है | कजाखस्तान ने द्विपक्षीय सम्बन्धों के अंतर्गत इन देशों के साथ राजनैतिक समझौतों के साथ ही साथ आर्थिक समझौते भी किए हैं | इन देशों में से पहले कोई भी बहुपक्षीय संगठनों (जैसे S.C.O.) में एक भी देश सम्मिलित नहीं था | भारत ने जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) की सदस्यता ग्रहण की है | अब भारत बहुपक्षीय रूप से कजाखस्तान के साथ आर्थिक रूप से सहभागिता का कार्य कर सकेगा | कजाखस्तान अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को और भी विस्तृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे अन्य राष्ट्रों के साथ भी द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता नजर आता है | (Suhag 2017: 1-3)

मध्य एशियाई देशों में से कजाखस्तान एक मात्र ऐसा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक मात्रा में व्यापार करता है | इन दोनों देशों के द्वारा सर्वप्रथम “क्लस्टर पहल” की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कजाखस्तान के व्यापार का विस्तार भारतीय व्यापार जगत के साथ करना था | कजाखस्तान का मानना था कि इस प्लान के तहत आर्थिक क्षेत्र में परस्पर लाभ अर्जित किया जा सकता है | कजाखस्तान ने भारत के साथ पर्यटन, कृषि उद्योग, प्राकृतिक तेल और गैस, मशीनरी, कार्गो, निर्माणगत सामग्री, धातुविज्ञान और वस्त्र, भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों (S.M.I.) के साथ साझेदारी स्थापित करने की संभावना व्यक्त की है, ताकि दोनों देशों के द्वारा क्लस्टर प्लान के तहत निवेश में परस्पर सहयोग करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके | कजाखस्तान के द्वारा 1991 से ही भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है | इसके परिणामस्वरूप कजाखस्तान और भारत के मध्य आयात और निर्यात में वृद्धि को देखा जा सकता है | वर्तमान समय में दोनों देशों के लिए रोजगार में अवसरों की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है | इस प्रकार के प्रयासों द्वारा दोनों देशों में रोजगार के नए अवसरों के उभरने के आसार बन सकते हैं | भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति एक

बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस कारण भारत कजाखस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों के विस्तार को लाभ की दृष्टि से देखता है | यदि भारत और कजाखस्तान के मध्य व्यापारिक रिश्ते इतने ही मजबूत बने रहते हैं, तो यह दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी | (Ibid 2017: 1-4)

कजाखस्तान में पिछले कई वर्षों से तेल के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी हुई है | अतः भारत की बढ़ती तेल की मांग को पूरा करने के लिए कजाखस्तान एक अच्छा निर्यातक हो सकता है | आज के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर क्रेता और विक्रेता के रूप में देख सकते हैं, जो दोनों ही देशों के साझे सहयोग द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं |

1991 के बाद से ही भारतीय उर्जा कंपनियों के द्वारा कजाखस्तान में तेल व गैस खनन क्षेत्र में भागीदारी का प्रयास किया गया | वर्ष 2005 में अलमाटी में आयोजित 13वें कजाखस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस प्रदर्शनी में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भाग लिया और कजाखस्तान के साथ भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में चर्चा की | (Embassy of India Astana 2010: 1-3)

कजाखस्तान और भारत के संबंधों का मूलरूप से उद्गम मध्यकाल और आधुनिक काल को माना जाता रहा है | ऐसा माना जाता है की कजाखस्तान एवं भारत का संपर्क प्राचीनकाल की विरासत है, जो अभी भी परंपरागत रूप से चली आ रही है | कजाखस्तान और भारत के आर्थिक समानता ऐतिहासिक संबंधों के कारण ही संभव हुआ है | इसलिए प्राचीनकाल से ही मध्य एशियाई क्षेत्र दोनों देशों का आवागमन का केंद्र-बिंदु रहा है | यहाँ पर पार-महाद्वीपीय व्यापारिक मार्ग से परागमन होता रहा है | मध्य एशिया का यह क्षेत्र व्यापारियों और यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था | इस बिन्दु पर व्यापारियों और यात्रियों के समूह व्यापार-वाणिज्य के कार्य करते

थे | प्राचीन काल से ही मध्य एशिया और भारत के लोगों के मध्य विचारों और वस्तुओं का आदान-प्रदान होने लगा, जिससे मध्य एशिया और भारत के बीच निकटता बढ़ने लगी | भारतीय रीति- रिवाजों के प्रति मध्य एशिया में सम्मान की भावना पायी जाती थी | आज मध्य एशिया न केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है | भारत द्वारा जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाँच दिवसीय यात्रा इस बात को सिद्ध करती है कि मध्य एशिया क्षेत्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है | (Jacob 2015: 1-3)

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कजाखस्तान स्वतंत्र हो चुका था, इसके बाद कजाखस्तान और भारत के संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गये थे क्योंकि कजाखस्तान की भौगोलिक स्थिति की विशेषता के कारण भारत कजाखस्तान के साथ गुणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करने लगा | कजाखस्तान और भारत के बीच समान समस्याएँ हैं | कजाखस्तान और भारत के मध्य आतंकवाद और इस्लामिक भय अधिक प्रभावशाली है जिनका सामना दोनों देशों को करना पड़ रहा है, इस प्रकार की समस्याओं से दोनों देशों के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है | कजाखस्तान और भारत के मध्य उत्पन्न समस्याओं को खत्म करने के लिए दोनों देशों को समान रूप से एक साथ आर्थिक विकास के पथ पर चलना अनिवार्य है | (Roy 2002:48-15)

कजाखस्तान और भारत के बीच व्यापारिक आकड़ों का पूर्वावलोकन करें, तो हम पाएंगे कि पिछले 10 वर्ष के दौरान 2005 में दोनों देशों के बीच व्यापार 120.88 मिलियन डॉलर था और 2006 में 210.25 मिलियन डॉलर हो गया | इन वर्षों के अंतराल में 73.93 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है | इस आकड़ों से यह सिद्ध होता है कि कजाखस्तान और भारत के बीच व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुआ है | वर्ष 2004 में 96.5 मिलियन डॉलर व्यापार था जबकि अगर देखा जाए तो 2006 में इसका दुगुना व्यापार हुआ है | इन आँकड़ों को देखे तो हम पाएंगे कि

उस समय कजाखस्तान और भारत के मध्य सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का 13.2 मिलियन डॉलर व्यापार हुआ था इस प्रकार कजाखस्तान और भारत के मध्य व्यापारिक कार्यों में तीव्रता से वृद्धि हुई है | (Hussain 2009: 1-10)

कजाखस्तान के द्वारा भारत को निर्यात मुख्य रूप से प्राकृतिक तेल, नमक, सीमेंट, चमड़ा, कच्चेमाल और लौहसंबंधी तत्वों का होता है एवं कजाखस्तान द्वारा भारत से कॉफी, चाय, सिगरेट, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और इससे संबंधित सामान, रबर और इससे संबंधित उत्पाद, उपकरण और यांत्रिक उपकरणों, बिजली उपकरणों आदि वस्तुओं का आयात किया जाता है | कजाखस्तान और भारत के मध्य पिछले 5 वर्ष के आँकड़ों का आकलन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि अब तक कजाखस्तान और भारत के मध्य व्यापार और निवेश में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है | नीचे दी हुई इस सारणी में इस बात की व्याख्या की गयी है

Bilateral trade	2013	% change over previous year	2014	% change over previous year	2015	% change over previous year	2016	% change over previous year	2017	% change over previous year
Exports to Kazakhstan	351.63	(+) 5.47%	260.50	(-) 25.9%	241.77	(-) 7.2%	203.81	(-) 15.7%	182.91	(-) 10.25%
Imports from Kazakhstan	330.85	(+) 90.2%	1083	(+) 227.3%	220.08	(-) 79.68%	414.61	(+) 88.39%	575.9	(+) 38.9%
Total Trade	682.49	(+) 34.5%	1343	(+) 96.78%	461.85	(-) 65.61%	618.42	(+) 33.9%	758.81	(+) 22.7%

Bilateral Trade between India and Kazakhstan during last five years (in US\$ millions)

Source:-<http://www.indembastana.in/ieb.php?id=Investment%20Statistics>

सारणी के अंतर्गत हम 2013 से 2017 के मध्य दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का आकलन कर सकते हैं | हम देखते हैं कि वर्ष 2013 से 2014 के बीच कजाखस्तान और भारत के मध्य कुल व्यापार 682.49 मिलियन अमेरिकन डॉलर हुआ है, जो 2014 में बढ़कर 1343 मिलियन डॉलर हो गया | इस समय अंतराल में कुल व्यापार में 34.5 प्रतिशत का बदलाव आया है | इसी प्रकार इन पाँच वर्षों में दोनों देशों के मध्य निवेश में भी वृद्धि हुई है | 2017 में आयात और निर्यात की मात्रा में 22.77 प्रतिशत सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है परंतु कुल व्यापार में कमी आई है | कजाखस्तान ने वर्ष 2013 में भारत में कुल 351.63 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है, परंतु यह 2014 में घटकर 260.50 डॉलर हो गया था इस तरह एक वर्ष के अंतराल में -25.9 प्रतिशत निर्यात कम हुआ है | इसी तरह 2015 और 2016 के निर्यात के आकड़ों को देखे तो पायेंगे कि निर्यात में -7.3 प्रतिशत की कमी आई है, इस से ज्ञात होता है कि कजाखस्तान और भारत के मध्य निर्यात धीरे-धीरे घट रहा है | आयात के आकड़ों से पता लगता है कि कजाखस्तान ने 2013 में 330.85 मिलियन डॉलर का आयात किया है और 2014 में यह बढ़कर 1083 मिलियन डॉलर हो गया है | इस समय अंतराल में 90.2 प्रतिशत की तेजी से बढ़ोतरी हुई है | इस प्रकार हम 2016 और 2017 के मध्य के आयात का आकलन करे तो पायेंगे कि 618.42 मिलियन डॉलर से 758.81 मिलियन डॉलर का आयात हुआ है | इन आकड़ों से ज्ञात होता होता है कि कजाखस्तान और भारत के बीच पिछले पाँच वर्ष के अंतराल में निवेश में बार-बार परिवर्तन होने के बाद भी आयात और निर्यात सकारात्मक रहा है | (Embassy of India, Kazakhstan 2017)

कजाखस्तान और भारत के मध्य वास्तविक रूप से बुनियादी ढांचों की कमी रही है | इसका कारण यह है कि इन दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार परिवहन (व्यापार का सीधा रास्ता न होने कारण) नहीं है | वर्तमान समय में कजाखस्तान और भारत के मध्य व्यापार “परिवहन

कंटेनर” के माध्यम से होता है, जो भारत से चीन और चीन से कजाखस्तान के लिए प्रस्थान करता है | दूसरा मार्ग भारत से ईरान और ईरान से कजाखस्तान को जाता है | इन दोनों मार्गों से ही कजाखस्तान और भारत के बीच व्यापार होता आया है, और इन दोनों ही रास्तों से व्यापार में अत्यधिक परिवहन खर्च आता है | जिसके कारण वस्तुओं की कीमत में काफी वृद्धि हो जाती है | इस कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार की गति धीमी हो गयी है |

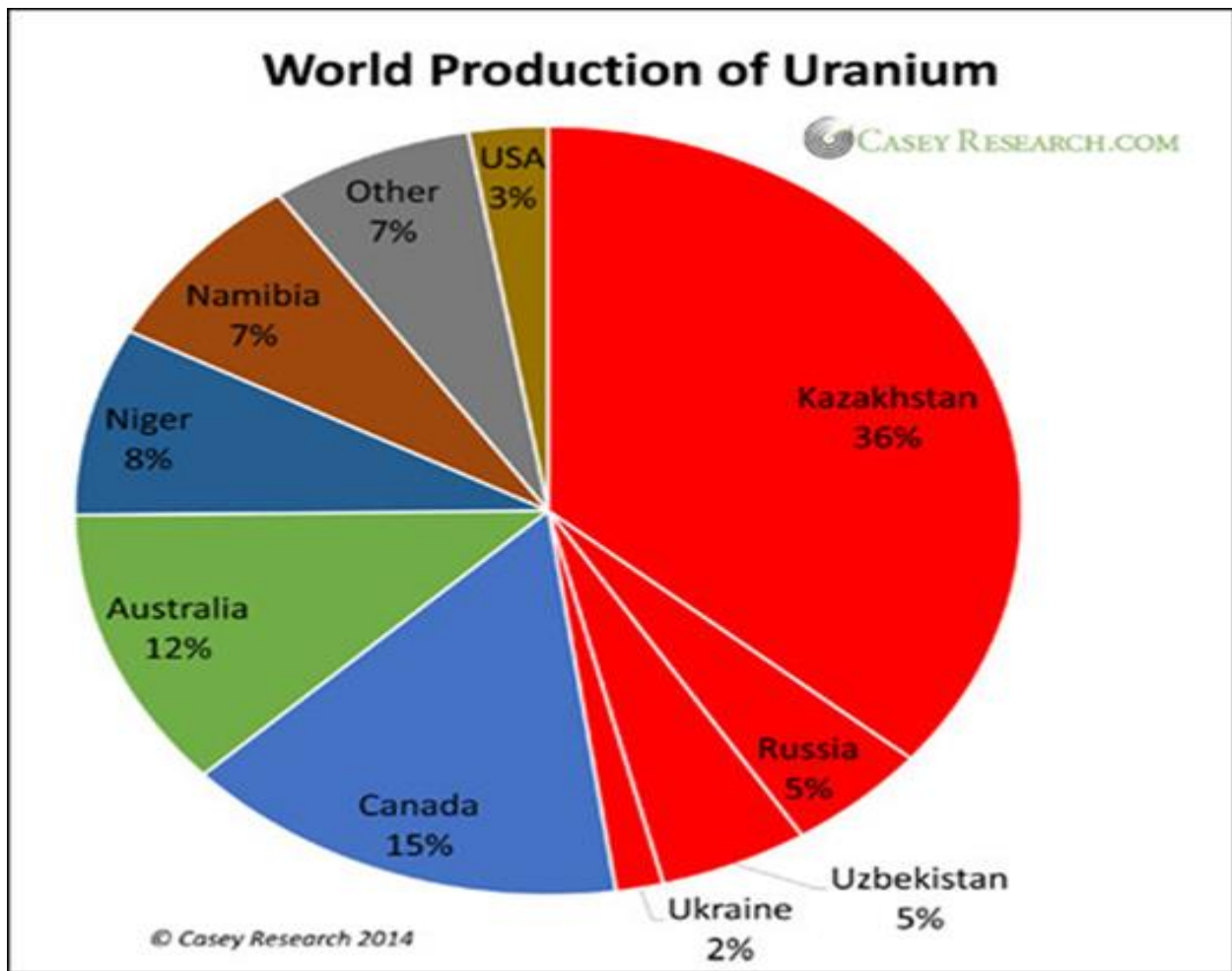
कजाखस्तान के साथ व्यापार के लिए भारत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के सात शाखाओं की स्थापना 1998 में अलमाटी में की गई है, जिससे कि दोनों देशों के मध्य व्यापार-वणिज्य और निवेश की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके | वहीं दूसरी तरफ कजाखस्तान के द्वारा भारत में किसी भी प्रकार के बैंक की स्थापना नहीं की गई | कजाखस्तान और भारत ने व्यापार से संबन्धित विभिन्न प्रकार की कमियों को पूरा करने के लिए तेज गति से ठोस कदम उठाये हैं | निवेश से संबन्धित मुद्दों को दोनों देशों की सरकारें परस्पर विचार-विमर्श द्वारा हल करती रहीं हैं | इस सम्बन्ध में कजाखस्तान और भारत ने जुलाई 1993 में एक आर्थिक आयोग की स्थापना कर दी थी | (Mukarji 2006:24-35)

भारत और कजाखस्तान के मध्य परिवहन विभिन्न रूपों में है | हालांकि दोनों देशों के लिए “नॉर्थ-साउथ कॉरीडोर” बहुत ही महत्व रखता है | इसके अतिरिक्त कजाखस्तान और भारत को जोड़ने के लिए फिर से परंपरागत “रेशम मार्ग” (सिल्क रूट) को पुनः स्थापित किया जा सकता है | इस मार्ग को चीन के शिनचियांम प्रांत के माध्यम से मध्य एशिया की सड़कों से जोड़ा जा सकता है, जो कि कजाखस्तान की मौजूदा रेलवे लाइनों के साथ उत्तर-दक्षिण दिशा में एक सीधा रूप लेते हुए कजाखस्तान, पश्चिमी चीन और भारत की सड़कों में शामिल होते हुए अल्माटी, कोर्ग, यिनिंग, कूका, अकसू, कशगर, यारकंद, यिकांग (शिनचियांम-तिब्बत के साथ राजमार्ग सं 219), मजार, शाहिदुआई, सरन्क्षी, डरब, रिजम, शिखानेहे, गार,कैलाश, बुरांग, लेपु-इकाह आदि

स्थानों को जोड़ा जा सकता है | इस मार्ग की कुल दूरी 3000 किलोमीटर से भी कम है, जबकि ईरान से कजाखस्तान को जाने वाले मार्ग की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर है | जबकि यह सिल्क रूट का यह मार्ग पूर्वस्थापित है और वर्तमान समय में केवल इस मार्ग को पुनर्जीवित करना है (Ibid) |

भारत और कजाखस्तान द्वारा “ज्वाइंट वर्किंग” ग्रुप बनाया गया है जोकि परिवहन के साथ ही साथ इन दोनों देशों के मध्य निवेश के कार्यों को भी देखता है | कजाखस्तान और भारत के लिए नॉर्थ साउथ कॉरीडोर भी वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से भारत और कजाखस्तान की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के और अधिक निकट आ सकती हैं | यूरेनियम के आपूर्तिकर्ता देश के रूप में कजाखस्तान भारत के लिए विशेष महत्व है | भारत चूँकि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके पास उर्जा संसाधन कम मात्रा में हैं अतः भारत कजाखस्तान को एक भावी सहयोगी के रूप में (विशेषकर उर्जा संसाधनों के आपूर्तिकर्ता देश के रूप में) देखता है | अंतर्राष्ट्रीय उर्जा संस्थान का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में उर्जा की खपत दुगुनी हो जाएगी |

विश्व में यूरेनियम का उत्पादन 2016 में लगभग 62,012 टन हुआ था | उर्जा संसाधनों के रूप में यूरेनियम की मांग सम्पूर्ण विश्व में अधिक हो रही है इसलिए कजाखस्तान द्वारा अपने यूरेनियम के भण्डारों का खनन अधिक मात्रा में किया जा रहा है | कजाखस्तान में यूरेनियम की इतनी मात्रा है कि अगले 50 वर्षों तक भी यह नहीं समाप्त होगा | पिछले कई वर्षों से यूरेनियम उत्पादन देशों में कजाखस्तान का स्थान अग्रणी रहा है |



World Production of Uranium (In %)

Source:-<https://www.wiseinternational.org/nuclear-energy/uranium-mining>

वर्ष 2017 के आकड़ों के अनुसार यह विश्व में यूरेनियम उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, इसके बाद कनाडा और आस्ट्रेलिया का स्थान आता है | कजाखस्तान में विश्व का लगभग 39 प्रतिशत उत्पादन 2017 में किया गया, जो कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है (Show 2017: 1-2) |

विदेशी निवेशकर्ताओं के कजाखस्तान की ओर आकर्षित होने का एक प्रमुख कारण यूरेनियम ही है | भारत ने कजाखस्तान के साथ जुलाई 2015 में यूरेनियम की पूर्ति के लिए एक समझौता

किया है | भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनसी काजएटमप्रोम जेएससी और एनपीसीआईएल के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया गया | इस कांट्रैक्ट के तहत 5000 टन यूरेनियम कज़खस्तान भारत के लिए 2019 तक निर्यात करेगा, जो कि ऊर्जा संबंधी भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है | प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कजाखस्तान उन पहले देशों में शामिल है, जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता किया है (Show 2017: 1-2) |

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबायेव के बीच वार्ता के दौरान एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने अपने करीबी क्षेत्र और दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद की बढ़ती चुनौती को रेखांकित किया है और इन दोनों देशों का मानना है कि शांतिपूर्ण आर्थिक विकास के लिए स्थिर और सुरक्षित माहौल आवश्यक है | इस बयान में यह भी कहा गया कि दोनों देशों ने आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सहभागिता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है जिनमें सूचनाओं का आदान-प्रदान भी शामिल है (World Nuclear News 2015) |

कजाखस्तान और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध जीवंत, गतिशील और विस्तारित रहे हैं हालांकि इनका विकास पूर्णरूप से अभी नहीं हुआ है | भारत और कजाखस्तान के बीच 2016 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 618.42 मिलियन डालर से लगभग 758.81 मिलियन डॉलर हो गया है | इस तरह दोनों देशों के आपसी व्यापार में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है | कजाखस्तान में होने वाले विदेशी निवेश में भारतीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है जैसे पुंज लॉयड कजाकिस्तान लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, टीसीएस आदि | प्राकृतिक तेल और गैस के उत्पादन में कजाखस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है जिसके कारण यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के खनन और शोधन के क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में विदेशी कम्पनियाँ

सक्रिय हैं | भारत से कजाकिस्तान को निर्यात होने वाली वस्तुओं में चायपत्ती का प्रमुख स्थान है, परंतु पैकेजिंग की गुणवत्ता में कमी के कारण भारतीय चाय धीरे-धीरे कजाखस्तान के बाजार में अपनी पहचान खो रही है | भारत और कजाखस्तान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को घनिष्ठ करने में सबसे बड़ी समस्या सीधा संपर्क मार्ग का न होना है | इसके कारण आपसी व्यापार में तीव्र बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है

अध्याय-4

रक्षा सहयोग

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रक्षा सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रक्षा सहयोग द्वारा सैन्य सामग्री का आदान प्रदान, सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण इत्यादि जैसी प्रक्रिया को परस्पर मिलकर करता है इसी कदम में कजाखस्तान और भारत के बीच रक्षा सहयोग जैसे संबंध उभर कर आते हैं । इन दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबन्धित मुद्दे एक जैसे हैं चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या नशीली दवाओं की तस्करी संबंधित मुद्दे । इस प्रकार के मुद्दे राष्ट्रीय हित के लिए नकारात्मक सिद्ध होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक बन जाते हैं ।

कजाखस्तान और भारत के मध्य रक्षा क्षेत्र में संबंध पहले इतने प्रभावशाली नहीं थे लेकिन वर्तमान समय में रक्षा सहयोग उभर कर सामने आ रहे हैं । जिससे दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है । कजाखस्तान और भारत के मध्य राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरों का सामना करने के लिए रक्षा सहयोग किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके लिये हमें दोनों देशों की सुरक्षा संबंधित खतरों को समझना होगा ।

कजाखस्तान एवं भारत के समक्ष सुरक्षा का खतरा :

कजाखस्तान और भारत इन दोनों देशों के मध्य सुरक्षा से संबन्धित खतरे मुख्य रूप से प्रचलित हैं इन खतरों के कारण दोनों को धमकी भरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । इन खतरों में आतंकवाद, इस्लामी कट्टरतावाद, अफगानिस्तान में अस्थिरता, नशीले पदार्थों का व्यापार और कैस्पियन सागर में आये दिन धमकी भरे घटित मुद्दे हैं । इस तरह के खतरों को देखते हुये कजाखस्तान की रक्षा बल को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है । इसी तरह भारत में भी आतंक का भय बना हुआ रहता है यहाँ पर भी नशीले पदार्थों का व्यापार, कश्मीर में उग्रवादी

संगठनों का दिन प्रति दिन खून-खराबा इत्यादि घटनाओं को देखते हुए दोनों देशों की सरकार एक दूसरे को रक्षा सहयोग करने के लिए परस्पर अग्रसर है ।

आतंकवाद और इस्लामी कट्टरतावाद :

कजाखस्तान में होने वाले आतंकी हमलों में हम देखें तो अकोबे में घटित जून 2016 के आतंकी हिंसक हमला मुख्य है, जिसमें कजाखस्तान के लोगों को भारी मात्रा में जन धन का नुकसान हुआ है यह हमला अमेरिका में घटित सितंबर 2001 के हमले के समान था जिससे ज्ञात होता है की आतंकवाद से लोग किस तरह से भयभीत रहते हैं अकोबे के हमले का अवलोकन करने पर कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSG) ने बयान जारी किया कि इस प्रकार के हिंसक हमलों में बालखश शहर के निकट रूसी सैन्य इकाई भी सम्मिलित थी जो आतंकी समूह का साथ देती है इससे यह स्पष्ट होता है कि कजाखस्तान का पड़ोसी देश रूस भी किसी न किसी रूप में कजाखस्तान में आतंक फैलाने के लिए तत्पर है । कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने (NSG) यह बताया कि आतंकी समूह में आठ अलग-अलग इस्लामिक समूह है, जिनमें कुछ किर्गिस्तान के नागरिक भी शामिल है जो कजाखस्तान के अंतर्गत इस्लामिक कट्टरतावाद का साथ देते हैं । इस्लामिक समूह होने के कारण कजाखस्तान में इस्लामीकरण का प्रचलन लगातार जारी है जो दिन प्रतिदिन आतंकी हमले कराने में लगे हुए है जिसके कारण कजाखस्तान में आतंकी भय बना रहता है । (Sorbello and Galdini, 2017:13)

कजाखस्तान की तरह भारत में भी आतंक का भय बना हुआ है । भारत में नवंबर 2008 के मुंबई हमले को देखने से पता लगता है कि इस हमले में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था इस आतंकी घटना से सम्पूर्ण भारत में आतंकवाद का डर सताने लगा इस आतंकी घटना से पता लगता है कि उग्रवादियों के अंतरंग संबंध वैश्विक स्तर पर फैले हुये जिहादी

नेटवर्क से जुड़े हुये है जिसमें ओसामा बिन लादेन, अलकायदा एवं पाकिस्तानी जिहादी संस्कृति का सहयोग प्राप्त है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद के विभिन्न समूह जैसे अलगाववादी समूह, माओवादी समूह, नक्सलियों का समूह भी किसी न किसी रूप में उग्रवादियों के लिए एक उपकरण की भांति कार्य करते है इससे यह पता लगता है की स्वदेशी समूह भी तीव्र हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में होने वाले हमले को मददेनजर रखते हुये जात होता है की भारत के लिए रक्षा बल कितना महत्वपूर्ण है | इसी वजह से भारत रक्षा बल को मजबूती देने के लिए कजाखस्तान के साथ सैन्य प्रशिक्षण कराने के लिए रक्षा सहयोग में अग्रणी भूमिका निभा रहा है | (Riedel 2008:1-5)

अफगानिस्तान में अस्थिरता एवं नशीले पदार्थों की तस्करी :

कजाखस्तान और भारत के समक्ष अफगानिस्तान में विद्यमान इस्लामिकरण और नशीले पदार्थों का व्यापार जैसी घटनाएँ दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अफगानिस्तान से कजाखस्तान और भारत में इस्लामिकरण का प्रचार- प्रसार होता है एवं नशीले पदार्थों का व्यापार इन देशों में होता है भारत और कजाखस्तान में अपने- अपने पड़ोसी देशों के माध्यम से इस्लामीकरण का प्रसार और नशीले पदार्थों का प्रचलन हुआ है | जिनके कारण दोनों देशों में आतंकी घटनाओं का होना संभव है इन देशों में नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसका प्रभाव हम राष्ट्रीय स्तर पर ऋणात्मक दृष्टि के रूप में देखते है, जो दोनों देशों में युवा पीढ़ी को नशे का आदी बना दिया है | इन तथ्यों से यह पता लगता है की अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना दोनों देशों के लिए कितना उपयोगी है | सन् 2001 में कजाखस्तान की सरकार द्वारा अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए नए रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव प्रसारित किया गया | इस प्रस्ताव में कजाखस्तान द्वारा

तालिबान मिलिशिया के लगाव को समाप्त करना था | परंतु यह प्रस्ताव सफल नहीं होने के कारण कजाखस्तान में यथा स्थिति बनी हुई है | (McMahon 2001:1-5)

कजाखस्तान और भारत ने रणनीतिक साझेदारी के तौर पर दिसम्बर 2016 को संयुक्त कार्यकारी दल (JCW) की पाँचवी बैठक कि गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सीमा पार अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रचलित इस्लामीकरण के कारण फैले आतंक, नशीली दवाओं की तस्करी, कट्टरपंथीकरण और साइबर स्पेस का दुरुपयोग इत्यादि का अंत करना है, इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने सुरक्षा के महत्व को देखते हुये सूचनाओं का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, पारस्परिक रूप से कानूनी सहायता करना, हिंसक अतिवाद का मुकाबला करना एवं संयुक्त राष्ट्र और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोगात्मक रूप से साथ देने का निर्णय लिया गया | जिससे कि इस प्रकार की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से आतंकवाद जैसी विरोधी शक्तियों का अंत किया जा सकता हो | (Ministry of External Affairs, India 2017)

वैश्विक स्तर पर चुनौती :

कजाखस्तान और भारत के सामने वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियों का सामना करना होता है | इन चुनौतियों को दूर करने के लिए दोनों देशों को रक्षा सहयोग करने की आवश्यकता है उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कजाखस्तान के समक्ष कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के मध्य पानी का एक “लैंडलाकड बॉडी” है जिसकी अतर्देशीय समुद्री सीमाएं रूस, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान जैसे देशों से लगे होने के कारण इन देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहता है | कैस्पियन सागर का रणनीतिक महत्व ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता में निहित है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तेल और गैस के भंडार पाये गए हैं लेकिन

यहा पाँच सीमावर्ती देशों के मध्य विवाद बना हुआ है यह विवाद समुद्री सीमाओं का विभाजन नहीं होने के कारण बना हुआ है समुद्री सीमाओं का विभाजन नहीं होने के कारण ऊर्जा संसाधनों को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसके कारण अधिकांश संसाधनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है | इस विवाद का परिणाम कजाखस्तान को भुगतना पड़ रहा है जो आंशिक रूप से कजाखस्तान को प्रभावित करता है जिससे की मध्य एशियाई देशों को खतरों भरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है यह कजाखस्तान में आतंकी घटना घटित होने का एक कारण भी है, जो कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है |¹

कजाखस्तान की तरह भारत को भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है | भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण चीन जैसे राष्ट्र भारत का किसी न किसी रूप से विरोध करते आये हैं | भारत और चीन के बीच विभिन्न मुद्दे जैसे सीमा विवाद का मुद्दा, तिब्बत का मुद्दा, और आर्थिक स्पर्धा की होड़ इस प्रकार के मुद्दों का सामना करने के लिए रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना भारत के लिए अति आवश्यक है | इसलिए कजाखस्तान और भारत के लिए रक्षा सहयोग करना अति आवश्यक है जिससे कि दोनों देशों के खतरों संबंधित भय को खत्म किया जा सकें और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक मजबूत रूप प्रदान किया जा सके |

सुरक्षा :

कजाखस्तान और भारत की सुरक्षा की विवेचना करने से पूर्व हमें मध्य एशिया क्षेत्र के महत्त्व को समझना होगा | मध्य एशियाई क्षेत्र के संन्दर्भ में जैसा की संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पूर्व में ही मान लिया कि मध्य एशिया का “काकेशस” क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत कजाखस्तान को अत्यधिक महत्त्व की दृष्टी से देखा जाता

¹ Worldview release video, “The strategic important of Caspian Sea”. Available at: <https://worldview.stratfor.com/article/strategic-importance-caspian-sea>. Accessed on: 3 May 2018.

है | उन्होंने इस क्षेत्र की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाये रखने के लिए रूस को भी यह चेतावनी देते हुये निर्देश दिया की मध्य एशियाई देशों की संप्रभुता का उलंघन करने से दूर रहना चाहिए क्योंकि ईरान और तुर्की भी इस क्षेत्र के राजनीतिक सहयोगी है | (Banerjee 1996 : 725-40)

मध्य एशिया के महत्व को देखते हुये राज्य के उप सचिव स्ट्रोब टैलबोट जोहान ने हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में बोले कि “ “मध्य एशिया का काकेशस क्षेत्र सीमाओं के रणनीतिक दृष्टी से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जिससे चीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं” | इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि कजाखस्तान भी भारत के लिए प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है एवं भारत भी कजाखस्तान के लिए रक्षात्मक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है इसलिए दोनों देश परस्पर संबंधो का विकास करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक एवं रक्षा क्षेत्र में सामरिक भागीदारी निभा रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रक्षात्मक संबंधो पर ज़ोर दे रहे हैं |

राष्ट्रीय सुरक्षा वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों को वैध बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धारणा है | प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रथम श्रेणी में रखता है , जैसा कि हैन्स मोर्गेथऊ के अनुसार “राष्ट्रीय हित का अर्थ राष्ट्र-राज्यों में फैले अतिक्रमण के खिलाफ शारीरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा है |” उन्होने राष्ट्रीय हितों को राज्यों के उद्देश्यों, लक्ष्यों और मांगों के रूप में परिभाषित किया है | जिनके कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ आपसी संबंधो को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है जिससे की राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहती है | किसी भी देश की सुरक्षा की नीति राष्ट्रीय हितों पर भी आधारित होती है इसलिए सुरक्षा के पहलू को देखते हुये राष्ट्रीय हितों का ध्यान में रखा जाता है | (Morgenthau 1992 : 961-98

राष्ट्रीय सुरक्षा देश को बाहरी प्रभाव एवं आंतरिक अवक्रमण से बचाती है इसलिए यह देश के लिए कुछ मूल्यों में कल्याणकारी है | कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का विश्लेषण करने से हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार से कजाखस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्माण किया है | कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल जैसे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान ,रूस जैसे देशों की अवधारणाओं और प्रथाओं से जुड़ा हुआ है | परंतु भारत जैसे देश के साथ सुरक्षा का सहयोग भविष्य में सार्थक होने के आसार है | इसलिए कजाखस्तान और भारत की सुरक्षा को बनाए रखना अति आवश्यक मानते हैं | कानून के अनुसार कजाखस्तान की सुरक्षा के परिचालन के पक्ष सशस्त्र बल, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के अंग, जैसे खुफिया पुलिस, सैन्य बल, सेवा कर, सीमा शुल्क और आपातकालीन स्थिति की सेवा है | ये सब राष्ट्रपति के द्वारा सम्मिलित की जाती है | इन सभी सेवाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक सुरक्षा परिषद का गठन किया जाता है | जो इनके कार्यों और क्षमताओं को परिलक्षित करती है एवं राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षा की अवधारणाओं पर हस्ताक्षर किया जाता है | ² सुरक्षा परिषद जैसी संस्था के गठन की प्रक्रिया पूर्व सोवियत काल से ही चली आ रही है इस कारण इसे सोवियत संस्थागत विरासत माना जा सकता है क्योंकि इस का गठन 1990 में किया गया था |

कानून के अनुसार कजाखस्तान की सुरक्षा रूस की सुरक्षा के समकक्ष है जैसाकि रूस की सुरक्षा की परिभाषा के अनुसार सुरक्षा को आंतरिक खतरों और समाज में व्यक्तियों के लिए तथा राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कानून सुरक्षा के प्रावधानों की व्याख्या करता है | जैसे व्यक्तियों की समाज में वैधता है वैसे ही कानून राज्य में व्यक्तियों और समाज में संतुलन बनाए रखता है | कानून का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के संबंध से है जो विभिन्न राज्य निकायों के बीच जिम्मेदारियों का वितरण करता है | इसलिए

² "Official site of the President of the republic of Kazakhstan.", Available at <http://www.president.kz/en> , Accessed on 4 May 2018.

कजाखस्तान की सुरक्षा का प्रावधान कानूनी रूप से है | ³ कजाखस्तान के कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा का तीन स्तरों में विश्लेषण किया जाता रहा है | व्यक्ति ,समाज और राज्य की संस्थानों की सुरक्षा के रूप में लेकिन इन मुद्दों को अत्यधिक ईश्वरवादी माना गया है इसलिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है | जिसकी प्राप्ति से राज्य की क्षमता का विकास, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित की जाती है जिससे कि कजाखस्तान के नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें इसलिए कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समता मूलक है, जो सभी स्तरों पर संतुलन बनाए रखती हैं |

कजाखस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के दूरदर्शी पक्ष को देखें तो “कजाखस्तान मिशन 2030” के तहत कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबयाव ने कजाखस्तान की जनता को संबोधित करते हुए यह कहा कि “कजाखस्तान अभी बर्फ में चलते हुए तेंदुआ की गति से चल रहा है इसे एशियाई बाघों का पीछा करने के लिए 2030 तक का समय लगेगा हमें एशियाई देशों के साथ मिलकर काम करना होगा उन्नत प्रौद्योगिकियों को एशियाई ज्ञान और सुरक्षा के सहयोग से आगे बढ़ने की जरूरत है तभी हम कजाखस्तान को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देख सकते हैं और उन्नत प्रौद्योगिकियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बना पाएंगे अगर कजाखस्तान यूरोप और एशिया की सभ्यता के साथ सामरिक संबंध को जोड़ता है तो यूरेशिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनने की संभावना निश्चित है |” कजाखस्तान 2030 के मिशन की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी आक्रामक और समझदार दृष्टिकोण प्रदान करती नज़र आती है | इस मिशन को पूरा करने के लिए कजाखस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने की कोशिश करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, लेकिन भूगर्भीय प्रतिद्वंदियों में

³ “The security Council of the Russian federation” official site, Available at: <http://www.scrf.gov.ru/> ,Accessed on May 6 2018.

उलझन में नहीं आएगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश भी करेगा, कजाखस्तान तेल और गैस के बाज़ार का विस्तार करने का प्रयास लगातार कर रहा जिससे की विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने की संभावना निश्चित साकार हो सकती है कजाखस्तान का उद्देश्य पारंपरिक रूप से सैन्य-राजनीतिक-आर्थिक अर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार किया जाना इस मिशन के अंतर्गत है | ⁴

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य सैन्य बल को मजबूत करना है | वर्तमान संदर्भ में एक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतियों का अत्यधिक महत्त्व होता है | भारत की रणनीति स्वायत्तता के साथ साथ बाहरी सेना के खतरो से निपटकर देश को खतरों से बचाना है | इसका यह अर्थ है की भारत को आंतरिक और गैर परंपरागत खतरों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा इसके साथ-साथ राजनीतिक साधनों की भी आवश्यकता है | इस उपलब्धि को पाने के लिए भारत को समयबद्ध तरीके से घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय रणनीति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ सुरक्षा सहयोग करना होगा | (Compose 2016 :16)

भारत की राष्ट्रीय रक्षा नीति को एक आदर्श रूप में देखा जाना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को एक अभिन्न अंग के रूप में देखना राज्य के लिए महत्त्वपूर्ण है | सशस्त्र बलों की प्राथमिक भूमिका अपने क्षेत्र की रक्षा करना होता है | देश की अखंडता को बनाए रखना , संविधान में स्थापित मूल भूत मूल्यों की रक्षा करना, युद्ध में देश की सामरिक स्वायत्तता की सुरक्षा करना ,

⁴ Ibid

कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, ये सब तत्व राष्ट्रीय रक्षा नीति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं | (Compose 2016 : 25)

कजाखस्तान और भारत के विकास के हित में द्विपक्षीय सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है | जिसके अंतर्गत सुरक्षा का सैन्य क्षेत्र और तकनीकी क्षेत्र को परिलक्षित किया गया है | द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच एक प्रोटोकॉल के तहत कजाखस्तान के रक्षा मंत्रालय और भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त कार्यकारी समूह का निर्माण करने के लिए सहमति बनाई जिसके अंतर्गत कजाखस्तान और भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना क्षेत्र में सुधार और तकनीकी क्षेत्र में विकास को सकारात्मक गतिशीलता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है | (Tibb 2009: 200).

संयुक्त कार्यकारी समूह का पहला सत्र 2002 में निर्धारित किया गया था जिसमें कजाखस्तान और भारत के बीच सैन्य क्षेत्र में आधुनिक स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सामरिक सहयोग किया जाएगा जिससे कि कजाखस्तान और भारत की नौसेना बलों के लिए आधुनिक हथियार और उपकरणों को उपलब्ध कराने में सामरिक सहयोग किया जा सके | कजाखस्तान और भारत के विशेषज्ञों की कानूनी रूप से यात्रा करने पर यह निर्णय लिया गया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद और अवैध रूप से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए दोनों देशों की प्रवर्तन निकायों को परस्पर सहयोग करना होगा | भारतीय विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत में विश्व के दो बेहतरीन रक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडकवासला (पुणे) और भारतीय सेना की दूसरी रक्षा अकादमी देहरादून में है | यहाँ पर कजाखस्तान के कैडेट कुशल प्रशिक्षण लेकर भविष्य में कजाखस्तान और भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रकाश डाल सकते हैं | इससे यह ज्ञात होता है कि भारत और कजाखस्तान परस्पर रूप से रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए प्रयासरत हैं | (Tibb 2009: 200).

इस संदर्भ में कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबाएव ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि “कजाखस्तान अब दुनिया के 50 प्रतिस्पर्धी देशों में गिना जा रहा है, क्योंकि कजाखस्तान ने अपने कार्यों के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों की चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष किया है | कजाखस्तान ने वैश्विक स्तर पर पारस्परिक रूप से भारत के साथ लाभप्रद सहयोग को मजबूत करने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करने का भी जिक्र किया है | भारत ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव की कीका (C.I.C.A.) का सदस्य बनाने की पहल की सराहना की है, जो एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंच के रूप में उभर रहा है | सन् 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कीका (C.I.C.A.) के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुये कहा कि कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबाएव की इस महत्वपूर्ण पहल से एशियाई लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना का विकास होगा | कजाखस्तान ने एशियाई लोगों को एक साथ लाने के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अर्जित की है | (Monthy and Swain 2009 : 167-179)

इसके अतिरिक्त कजाखस्तान और भारत ने बहुपक्षीय एकीकरण की पुष्टि करते हुये संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) के ढांचे को एक क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के रूप में देखा है जिसकी दो प्राथमिकताएं हैं सुरक्षा और अर्थव्यवस्था | भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सैन्य समाग्री का निर्यात मध्य एशियाई देशों में करता है | जिससे यह परिलक्षित होता है कि भारत अपने निर्यात का विस्तार कजाखस्तान में भी कर रहा है जिसमें रक्षा सामग्री भी आती है जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है | भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुये संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) देशों के साथ एक सहयोगी के रूप में रक्षात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है | संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) देशों के प्रतिभागी

देशों में से रूस, चीन और भारत मध्य एशियाई देशों से तेल प्राप्त करने के लिए तेल पाइपलाइन का निर्माण करने में शामिल हैं | (Movlonov and Ibrokhim 2006 : 426-431)

कजाखस्तान और भारत दोनों देश अफगान पुनर्निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं | अप्रैल 2010 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वाशिंगटन में हुये परमाणु शिखर सम्मेलन में कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों पर रुचि जाहिर करते हुये चर्चा की, जिसमें किर्गिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति को ध्यान में रखते हुये दोनों देशों के द्वारा देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाये रखने के लिए सहमति जताई | मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और नशीले पदार्थों की तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुये सामरिक सहयोग करने के लिए प्रयास करने की पहल की थी | इस पर कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबाएव ने भारतीय प्रधानमंत्री की पहल की काफी सराहना की और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए कजाखस्तान से सीधी सतह को जोड़ते हुये कजाखस्तान भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा | कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव ने भारत पर हुये मुंबई आतंकी हमलों की निंदा करते हुये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग को तेज करने की आवश्यकता को दोहराते हुये आश्वासन दिया कि कजाखस्तान भारत के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा है और आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे | (Review trade ties 2010: 28)

पाँच सूत्रीय अनुबंध

कजाखस्तान और भारत के मध्य सामरिक संबन्धों का एक नया रूप जुलाई 2015 को सामने आया जब भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कजाखस्तान की राजनीतिक यात्रा करते हैं | जिसका

मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और यूरेनियम की आपूर्ति के लिए अनुबंध करना था | इस यात्रा के दौरान कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबाएव और प्रधान मंत्री मोदी के मध्य अस्ताना में व्यापक रूप से वार्ता किए जाने पर पाँच प्रमुख समझौताओं को शामिल किया गया था जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने सक्रिय रूप से शामिल होने का निर्णय लिया गया था, जो आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ सामरिक रूप से लड़ाई लड़ने को दर्शाते हैं | मोदी और नज़रबाएव ने अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए और सुरक्षा के खतरों को देखते हुये इस प्रकार के अनुबंधों के द्वारा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास किया है | (Ministry of External Affairs, India 2017)

प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरबाएव के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तर की वार्ता के दौरान कजाखस्तान का हाइड्रोकार्बन में समृद्ध रूप से धनी होने के कारण भारत ने कजाखस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए सहमति व्यक्त करने का समझौता किया है | उन्होंने कजाखस्तान के राष्ट्रपति नज़रबाएव के साथ संयुक्त प्रेस समारोह मे बताया की हम वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे | कजाखस्तान और भारत दोनों देश संयुक्त रूप क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए सहमत हुये हैं | दोनों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय शांति स्थापित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास करने के लिए सुरक्षा सहयोग में सामरिक साझेदारी निभाने के लिए रक्षा सामग्री और उपकरणों का विस्तार करके रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के प्रयास पर समझौता किया है | कजाखस्तान और भारत ने अपने अनुबंध में सुरक्षा की दृष्टी को देखते हुये संयुक्त रूप से सैन्य प्रशिक्षण के तहत संयुक्त अभ्यास करना, सैन्य तकनीकी का परस्पर सहयोग करने पर भी समझौता किया है | इससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के दायरे को आगे बढ़ाने की मनसा ज्ञात होती है एवं दोनों देशों की रक्षा सहयोग का विस्तार करने की आकांक्षा जाहिर होती है | (Ministry of External Affairs, India

2017) प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम की खरीदारी के लिए भी कजाखस्तान की कंपनियों के साथ इस पाँच सूत्रीय अनुबंध में समझौता किया है । उन्होने कहा कि कजाखस्तान एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जिनके साथ हमने नागरिक परमाणु सहयोग शुरू किया है और हम इस अनुबंध से खुश हैं एवं आगे भी हम अन्य खनिजों के सहयोग के विस्तार करने में प्रयासरत हैं । कजाखस्तान और भारत ने संयुक्त रूप से आतंकवाद से उभरने के लिए “तेज कदम” जैसे कार्यक्रम भी जारी किया है । दुनिया में विभिन्न हिस्सों में आतंकी भय को देखते हुये इस प्रकार से सुरक्षा को मजबूती मिलने के आसार हैं । जो इन दोनों देशों के क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हुये आर्थिक विकास को सुरक्षित कर सकें । और सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से आतंकवादी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सहमति व्यक्त कर सकें । (Ministry of External Affairs, India 2017)

सैन्य अभ्यास :

कूटनीति जो राज्य यान का एक साधन होती है । इस के अंतर्गत सैन्य कूटनीति भी इसी का एक सबसेट है । राज्यों की सरकारों द्वारा लोकतान्त्रिक राजनीति में सेना की भूमिका एवं नेतृत्व को ही परिभाषित किया जाता है । आमतौर पर राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से देखता है । इसलिए राज्यों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक जुड़ाव को मान्यता दी जाती है । वर्तमान समय में सैन्य बल के जुड़ाव के कारण राज्य के बड़े बड़े कूटनीतिक तर्कों को मजबूती मिलती है । सैन्य बल के जुड़ाव से सशक्त स्टीरिंग समूह (ESGs) प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं और मंत्रियों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके एक दूसरे के बीच रक्षा समन्वय का विकास कर पाते हैं । इस प्रकार के समन्वय से दो या दो से अधिक सेनाओं के साथ विषय विशेषज्ञ विनिमय (SMEE) जैसे कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है । जिनमें दोनों देशों की सेनाओं

को प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षुओं को युद्ध का मुकाबला करने के लिए सैन्य उपकरणों की जानकारी प्राप्त होती है | इस कारण से देश सैन्य अभ्यास कराने के लिए सहमत होते हैं | (Khera 2017 : 17-24)

सैन्य अभ्यास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सैद्धांतिक रूप से तकनीकी संचालन में महत्वपूर्ण सहायता करता है | जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में ज्ञान की वास्तविकता के अनुरूप प्रशिक्षण लिया जाता है जो सैन्य प्रशिक्षण का उच्चतम स्तर है | जिसका मुख्य ध्येय एक साथ प्रशिक्षित करना एक साथ लड़ना है | सैन्य अभ्यास के दौरान सेना का एक मार्गदर्शक सिद्धांत यह होता है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर दोनों के शत्रु समान हैं और दोनों को उसके खिलाफ लड़ना होता है | निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सैन्य गठबंधनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विभिन्न अभ्यासों के बीच अंतःक्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य अभ्यास जैसी योजना को उत्तरी अटलांटिक संधि (NATO) जैसे सैन्य गठजोड़ की ताकतों के साथ जोड़ना होगा इस प्रकार के सैन्य अभ्यास को देखते कजाखस्तान और भारत के बीच “तेज कदम” कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है | (Khera 2017 : 20)

सैन्य प्रशिक्षण की क्षमता उपकरणों पर आधारित होती है | यहा पर विरोधियों के सशत्रु बलों की क्षमताओं का ज्ञान होना आवश्यक है | सामरिक रूप से दोनों देशों को सशत्रु बलों के परिचालन की रणनीति को कुशल बनाने के लिए कुशल उपकरणों का प्रशिक्षण लेना अति महत्वपूर्ण है | वर्तमान काल में संघर्ष उपकरणों के माध्यम से जारी है | इसलिए सैन्य अभ्यास में उपकरणों का अधिक प्रशिक्षण कराया जाता है | इसके लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है | इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सैन्य अभ्यास एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं | इसके अतिरिक्त सैन्य अभ्यास की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता आपदा से संबन्धित

है आपदाएं बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती हैं | किसी भी प्रकार संकट चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित हमले सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है | आपदा काल के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी समझ से दोनों देश आपदाग्रस्त देशों को सेना राहत प्रदान करने का काम करती है | आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत टीमों का गठन संयुक्त सैन्य अभ्यास वाले देशों से किया जा सकता है | उदाहरण स्वरूप हम भारत और नेपाल को देख सकते हैं नेपाल में अप्रैल 2015 में आये भूकंप से लोगों को राहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा प्रदान किए गए कुशल समर्थन द्वारा किया गया था | और नेपाल को राहत पूर्ण मदद की गई थी | इस तरह से कजाखस्तान और भारत भी सैन्य अभ्यास के तहत परस्पर रूप से सहयोगी बन सकते हैं | आज के परिप्रेक्ष्य में कजाखस्तान और भारत ही नहीं सम्पूर्ण वैश्विक स्तर पर यह सैन्य अभ्यास किया जा रहा है जिसमें हर एक देश रुचि जाहिर कर रहा है | (Khera 2017 : 21-25)

कजाखस्तान और भारत के सम्बन्धों का नया रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2015 को राजनीतिक यात्रा के दौरान “तेज कदम” के तहत कजाखस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कराने के विषय में कज़ाक राष्ट्रपति नज़रबाएव के साथ सहमति की | इसके साथ ही साथ दोनों देशों के नेताओं ने सैन्य तकनीकी सहयोग में कदम बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करके एक नई शुरुआत की है, जिसका मुख्य ध्येय आतंक के खिलाफ मुकाबला करना है एवं परस्पर संबंधों को मजबूती देना है | (Ministry of External Affairs, India 2017)

कजाखस्तान और भारत का संयुक्त अभ्यास “ प्रबल दोस्तीक -16 ” के नाम से जाना गया जिसका अर्थ है मजबूत मित्रता | कजाखस्तान और भारत के बीच प्रथम सैन्य अभ्यास की शुरुआत सितंबर 2016 को कजाखस्तान के करगांडा में की गई | इस सैन्य अभ्यास से कजाखस्तान और भारत के रक्षा सम्बन्धों को मजबूती मिली है | इसके अंतर्गत कजाखस्तान की

ओर से विशेष ऑपरेटिंग फोर्स यूनिट और भारत के तरफ से भारतीय सेना की विशेष इकाई ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपनी ताकत को दर्शाया है, एवं कजाखस्तान की सेना के साथ आपसी भाईचारे का संबंध बनाने का प्रयास किया है, जो दोनों देशों की मित्रता का संकेत है | आज वर्तमान काल की स्थिति को देखते हुये इन राष्ट्रों का यह प्रयास सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे सम्पूर्ण विश्व प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देख रहा है | इस चौदह दिवसीय अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र से किस प्रकार काउंटर किया जाये और संयुक्त राष्ट्र की छतरी के नीचे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए विद्रोह संचालन के दौरान अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाने का प्रयास है | यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत पहले चरण में एक दूसरे के साथ रणनीति, ड्रिल, हथियारों और उपकरणों से परिचित करना था जबकि दूसरे चरण में दोनों सेनाओं के सैनिक को एक अनुरूपित वातावरण में एक हेलीकॉप्टर बोलने ऑपरेशन को संयुक्त रूप से निष्पादित करने के लिए लड़ाकू युद्ध अभ्यास तथा शारीरिक फिटनेस व्यायाम इसका मुख्य केंद्र बिंदु था इस प्रकार कजाखस्तान का प्रथम सैन्य अभ्यास 17 सितंबर 2016 को सफल रूप से समाप्त हो गया था | Ministry of defence 2016)

दूसरा सैन्य अभ्यास “प्रबल दोस्तीक 2017”, 2 नवंबर से 15 नवंबर तक भारत के हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह में हुआ। इस 14 दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कजाखस्तान ने भारतीय सेना के 3/11 गोरखा राइफल के साथ जवानों को तैयार किया | सैन्य अभ्यास में लगभग 20 टुकड़ियों ने भाग लेकर कुशल प्रशिक्षण लिया था तथा इस अभ्यास में भारतीय सैनिकों ने कजाखस्तान के सैनिकों को आतंकवादियों का मुकाबला करने और काउंटर विद्रोह के स्थानों पर कम तीव्रता के संघर्ष का संचालन करना सिखाया है जो कजाखस्तान की सेना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि से कम नहीं है। इसके अतिरिक्त कजाखस्तान के सैनिकों ने

भारतीय सेना के जवानों को जंगल में आर्मी ऑपरेशन संचालन का पूरा प्रशिक्षण भी करवाया जों भारतीय जवानों की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी जिसको कजाखस्तान के सैनिकों के द्वारा पूरा किया जा रहा है |



India- Kazakhstan's Joint Exercise

Source: - <https://akipress.com/news:598504/>

इस सैन्य अभ्यास का मुख्य लक्ष्य दोनों सेनाओं के बीच संबंधों और सैन्य कौशल का विनिमय करना था | दो बड़े राज्यों के मध्य आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए इस अभ्यास को निर्धारित किया गया था | इस के तहत दोनों देशों की युद्ध रणनीति व तकनीकी प्रक्रिया को समझा जा सकता है | इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के संचालन से रक्षा सहयोग के लिए एक सार्थक मंच स्थापित होगा और दोनों देशों के मध्य भावनात्मक संबंधों में वृद्धि होगी |
(Ministry of Defence 2017)

कजाखस्तान और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग को हमने विभिन्न आयामों से विवेचना करते हुये आकलन किया की ये दोनों देश आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है | इन देशों की दिशा दशा समान होने की वजह से दोनों देश वैश्विक स्तर पर आतंकवादी खतरों को मद्देनजर रखते हुये अपने रक्षा क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं यह प्रयास द्विपक्षीय रूप से वार्ता करने के कारण संभव हुआ है कजाखस्तान और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये सेना को आधुनिक उपकरणों का ज्ञान एवं उपलब्धि के लिए सामरिक सहयोग कर रही है एवं इन दोनों के मध्य नशीले पदार्थों की होने वाली तस्करी को रोकने का प्रयास किया है | अफगानिस्तान में फैली अशांति के लिए दोनों देशों ने शांति और सुरक्षा के लिए सामरिक प्रयास में सहभागिता का काम किया है, इन देशों के समक्ष समान रूपी खतरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य अभ्यास की शुरुआत से रक्षा संबंधों में मजबूती इसका परिणाम है | आज दोनों देश अपने कूटनीतिक रणनीति से हर एक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने के प्रयास में हैं जिसे दोनों देशों का विकास होना संभव है |

अध्याय-5

निष्कर्ष

कजाखस्तान का उद्भव सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कजाखस्तान ने अपने राष्ट्रीय हितों का विकास करने के लिए वैदेशिक संबंधों के महत्त्व को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए भारत के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय विदेश नीति को प्राथमिकता दी | कजाखस्तान अपने विकास पथ को आगे बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है | पिछले दशकों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती हुई सम्मान जनक भूमिका को देखते हुए कजाखस्तान ने भारत के साथ उच्च स्तर पर सामरिक सहयोग स्थापित करने पर बल दिया है, जो वर्तमान समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जैसी गैर कानूनी समस्याओं का समाधान तभी संभव है | कजाखस्तान और भारत के ऐतिहासिक पहलुओं से पता लगता है कि इन दोनों देशों के संबंध प्राचीन काल से ही जुड़े हुए हैं इसलिए इन देशों का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में कजाखस्तान और भारत के संबंधों को एक अलग महत्त्व के रूप में देखा जा सकता है | वर्तमान काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में कजाखस्तान का महत्त्व भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण है | यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिसके कारण भारत जैसे राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कजाखस्तान के साथ संबंधों का विस्तार करने के लिए तत्पर है | कजाखस्तान यूरेशिया का ऐसा देश है जो ऊर्जा से परिपूर्ण है जिसका लाभ इसके पड़ोसी देश रूस, चीन एवं अन्य मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान भी लेना चाहते हैं | इन सभी तथ्यों से ज्ञात होता है कि कजाखस्तान का महत्त्व वैश्विक स्तर पर निरन्तर बढ़ रहा है जिससे कि कजाखस्तान भारत के लिए ऊर्जा संसाधनों के रूप में सकारात्मक सिद्ध हो सकता है |

कजाखस्तान और भारत के प्राचीन संबंधों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हमने इस वर्तमान अध्ययन में कजाखस्तान के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् की समकालीन नीतियों और मुद्दों पर प्रकाश डाला है | इस अध्ययन में कजाखस्तान और भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के संबंधों का बारीकी से अध्ययन करके दोनों देशों के संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाले तथ्यों को उजागर करने की कोशिश की है जिससे की मौजूदा साहित्य के अंतर को पूरा किया जा सकता हो |

इस शोध के अंतर्गत कजाखस्तान और भारत के भौगोलिक महत्व को समझने का प्रयास किया गया है तथा इन देशों की समान स्थिति को देखते हुये ऐतिहासिक संबंधों के महत्व का अध्ययन करने के पश्चात् मध्य एशिया और भारत के बीच प्राचीन “सिल्क रोड” के महत्व को ध्यान में रखते हुए मध्य एशिया और भारत के संपर्क से होने वाले विस्तार पर प्रकाश डाला गया है | जिससे भारत में विचारों एवं ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है | धर्मों में बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया से चीन तक विकसित हुआ है | सूफी विचारधारा का विस्तार मध्य एशिया से भारत में स्थापित हुआ है | इन विचारधाराओं से कजाखस्तान और भारत के बीच परस्पर सहयोग की भावना विकसित हुई है | “सिल्क रोड” के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ है जो मुख्यतः गणित, शल्यचिकित्सा एवं दर्शन है | (Haidar 2004:35-42)

मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक सम्पर्क कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं किन्तु भारत आज भी “कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी” के तहत जोड़ने के प्रयास में लगा हुआ है, जो मध्य एशिया में वाणिज्य के विस्तार को जन्म देती है | आर्य जनजातियों का प्रवास भारत में मध्य एशिया से हुआ है वैदिक साहित्य के अनुसार कजाखस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र से आर्य जनजातियों का उद्गम हुआ है परंतु बाद में यह क्षेत्र खंडित हो गया |

इस शोध में राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हुये हम विश्लेषण करते हैं कि कजाखस्तान और भारत के संबंध 1991 के बाद दोनों देशों के संबंध राजनीतिक रूप से परस्पर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है साथ ही साथ इसके अंतर्गत दोनों देशों की सामरिक नीतियों का अवलोकन करने से यह भी पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अतिवाद दोनों देशों में समान रूप से फैला हुआ है जिसके विरुद्ध संघर्ष के लिए दोनों देशों ने कीका (C.I.C.A.) और संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) जैसी पहलों के माध्यम से सुधार करने की भूमिका पर भी चर्चा की है, एवं परस्पर राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है | (Ministry of External Affairs 2016)

कजाखस्तान और भारत की आर्थिक, जनसांख्यिकीय क्षमता, और भौगोलिक रणनीति को देखते हुए यह पता लगता है कि इन दोनों देशों के क्षेत्रीय संबंधों का महत्व कैसे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में परस्पर भूमिका अदा करता है |

कजाखस्तान की भौगोलिक रणनीति रूस और चीन के मध्य होने के कारण यह देश यूरोप और एशिया महाद्वीप के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कजाखस्तान यूरेशिया का केंद्र बिंदु होने की वजह से यह पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को जोड़कर एक चौराहे की भांति काम कर सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में होने के कारण कजाखस्तान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के हितों को पूरा कर सकता है |

कजाखस्तान और भारत की विदेश नीति परंपराओं पर आधारित है दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता की भावना जुड़ी हुई है, जो इन देशों की सरकारों के मध्य सहयोग की भावना का प्रतीक है जिससे दोनों देशों के संबंधों के विकास को मजबूती मिलने की आकांक्षा की जा सकती है तथा

दोनों देश के संबंधों की घनिष्ठता के परिणाम को हम राजनीतिक सहयोग की उच्च स्तर की गतिविधियों के रूप में भी देखते हैं ।

1992 में कजाखस्तान के राष्ट्रपति नजरवाएब द्वारा शुरू किया गया कीका (C.I.C.A.) का भारत ने लगातार विश्वास करते हुये सक्रिय रूप से विश्वास निर्माण का समर्थन किया है । भारत ने कजाखस्तान के कीका (C.I.C.A.) की प्रक्रिया में कजाखस्तान की विदेश नीति का समर्थन भी किया है, एवं भारत राजनीतिक रूप से कजाखस्तान का संयुक्त राष्ट्र में भी समर्थन करता आया है । आज के परिप्रेक्ष्य में कजाखस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन करता है, इससे यह ज्ञात होता है कि कजाखस्तान और भारत के संबंध मजबूती से निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त कजाखस्तान और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पारस्परिक रूप से सहायक रहे हैं । कजाखस्तान भारत के लिए विभिन्न रूपों में समर्थन करता आया है । कजाखस्तान ने भारत को 2005 में संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) में पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश दिये जाने के लिए समर्थन किया था और आज भारत कजाखस्तान के समर्थन के कारण पाकिस्तान के साथ संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य है । भारत ने कजाखस्तान के साथ-साथ संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) की नीतियों का पालन करते हुए आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ने का भी समर्थन किया है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुये आतंकी भय को समाप्त किया जा सकता है । (Yerzhan 2009: 4-5)

संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) का ढांचा भारत को मजबूत बनाने में मदद करता आया है भारत को आर्थिक क्षेत्र में निवेश व्यापारिक रूप से सहायक है, जिससे कि भारत की राजकोषीय नीतियों को मजबूत किया जा सकता है । संघाई सहयोग संगठन (S.C.O.) के सदस्य देशों ने भारत के लिए परिवहन मार्ग की अनुमति देने की सहमति जताई है, जिसकी सहायता से भारत

मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क स्थापित करके व्यापारिक विनिमय का विस्तार कर सकता है, एवं कजाखस्तान के साथ परस्पर व्यापारिक संबंध स्थापित करके आर्थिक विकास में भी लाभदायक हो सकता है | कजाखस्तान और भारत के मध्य राजनीतिक वार्ता नियमित रूप से होती रहती है जिससे कि दोनों देशों की समस्याओं को बारीकी से समझा जाता है और एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक रूप से निकाला जा सकता है |

इस शोध में कजाखस्तान और भारत के आर्थिक पहलु दोनों देशों की आर्थिक सहयोग को उजागर करता है जिससे दोनों देशों की आर्थिक क्षमता को समझने के पश्चात्, आर्थिक समस्याओं की पहचान की जाती है तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष रूप से ऊर्जा और तकनीकी सहयोग पर बल दिया जाता है | भारत और कजाखस्तान के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध गतिशील हैं, इन संबंधों को हम आज भी विस्तारित होते हुये देखते हैं उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम आईएसपी करगंडा में धातु संयंत्र की स्थापना करके लाभ प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण किया है और अत्यधिक उद्घोगों के विकास पर बल दिया है | कजाखस्तान और भारत ने संयुक्त रूप से कारखानो का निर्माण भी किया है, इनसे दोनों देशों के आर्थिक विकास के संबंधों में निकटता आई है जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से देखी जा सकती है | कजाखस्तान में 1999 में लगभग 30 भारतीय कंपनी स्थापित हो चुकी थी जिनमें टाटा, रिलायंस, सोनालिका, चन्दन स्टील ग्रुप इत्यादि है | आज भी कजाखस्तान में इन कंपनियों के कार्यालय सक्रिय रूप से पूँजी निवेश कर रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि कजाखस्तान और भारत दोनों देश व्यापार के क्षेत्र में सामरिक सहयोग की भागीदारी रखते हैं | कजाखस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन देशों ने एक ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत छोटे उद्घमों का सम्मिलित रूप से निर्माण करने का फैसला

लिया है | इस प्रकार से कजाखस्तान और भारत के आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धि होती दिखाई देती है |

मध्य एशियाई देशों में कजाखस्तान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है | भारत व्यापार के क्षेत्र में दिवपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है | भारत ने कजाखस्तान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि इत्यादि का व्यापार करता आया है | किन्तु वर्तमान समय में भारत ने कजाखस्तान के साथ उच्च स्तर की व्यापारिक सामग्री पर बल दिया है, जिसमें गैस और यरेनियम जैसे ऊर्जाजनक पदार्थ आते हैं |

कजाखस्तान और भारत के मध्य दिवपक्षीय व्यापार के अंतर्गत आयात-निर्यात को बढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या परिवहन मार्ग की सामने आती है, इन देशों के मध्य कोई ऐसा सीधा मार्ग नहीं है जिससे कि कठिनाई के बिना वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जा सकता हो | वर्तमान समय में दोनों देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरते हुए भूमि मार्ग के माध्यम से आयात-निर्यात करते हैं जिसकी वजह से आतंकी घटनाओं का सामना करना पड़ता है | यदि कजाखस्तान और भारत व्यापारिक संबंधों को दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में जोड़ते हैं तो तेल और गैस के लिए पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन मार्ग का निर्माण कर सकते हैं जिसको नए रेशम मार्ग की संज्ञा दी जा सकती है |

कजाखस्तान और भारत के आर्थिक संबंधों को मद्देनजर रखते हुये एक और समस्या अधिकतर सामने आती है, हार्ड मुद्रा को लेकर मुद्रा का रूपांतरण अनुपलब्धता की कमी के कारण दोनों देशों के लोगों को असुविधा उत्पन्न होती है जिससे कि दोनों देशों के व्यापार पर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है | इससे यह अवगत होता है कि इन देशों के मध्य बैंकिंग चैनलों की कमी है |

इसलिए भारत और कजाखस्तान के बीच व्यापार का विस्तार करने के लिए इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कजाखस्तान और भारत को नए कदम उठाने चाहिए । कजाखस्तान और भारत को व्यापार और आर्थिक सहयोग को तेज़ करने के लिए इटरबैंक जैसे समझौतों को विकसित करने के लिए हस्ताक्षर करने की जरूरत है । इस प्रकार से कजाखस्तान और भारत की आर्थिक संबंधों के विस्तार की खामियों को दूर किया जा सकता है । हम देखते हैं कि कजाखस्तान और भारत की अर्थव्यवस्था परस्पर पूरक हैं, दोनों देशों के मध्य व्यापारिक गतिविधियां सामरिक रूप से अर्थव्यवस्था का विकास कर रही हैं ।

इस शोध के अंतर्गत रक्षा सहयोग को देखते हुए इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कजाखस्तान और भारत के रक्षा सहयोग की भूमिका वर्तमान समय की मांग को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सैन्य बल को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग करता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कजाखस्तान और भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा सहयोग स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं । कजाखस्तान और भारत के लिए रक्षा सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों में आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दे समान रूप से व्याप्त हैं । इन मुद्दों का सामना करने के लिए दोनों देशों को कुशल सैन्य बल की आवश्यकता होती है जो रक्षा सहयोग से ही संभव है । कजाखस्तान और भारत के रक्षा सहयोग एक दशक पूर्व अधिक प्रभावशाली नहीं थे, परंतु अब कजाखस्तान और भारत रक्षा सहयोग करने के लिए लगातार अग्रणी हैं ।

कजाखस्तान और भारत में आतंकवाद का भय और नशीली पदार्थों के फैले जाने के वजह से दोनों देशों के अंतर्गत अशांति उत्पन्न होती है जो राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने का काम करती है और अशांति से विरोध उत्पन्न होता है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को नष्ट कर देता है । नशीले पदार्थों

कि तस्करी से अधिकतर युवा पीढ़ी पर प्रभाव पड़ा है, युवा पीढ़ी को नशे का उपभोगी बना दिया है, जिसके कारण राष्ट्र की प्रगतिशीलता पर प्रभाव पड़ा है | राष्ट्र का विकास युवापीढ़ी के हाथ में होता है आज का युवा यदि नशीले पदार्थों के लत से अपने आप को समाप्त करता है तो देश का विकास होना संभव नहीं है | इस प्रकार के तथ्यों से पता लगता है कि कजाखस्तान और भारत के लिए रक्षा सहयोग कितना महत्वपूर्ण है | कजाखस्तान और भारत ने इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया है |

कजाखस्तान और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को शक्तिशाली बनाना चाहता है इसलिए भारत दिवपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कजाखस्तान के रक्षा बलों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है | दिवपक्षीय सहयोग को गति देने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच एक प्रोटोकॉल के माध्यम से कजाखस्तान और भारत के रक्षा मंत्रालयों ने संयुक्त कार्यकारी समूह का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के माध्यम से सैन्य तकनीकी विकास को मजबूती प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है | आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना क्षेत्र में सुधार और तकनीकी क्षेत्र में निर्माण करना दोनों ही देशों के विकास के लिए सकारात्मक है | कजाखस्तान और भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सामरिक सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि दोनों देशों की नौसेना बलों के लिए आधुनिक हथियार और उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सकें |

भारत और कजाखस्तान ने अपने रक्षा क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए सैन्य अभ्यास की शुरुआत करने पर सहमति व्यक्त की है | सैन्य अभ्यास से प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों देशों की रक्षा संबंधों में निकटता बढ़ने के संकेत हैं, जो दोनों देशों के रक्षात्मक बल के प्रतीक हैं | सैन्य अभ्यास का पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक रूप से महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से वर्तमान

समय में सैन्य बल में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य “एक साथ प्रशिक्षण लेना एक साथ लड़ना” है | भारत और कजाखस्तान के भौगोलिक क्षेत्र पर समान रूपी समस्याओं का सामना करने के लिए दोनों देशों का सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण काफी हद तक सकारात्मक सिद्ध हो सकता है |

कजाखस्तान और भारत ने “प्रबल दोस्तीक” नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2016 में प्रथम बार आरम्भ किया है | इस अभ्यास की शुरुआत कजाखस्तान के करगांडा क्षेत्र में हुई थी, जिसका अर्थ मजबूत मित्रता है | इस सैन्य अभ्यास से कजाखस्तान और भारत के बीच रक्षा संबंधों को मजबूती मिली है | इस सैन्य अभ्यास में कजाखस्तान की ओर से विशेष “ऑपरेशन फोर्स” की इकाई ने भाग लिया है और भारत की ओर से भारतीय सेना की विशेष इकाई ने भाग लिया है, एवं दोनों देशों की सेना द्वारा सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया | इस सैन्य अभ्यास ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी मित्रता का संबंध स्थापित किया है | इसके अलावा दूसरा सैन्य अभ्यास भारत में हुआ है यह हिमांचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह में किया गया | इस चौदह दिवसीय सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने कुशल प्रशिक्षण लिया | इस प्रकार के सैन्य अभ्यास से सैन्य बलों में आत्मविश्वास की भावना जाग्रत होती है | कजाखस्तान और भारत के सामने समान चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा सहयोग को बढ़ाने का प्रयास भविष्य में भी जारी रखना चाहिये |

इस शोध प्रबन्ध की पहली परिकल्पना यह थी कि “भारत और कजाखस्तान के मध्य व्यापार 1991 से 2017 के बीच तेजी से बढ़ा है क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरक है |” इस परिकल्पना को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कजाखस्तान और भारत के मध्य सहयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है | वर्तमान विश्व में कजाखस्तान प्राकृतिक तेल, गैस एवं यूरेनियम निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है किन्तु कजाखस्तान के पास इनके पर्याप्त दोहन

के लिए पूँजी व तकनीकी का अभाव है वहीं दूसरी ओर भारत के पास पर्याप्त मात्रा में उच्च तकनीकी क्षमता विद्यमान है, अतः भारत पूँजी व उच्च तकनीकी के मामले में कजाखस्तान की सहायता कर सकता है ।

वर्तमान समय में भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है किन्तु इसके पास ऊर्जा संसाधनों का अभाव है, कजाखस्तान इस संबंध में भारत की सहायता कर सकता है । कजाखस्तान यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और वर्तमान समय में भारत में नाभकीय विद्युत गृहों का निर्माण तेजी से हो रहा है इसलिए भारत ने कजाखस्तान के साथ यूरेनियम आपूर्ति के संबंध में समझौता किया है अतः इस शोध प्रबन्ध की पहली परिकल्पना सिद्ध होती है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक दूसरे की पूरक हैं ।

इसी प्रकार दूसरी परिकल्पना “कजाखस्तान एवं भारत दोनों ही देश आतंकवाद व नशीले पदार्थों की तस्करी से पीड़ित हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के मध्य सहयोग बढ़ रहा है ।” यदि हम देखें तो इन दोनों ही देशों की सीमाओं के समीप अफगानिस्तान स्थित है और यहाँ पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों जैसे तालिबान, अलकायदा एवं हक्कानी संगठन इत्यादि के द्वारा दोनों ही देशों में आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है । कजाखस्तान में सक्रिय “इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान” और भारत के कश्मीर में सक्रिय “जमात-उद-दवा” के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में सक्रिय इन अतिवादी संगठनों के द्वारा आर्थिक और वैचारिक सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है । इसी के साथ ही साथ अलकायदा जैसे संगठनों के द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अफीम की खेती करवाई जाती है और इसकी तस्करी के लिए भारत और कजाखस्तान का इस्तेमाल “ट्रांज़िट रूट” के रूप में होता है, जो दोनों ही देशों की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है अतः

आतंकवाद के दोनों ही रूपों (आतंकवादी गतिविधियों जैसे बम विस्फोट और “नार्को टेरोरिज़्म”) का सामना करने के लिए ये दोनों ही देश आपसी सहयोग में वृद्धि कर रहे हैं ।

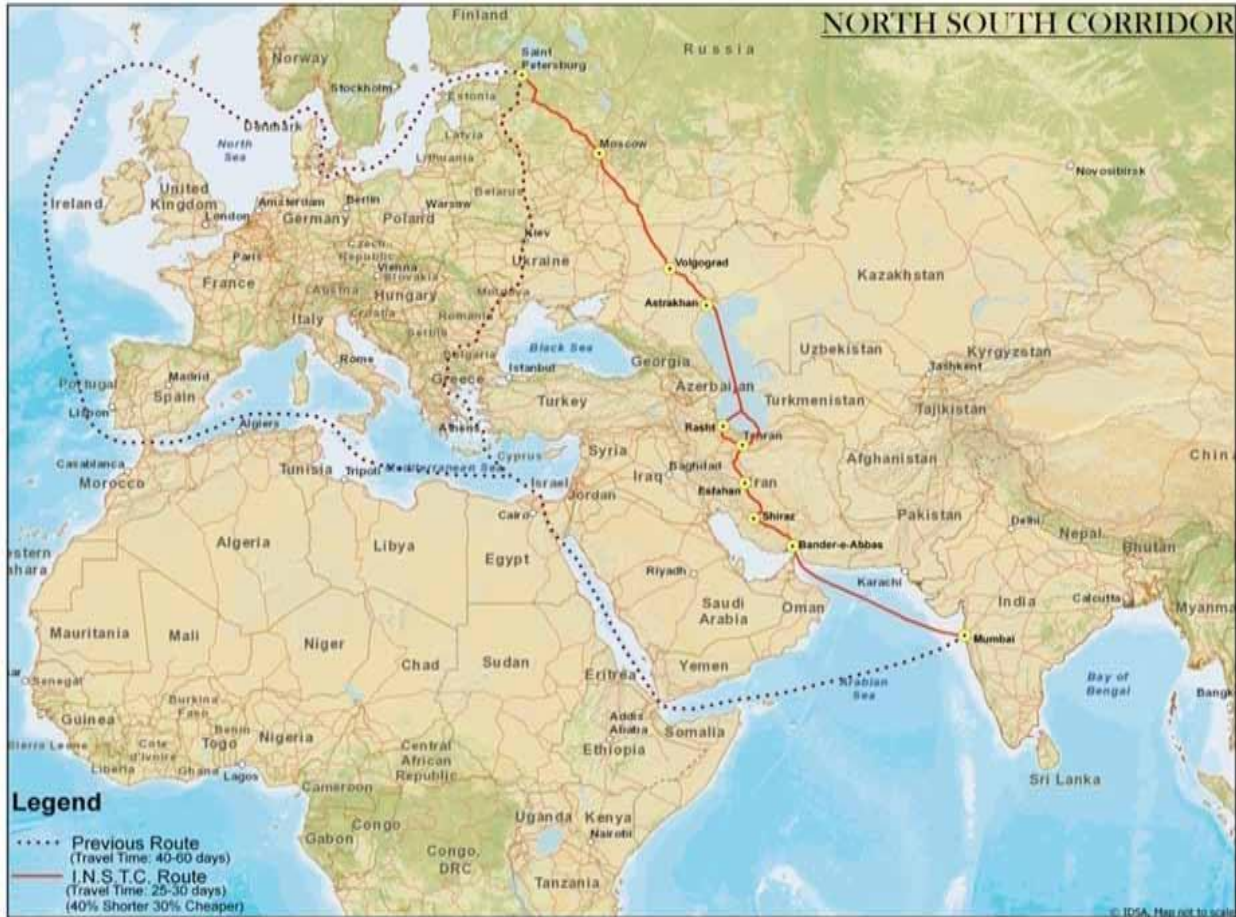
अतः निष्कर्ष स्वरूप इस शोध प्रबंध “भारत- कजाखस्तान संबंध, 1991-2017” में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा सहयोग कि महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर की आवश्यकताओं (युरेनियम, तेल, गैस एवं रक्षा सहयोग) को पारस्परिक सहयोग एवं सामरिक रूप से पूर्ण किया जा सकता है ।

परिशिष्ट

APPENDIX I: Map of Kazakhstan–India’s location.



APPENDIX II : Map of North - South Corridor.



The red line in the map shows the route of North – South Corridor (ISTC).

APPENDIX III

Joint Declaration India and Kazakhstan

New Delhi, February 12, 2002

The people of India and Kazakhstan have an ancient tradition of close and friendly relation which resulted in the development especially of cultural and economic cooperation.

The relations will strengthen further due to our common heritage and commitment to the ideals of tolerance, democracy, secularism and the desire for peace.

The Prime Minister of India expressed his happiness at the visit of President of the Republic of Kazakhstan on the 10th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries.

The two leaders expressed their common resolve that Kazakhstan and India should further enhance their cooperation and mutual consultations on bilateral, regional and international issues so as continue to contribute towards stability and prosperity of their common neighborhood in Asia and the world;

Afghanistan: We have noted with satisfaction the developments in Afghanistan, the establishment of the Interim Administration, the elimination of oppressive Taliban regime and support the resolve of the international community not to allow Afghanistan to be used as safe haven for terrorism. We agree that further efforts need to be made by the international community for the long-term establishment of a broad based multi-ethnic Government in an independent Afghanistan.

Terrorism: Recalling the strong and forthright condemnation by Kazakhstan of the terrorist attack on Indian Parliament on 13 December, 2001, we affirm that terrorism cannot be justified in any form, for any cause or for any reason used as an excuse. We also reiterate our strong belief that the fight against terrorism has to be global, comprehensive and sustained for the objective of total elimination of terrorism everywhere. In this context we recall our commitment to UN Security Council Resolution 1373, and also declare our intent to set up a bilateral forum on counter

terrorism. We reiterate that the global fight against terrorism must also address those who instigate, assist or acquiesce as much as those who perpetuate terrorism.

Regional Initiatives: We acknowledge the importance of frequent consultations to promote peace, stability and prosperity in the region. We have noted with satisfaction the progress of Conference on Interaction & Confidence Building Measures in Asia (CICA) which represented a unique initiative and agree that the forthcoming summit will be a significant step forward. We have also noted the progress being made by the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) as a regional organization. Kazakhstan expressed the belief that considering India's geographical proximity in the neighbourhood and its active participation on regional and global matters of cooperation, India's membership of SCO would add to the strength of that organization.

We have also agreed on the need to give impetus to regional economic cooperation for the common benefit of the people of the two countries and the region. In this context, Kazakhstan with its substantial hydro carbon resources could become an important source of energy to India, which is expected to become one of the largest energy consumers in the world. Similarly, India's prowess in Information Technology would be of great benefit to the needs of Kazakhstan's economy. We have agreed that concrete projects in these sectors will be worked out with a view to early implementation.

Bilateral: We have noted with satisfaction the results of the Fourth Session of Kazakhstan-India Joint Commission on Trade-Economic, Scientific and Technical Cooperation which was held in New Delhi on 11 February, 2002. During the session of the Commission, which was held in the spirit of mutual understanding and constructiveness, new areas of mutually beneficial cooperation were identified. We agreed that effective measures should be taken to implement the agreements reached thereby, which would serve to further strengthen the cooperation in various spheres.

We have also agreed that early action should be taken for finalizing agreements in educational, tourism, Military and Technical Cooperation sectors as well as for the extradition treaty.

The Prime Minister of India noted with satisfaction that the official visit of H.E. Mr. N.A. Nazarbayev, the President of the Republic of Kazakhstan to India made a substantial contribution to the strengthening of relations in political, trade and economic, military-technical, cultural and humanitarian spheres, and expressed confidence that it would promote further activation of the entire range of bilateral cooperation and search for new ways of collaboration.

We have agreed upon the expediency of expanding the Security Council of the United Nations Organization to make it more representative and efficient. The President of the Republic of Kazakhstan, noting the role being played by India in the world affairs, supports India as an appropriate candidate as a permanent member of a restructured UN Security Council.

The President of Kazakhstan invited the Prime Minister of India to visit Kazakhstan at an early date. The invitation was accepted with pleasure.

A.B. Vajpayee

N.A. Nazarbayev

Prime Minister of the India

Republic of President of the Republic of Kazakhstan

<http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/7522/Joint+Declaration+India+and+Kazakhstan>

APPENDIX IV

Tej Kadam: India - Kazakhstan Joint Statement

July 08, 2015

At the invitation of Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan, Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, paid an official visit to the Republic of Kazakhstan on July 7-8, 2015.

During the visit, Prime Minister Modi met with President Nazarbayev and Prime Minister Massimov. The talks were held in a warm and friendly atmosphere in a spirit of mutual understanding, which traditionally characterise India-Kazakhstan relations.

President Nazarbayev and Prime Minister Modi noted the strategic partnership established during the State visit of President Nazarbayev to India in January 2009, based on mutually beneficial cooperation in various spheres and a shared desire for regional and international peace and stability.

Leaders of both countries agreed that the visit of Prime Minister Modi would serve to expand the strategic partnership for the benefit of people of both countries.

Prime Minister Modi congratulated President Nazarbayev on his 75th birth Anniversary and noted the impressive all-round socio-economic development and progress achieved by Kazakhstan, as well as its important role in promoting regional and international peace and security.

Prime Minister Modi congratulated the people of Kazakhstan on Astana Day, the 550th Anniversary of the Kazakh Khanate and the 20th Anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan. Prime Minister Modi underlined the growing political and economic role of Kazakhstan, which contributes to stability and development in the region.

President Nazarbayev noted the importance and role of India in regional and global affairs and appreciated its contribution to peace and stability as well as the positive influence of the rapidly growing economy of India on the world economy. In this, President Nazarbayev sees a special role of the Indian leader in inspiring global confidence in India.

Prime Minister Modi highly appreciated the initiative of President Nazarbayev on institutionalisation of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, which has emerged as an important organisation strengthening peace, stability and security in Asia and noted Kazakhstan's efforts on transformation of the CICA to the Organisation on Security and Development in Asia. President Nazarbayev expressed gratitude for India's continued support of CICA's activity and contribution to the Conference. He also appreciated India's active support to various Kazakhstan's international initiatives, including Expo-2017.

The two Leaders welcomed the signing of an Agreement on defence and military-technical cooperation which would further widen the scope of bilateral defence cooperation including regular exchange of visits, consultations, training of military personnel, military-technical cooperation, joint exercises, special forces exchanges and cooperation in the area of UN peacekeeping operations.

The Leaders welcomed signing of the Treaty on Transfer of Sentenced Persons between the Republic of Kazakhstan and the Republic of India and the Memorandum of Understanding in the field of physical culture and sports.

Prime Minister Modi noted the new economic policy 'Nurly Zhol' (Bright Path) as well as five institutional reforms initiated by President Nazarbayev. In his turn President Nazarbayev highlighted several economic programmes initiated by Prime Minister Modi, including the "Make in India" initiative to transform India into a manufacturing hub.

The Leaders expressed satisfaction at the gradual increase in bilateral trade in recent years, and agreed to work closely to expand bilateral trade by addressing structural impediments between the two countries.

Both Leaders welcomed the organisation of Business Forum with participation of leading business CEOs of both countries as well as creation of a Joint Business council during the visit, which provided a platform for renewed cooperation between the businesses of the two countries. The Leaders noted that the signing of an Agreement between the Chamber of Foreign Commerce of Kazakhstan and Federation of Chambers of Commerce of India (FICCI) will serve to promotion of business linkages. The leaders also emphasized the importance of closer interactions between investment promotion agencies of the two countries.

The Leaders welcomed signing of the Memorandum of Understanding between JSC «Kazxnex Invest» and JSC «Invest India», which includes a "Road Map" on Trade, Economic and Investment Cooperation, which would identify concrete projects in various sectors and assist in efficient implementation of projects in both the countries to activate bilateral trade and economic relations.

The Leaders noted the successful 12th Meeting of the Kazakhstan-India Inter-Governmental Commission (IGC) on Trade, Economic, Scientific, Technological, and Cultural Cooperation in New Delhi on 16-17 June 2015, where new initiatives and proposals to strengthen cooperation in different sectors between countries have been explored. The Leaders called on the IGC to monitor implementation of the understandings reached, including through regular meetings of the various Joint Working Groups at the official level, as well as consultations between foreign offices of both countries on political, consular and visa matters.

Both Leaders welcomed the establishment of Joint Study Group between India and the Eurasian Economic Union on the feasibility of a Free Trade Agreement (FTA). The Leaders acknowledged that the proposed FTA would create an enabling framework for expanding economic linkages between Kazakhstan and India.

The Leaders agreed to collaborate closely in the framework of the International North-South Transport Corridor (INSTC) as well as through bilateral initiatives to improve surface connectivity between two countries and the wider region. They welcomed recent initiatives by India to operationalise the INSTC, including the hosting of a stakeholders conference in Mumbai on 12 June 2015. They called upon the next INSTC Council meeting to be held in India in August 2015 to take necessary decisions to facilitate usage of the corridor by traders of these countries. The Leaders agreed that the Kazakhstan-Turkmenistan-Iran rail-link, operationalised in December 2014, become a linked corridor of the INSTC. The Leaders also welcomed ongoing bilateral discussions aimed at setting up a dedicated freight terminal in one of the Western sea-ports of India for trade with Kazakhstan. They hope that these initiatives will serve as the basis for enhanced economic and commercial interaction between the two countries in the days ahead. In this connection, the Parties welcomed signing of Memorandum on Mutual Understanding on Technical Cooperation in the sphere of railways between the NC "Kazakhstan Temir Zholy" JSC and the Ministry of Railways of India.

The Leaders acknowledged the importance of collaboration in the hydrocarbons sector and welcomed the formal commencement of drilling of the first exploratory well in the Satpayev block which coincided with the visit. They agreed to expeditiously explore new opportunities for further joint collaboration in this sector. The Leaders further noted the agreement reached at the IGC meeting for a joint feasibility study to explore the possibility of transportation of oil and gas either through pipeline or as LNG from Kazakhstan to India.

The Leaders affirmed the importance of cooperation in the sphere of civil nuclear energy. They welcomed the signing of a Contract NC "KazAtomProm" JSC and DAE for a renewed long term supply of natural uranium to India to meet its energy requirements.

The Leaders welcomed the signing of Plan of Action between JSC "KazAgroInnovation" and Indian Council of Agricultural Research for cooperation in the field of agriculture.

The Leaders noted that pharmaceuticals, mining, textiles, information technology, banking, and health are promising areas for future cooperation between the two countries and agreed to extend full support to joint projects in realising potential in these areas on a mutually beneficial basis.

The Leaders welcomed the inauguration of the Kazakhstan - India- Centre of Excellence in Information and Communication Technologies at the L.N. Gumilev Eurasian National University in Astana with India's assistance. They hoped the Centre will contribute to advanced skill development in high performance computing and facilitate scientific research in Kazakhstan.

The Leaders noted the celebration of 50 years of Indian Technical and Economic Cooperation programme and acknowledged the contribution of the ITEC programme in capacity building of nearly 1000 professionals from Kazakhstan in different sectors.

The Leaders noted efforts to enhance air connectivity between the two countries and welcomed the decision to increase the number of frequencies allotted for early operations by designated carriers between the two countries.

The Leaders acknowledged ongoing cultural exchanges in the framework of the bilateral Programme of Cooperation in the field of culture and art. They extended support for organising cultural events in each other's countries and to consider exchange of reciprocal Cultural Festivals

in Kazakhstan and India. With the purpose of further strengthening cultural ties, the Leaders expressed interest in study of common historical heritage and promotion of touristic sites in Kazakhstan and India.

Prime Minister Modi thanked President Nazarbayev for supporting the UN resolution on the International Day of Yoga and successful organisation of the first International Day of Yoga on 21 June 2015 in Kazakhstan.

The two Leaders noted the broad convergence of their views on regional and international issues and their mutual support in international organisations. They emphasized that strengthening of cooperation in multilateral frameworks between Kazakhstan and India would contribute to regional and international stability and development.

The Leaders noted the rising challenge posed by terrorism in many parts of the world and in their immediate region and underlined the importance of a stable and secure environment for peaceful economic development. They agreed to continue their active engagement in the fight against terrorism and extremism including exchange of information.

In this context, they highlighted the importance of regular inter-agency consultations and meetings of the Joint Working Group on Counter-Terrorism. The Leaders also called for early conclusion of the UN Comprehensive Convention on International Terrorism.

Expressing concern at the slow progress on the UN Security Council reform, both leaders called for concrete outcomes to be achieved in the 70th anniversary year of the United Nations. They reaffirmed their commitment to Intergovernmental Negotiations (IGN) to comprehensively reform the Security Council including expansion in both categories of membership.

President Nazarbayev reiterated Kazakhstan's full support for India's permanent membership in an expanded UNSC as well as for India's candidature to the non-permanent seat of UNSC for the period 2021-22. Prime Minister Modi reiterated support for the candidature of Kazakhstan for the non-permanent seat of the UNSC for the period 2017-18.

Both Leaders agreed to strengthen cooperation in the framework of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and underlined that the SCO platform would be a useful addition to ongoing bilateral and regional initiatives to expand cooperation.

The Leaders expressed satisfaction with the outcomes of the official visit and shared the view that this visit has made a positive contribution towards expansion of the strategic partnership between the two countries. President of Kazakhstan Nazarbayev expressed deep appreciation to Prime Minister Modi for the visit which underlines the importance which India places on the development of its relations with Kazakhstan.

Prime Minister Modi expressed his gratitude to President Nazarbayev and the Government of the Republic of Kazakhstan for the warm hospitality extended during the visit.

Prime Minister Modi invited President Nazarbayev to visit India. The invitation was accepted with pleasure.

Astana

July 8, 2015

http://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/25437/Tej_Kadam_India__Kazakhstan_Joint_State_ment

APPENDIX V

Almaty Act

Preamble

We, the Heads of State or Government of the Member States of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA),

Having met in Almaty at a time of profound changes which are taking place in Asia and the world to set up our vision of security in Asia and enhance our capabilities for co-operation on issues of common concern for our peoples;

Recognising the close link between peace, security and stability in Asia and in the rest of the world;

Committing ourselves to working to ensure peace and security in Asia and making it a region open to dialogue and co-operation;

Believing that the CICA process presents new opportunities for co-operation, peace and security in Asia;

Declaring our determination to form in Asia a common and indivisible area of security, where all states peacefully co-exist, and their peoples live in conditions of peace, freedom and prosperity, and confident that peace, security and development complement, sustain and reinforce each other;

Reaffirming our commitment to the UN Charter, as well as to the Declaration on the Principles Guiding Relations Among CICA Member States, which is an integral part of the Almaty Act, as the basis for our future co-operation;

Considering that all aspects of comprehensive security in Asia, including its political and military aspects, confidence-building measures, economic and environmental issues, humanitarian and cultural co-operation, are interdependent and interrelated and should be pursued actively;

Confident that full, equal and comprehensive implementation and observance of the principles, provisions and commitments enshrined in the Almaty Act will create the conditions for advanced co-operation among the CICA Member States and will guide us towards a better future, which our peoples deserve;

Have adopted the following:

I. Security and co-operation

1. The main objective and thrust of the CICA will be to enhance co-operation through elaborating multilateral approaches towards promoting peace, security and stability in Asia.
2. In order to achieve this objective, the Member States will take the necessary steps to develop the CICA as a forum for dialogue, consultations and adoption of decisions and measures on the basis of consensus on security issues in Asia.
3. We call upon and continue to encourage all Member States who are parties to a dispute to settle this peacefully in conformity with the principles envisaged in the UN Charter.
4. Recognising the contribution which increased trade and economic co-operation can make for the prosperity and stability in Asia and to the well-being of their peoples, we will make further efforts to promote initiatives in these fields, as mentioned in the Declaration on the Principles Guiding Relations among the CICA Member States. We also recognise the need for better co-operation on all issues which constitute risks to the environment.
5. The Member States reiterate their belief that protection of human rights and fundamental freedoms in accordance with the UN Charter and the international conventions and instruments to which they are parties contributes to the consolidation of peace, security and stability in Asia. They also declare their readiness to further their co-operation in this field in a spirit of friendliness.
6. We consider that humanitarian issues, such as natural disasters and refugee flows, are areas of common concern since they also affect stability and security in the region. The Member States are resolved to developing measures, where necessary, to address these issues through co-operation in the region as well as with the UN and other relevant international organisations.
7. We believe that enhancing mutual respect, mutual understanding and tolerance in the relations among civilisations is an important goal for our times. Noting with satisfaction the designation of the first year of the millennium as the year of Dialogue among Civilisations, we shall encourage and strengthen this process.
8. We consider globalisation as a challenge of our time. While it could offer certain opportunities for growth and development, at present the benefits of globalisation are unevenly shared among

the nations and much remains to be done to ensure that its benefits be comprehensively and equitably distributed at the global level.

9. Joint actions and co-ordinated responses are necessary to deal with challenges and threats that our states and peoples are faced with.

II. Challenges to security

10. The Member States seek to promote regional and international security and stability, which will also contribute to peaceful settlement of existing and prevention of the emergence of new crisis situations and disputes.

11. The continuing existence and proliferation in all its aspects of nuclear weapons, as well as chemical and biological weapons, pose a great threat to all humanity. The Member States pledge to support the efforts for the global elimination of all weapons of mass destruction (WMD) and therefore they commit themselves to an increased co-operation for the prevention of proliferation of all such weapons, including nuclear weapons, which constitute a particular danger to international peace and security.

12. With the end of the Cold War, the opportunity now exists for the international community to pursue nuclear disarmament as a matter of the highest priority. We shall encourage all nations to keep all options open for achieving this aim, including the possibilities of convening an international conference to identify ways of eliminating nuclear dangers and negotiating a comprehensive and verifiable nuclear weapons convention. We affirm the importance of the early realisation of the universal adherence to the multilaterally negotiated instruments on the elimination of WMD, and urge those states not yet party to these instruments to accede to them as soon as possible.

13. We support the establishment of zones free from nuclear weapons and other WMD in Asia on the basis of arrangements freely arrived at among the states of the region concerned. The establishment of such zones in regions for which consensus resolutions of the UN General Assembly exist, such as the Middle East and Central Asia, should be encouraged; in this context, we invite adherence to internationally negotiated disarmament and non-proliferation instruments in accordance with all the provisions of the relevant consensus resolutions of the UN and the positions of states concerned on the implementation of these resolutions.

14. The Member States reaffirm their belief in the need of ensuring security at the lowest level of armament and military forces. We recognise the necessity to curb excessive and destabilising accumulation of conventional armaments. We emphasise the importance of the maintenance of the international strategic stability to world peace and security and to the continued progress of arms control and disarmament. We emphasise the importance of multilateral negotiations on the prevention of an arms race in outer space.

15. We believe that direct or indirect threat or use of force in violation of the UN Charter and international law against the sovereignty, territorial integrity and political independence of the states; denial of the right to self-determination of peoples which remain under foreign occupation (a right which has to be exercised in accordance with the UN Charter and international law); interference in the internal affairs of states and offensive strategic doctrines pose threats to regional and international peace.

16. The Member States unconditionally and unequivocally condemn terrorism in all its forms and manifestations as well as any support or acquiescence to it and the failure to directly condemn it. The threat posed by terrorism has been increasingly growing over the last decade. Terrorism in all its forms is a trans-national threat, which endangers the lives of individuals and peoples and undermines the territorial integrity, unity, sovereignty and security of states. The menace of terrorism has been magnified by its close links with drug trafficking, illicit trafficking of small arms and light weapons (SALWs) and their transfers in any form to terrorist groups, racist ideologies, separatism, all forms of extremism which present basic sources of financing and providing manpower for terrorist activities. We regard as criminal all acts, methods and practices of terrorism and declare our determination to co-operate on bilateral as well as multilateral basis to combat terrorism including its possible sources. In order to eradicate this menace to peace and security, we shall reinforce and unite our efforts in order not to allow terrorism in any form to be prepared, assisted, launched and financed from the territory of any state and we shall refuse to provide terrorists with safe haven and protection.

17. We recognise that implementation of the UN Conventions will contribute to tackling the problems of terrorism and support the elaboration of a Comprehensive Convention on International Terrorism.

18. Separatism is one of the main threats and challenges to the security and stability, sovereignty, unity and territorial integrity of states. The Member States shall not support on the territory of another Member State any separatist movements and entities, and, if such emerge, not to establish political, economic and other kinds of relations with them, not to allow the territories and communications of the Member States to be used by the above-mentioned movements and entities, and not to render them any kind of economic, financial and other assistance. We reaffirm the right of people living under foreign occupation for self-determination in accordance with the UN Charter and international law.

19. We reject the use of religion as a pretext by terrorists and separatist movements and groups to achieve their objectives. We also reject all forms of extremism and will work to promote tolerance among our nations and peoples.

20. Illicit drug trafficking represents a major threat to internal and international stability and security of our states and our continent as a whole as well as to the well-being of our peoples. This problem is closely linked with the socio-economic and political situation in several regions, terrorist activities across the world, and international criminal groups engaged in trans-national crime, money laundering and illicit SALW trafficking. We recognise that there are several states in Asia which require priority attention and assistance by the international community in order to combat drug trafficking. We also recognise the need for effective strategies to reduce production, supply and demand for drugs. In this respect, we will co-operate to monitor suspicious financial flows, including issues related to incomes and transparency of bank operations in accordance with the existing international legal instruments, and to identify the sources of production, consumption and trafficking of drugs. In order to assist the practical implementation of these tasks, multinational training courses and exercises as well as exchange of information among the competent authorities of the Member States will be promoted. We also call upon major consuming countries to play a more active role in providing equipment, training and educational courses, rehabilitation, technical and financial assistance to Asian drug producing and transit countries. Adoption and implementation of crop substitution plans and alternative development strategies in drug producing regions in Asia should also be encouraged to tackle the menace of illicit drugs more effectively.

21. We also recognise corruption as a trans-national crime which calls for concerted multilateral action. In this regard, we emphasise the need for banning the transfer of illicit funds and wealth and also the need for enhanced international co-operation in tracing and repatriating such assets.

22. The Member States recognise that illicit traffic in small arms and light weapons poses a threat to peace and security and is directly linked with terrorist activity, separatist movements, drug trafficking and armed conflicts. In this context, we underline the importance of the Firearms Protocol reached in the framework of the UN Convention against Transnational Organised Crime and the Programme of Action adopted by the UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects which was held in New York in July 2001.

23. We are determined to co-operate with each other on bilateral and multilateral basis to prevent such threats to peace and security in Asia.

III. Confidence Building Measures

24. In the context of achieving CICA objectives, we will take the necessary steps for the elaboration and implementation of measures aimed at enhancing co-operation and creating an atmosphere of peace, confidence and friendship. Such measures should be in accordance with the principles of the UN Charter, CICA, and international law. In doing so, we will take into account specific features and characteristics in various regions in Asia and proceed on a gradual and voluntary basis.

25. We encourage all states in the region having disputes to make efforts to solve their disputes peacefully through negotiations in accordance with the principles enshrined in the UN Charter and international law. We recognise that the resolution of territorial and other disputes and implementation of arms control agreements may, depending upon specific situations, facilitate implementation of confidence building measures (CBMs); on the other hand, we also recognise that implementation of CBMs may, depending upon specific situations, facilitate, or create a conducive climate for, the resolution of disputes and arms control agreements.

26. We recognise that disarmament and arms control, universality of all internationally negotiated instruments on the elimination of weapons of mass destruction, promoting non-proliferation, have a significant role in enhancing confidence building among regional states. We affirm that being a State Party to the relevant internationally negotiated instruments should not be interpreted as

affecting the inalienable right of all parties to those treaties to develop research, production and use of nuclear technology, chemical and biological materials and equipment for peaceful purposes in accordance with the provisions of these instruments. We reiterate the importance of negative security assurances to the non-nuclear-weapon states and express our readiness to consider further steps on this subject which could take the form of an internationally legally binding instrument.

27. The Member States will prepare with mutual agreement a “CICA Catalogue of Confidence Building Measures” and proceed on a gradual basis for its implementation. The Catalogue, which will be regularly reviewed and further developed, may include, among others, measures in the military–political, economic and environmental, humanitarian and cultural spheres.

IV. Structure and institutions of CICA

28. In order to facilitate its efficient functioning, we have decided to provide for CICA the necessary structure and institutions, consisting mainly of the following:

1. Regular meetings

29. The meetings of the Heads of State or Government will be convened every four years in order to conduct consultations, review the progress of, and set priorities for CICA activities. Special meetings may be convened as necessary by consensus. Summit meetings will be preceded by meetings of the Ministers of Foreign Affairs.

30. The Ministers of Foreign Affairs will meet every two years. Their meetings will be the central forum for consultations and examination of all issues related to CICA activities. Special meetings may be convened as necessary by consensus.

31. The Committee of Senior Officials will meet at least once a year to follow-up on previous CICA decisions, carry out consultations on the current CICA issues, oversee the work of Special Working Groups and co-ordinate the work of other meetings. The Committee will also make the necessary preparations for the organisation of the Summit and ministerial meetings, including elaboration of draft documents.

32. Special Working Groups will be established to study specific issues relevant to CICA’s areas of interest and to carry out the tasks mandated to them. They will submit the results of their work to the Committee of Senior Officials.

2. Specialised meetings

33. The Member States may agree to convene meetings of other ministers or of the competent national agencies and institutions in order to discuss issues of a specific and/or technical nature.

3. Academic and professional inputs

34. Opportunities will be provided as necessary for academic and professional inputs and reports, as well as assistance and contributions to publications which CICA may decide to produce.

4. Secretariat

35. In order to provide follow-up and administrative support for regular meetings and political consultations and other activities mentioned in the Almaty Act, we support the establishment of a Secretariat of the CICA. We task our Ministers of Foreign Affairs to finalise the elaboration of all aspects related to the establishment of the Secretariat.

Done in Almaty, June 4, 2002

Kazakhstan News Bulletin Released weekly by the Embassy of The
Republic of Kazakhstan

http://www.kazakhembus.com/Almaty_Act.html

201

संदर्भ सूची

REFERENCES

(*indicates a primary sources)

Abdykarimov, A. (1994) *History of Kazakhstan from ancient times to the present day*, Almaty: Atamura.

Abuseitova, M., (2004), “Historical and cultural relations between Kazhakhstan, Central Asia and India from ancient times to the beginning of the XX century”, *Dialogue*, 6 (2) 1-14.

*Addresses of the President of the Republic of Kazakhstan to the People of the Kazakhstan (annual1998-2006), [online: web] Accessed 30 May 2018 http://www.akorda.kz/page.php?page_id= 156&Lang=2.

Ashgar, Tahir, in interview to Security Research Review, *The Journal Of Bharat-Rakshak.com*, [online web] Assessed 29 June 2006, URL: <http://www.bharat-rakshak.com/SRR12006/0I/65-0il%20DipIomacy.html>.

Banerjee, D. (1996), “Central Asia Republic Today”, *Strategic Analysis*, 5(9), 725-41.

Blarel, Nicolas (2012), “India: the next superpower?: India's soft power: from potential to reality? IDEAS reports - *special reports*”, Kitchen, Nicholas (eds.), and London UK: SR010. LSE IDEAS, London School of Economics and Political Science.

Brunet, M. F., Volozh, Y. A., Antipov, M. P., & Lobkovsky, L. I. (1999), “The geodynamic evolution of the Precaspian Basin (Kazakhstan) along a north–south section”, *Tectonophysics*, 313(1-2):88-105.

Cochan, Ariel. (2006), *Kazakhstan energy cooperation with Russia – Oil and Gas beyond*, London: GBM Publishing Ltd.

Constitution of the Republic of Kazakhstan, (1996) Almaty, *Vedomosti Parlamenta: 4*.

*CTBTO (2007), “Kazakhstan Ratifies Comprehensive Nuclear Test-Ban –Treaty”, [Online: web] Accessed 29 May 2018, URL: <https://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2002/kazakhstan-ratifies-comprehensive-nuclear-test-ban-treaty/>.

Dadwal, S.R. (1999) “Energy security: India’s options”, *Strategic Analysis*, 23(4): 653-670.

Dave, Bhavna. (2007), *Kazakhstan – Ethnicity, Language and Power*, London: Routledge.

Dwivedi, R. (2006, November). China’s Central Asia policy in recent times. In *China and Eurasia Forum Quarterly*. 4. (4): 139-159.

*Embassy of India Astana, Kazakhstan, (2017), “Bilateral trade between India and Kazakhstan”, 10 April 2018 Accessed URL: <http://www.indembastana.in/ieb.php?id=Investment%20Statistics>

*Embassy of India, Astana (2010), “*India – Kazakhstan relations*”, [Online: web] Accessed 25 March 2018 URL: http://pharmexcil.org/data/country_files/Kazakhstan.pdf.

*Embassy of the Republic of the Kazakhstan (2015), Government of Kazakhstan, ‘Presidential Elections 2015: understanding Kazakhstan politics’, Newsletter of Embassy of Republic of the Kazakhstan: The Diplomat. March – April: 1-2.

Forecast News, (2017), “Kazakhstan GDP”, [Online: web] Accessed 20 March 2018, URL:<https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp>.

Fredholm, M. (2013), “ Too Many Plans For War, Too Few Common Values: Another Chapter in the History of the Great Game or the Guarantor of Central Asian Security ?” , in Michael Fredholm (eds.) *The Shanghai Cooperation organization Geopolitics , New Directions, perspectives and Challenges*, U.K., NIAS Press.

Gleason, Gregory. (2003), “Markets and politics in Central Asia.”, *London: Routledge*, (2): 33-39.

Grousset, Rene. (1988) *The empire of the steppes: A history of central Asia*, Translated by Naomi walford, London: Rutgers university press.

Habib, M.A. (2018), “How China got Sri Lanka to cough up a port”, *New York Times*, New York, [6 June 2018].

Haidar, M. (2004), *Indo-Central Asian Relations: From Early Times to Medieval Period*, New Delhi, Manohar Publications.

Hanks, R. R. (2009), ‘Multi-vector politics’ and Kazakhstan's emerging role as a geo-strategic player in Central Asia. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 11(3), 257-267.

Hussain, Z. (2009). “*India and Kazakhstan: New Ways Ahead*”, [online: web] Accessed 26 March 2018 URL: http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/IndiaandKazakhstan_ZHussain_180209.

Jacob, Jayanth. (2015), “Underlying themes of PM Modi’s central Asia ” *Hindustan times*, New Delhi, 6 July 2015.

Jha, M. (2016), “India’s Connect to Central Asia Policy a look back at India –Central Asia relations in the post-Soviet era”, *The Diplomat* [Online: web] Accessed 2 June 2018 URL: <https://thediplomat.com/2016/12/indias-connect-central-asia-policy-2/>.

Khaliq, A. (2018), “Is Pakistan falling into China’s debt trap?” *CADTM The abolition of second legitimate Debt*. Pakistan, 16 April 2018.

Khazhmuratova, A.M. (2010), *Kazakhstan –India relations, 1991-2006*, PhD. Thesis, New Delhi: Jawaharlal Nehru University.

Khazhmuratova, A.M. (2010). “*Kazakhstan – India Relations Historical Prospective*”, [Online: web] Accessed 12 Feb. 2018 URL: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18330/7/07_chapter%201.pdf.

Kozhokin, Y. (2001), “Shanghai Five: Present Realities and Future Prospects”, *Strategic Digest*, 131(7): 885.

Mackinder, H.J. (1904), “The geographical pivot of history”, *Geographical Journal*, 23(4): 421–37.

Mavlonov, Ibrokhim R. (2004), “India’s Economic Diplomacy Trends with Central Asia: The Potentials and Priorities”, *Contemporary Central Asia*, 3 (1): 5.

Mavlonov, Ibrokhim R. (2006), “Central Asia and South Asia: Potential of India’s Multilateral Economic Diplomacy in Inter-Regional Cooperation”, *IDSAs Strategic Analysis*, 30(2) 324-349.

Mehmahan P. (2001), “ UN: Kazakhstan calls for new approach on Afghan peace, Radia free Europe Radio Liberty [online web] Accessed 24 May 2018 URL: <https://www.rferl.org/a/1096483.html>.

*MEA (2012) Statement by Mr. Sanjay Singh, Secretary (East) Meeting in Bishkek”, [online: web] Accessed 28 May 2018, URL: <http://www.mea.gov.in/in-focus/article.htm?20907/Statement+by+Mr+Sanjay+Singh+Secretary+East+at+the+SCO+Heads+of+Government+Meeting+in+Bishkek>.

*MHA (2017), “Introduction of India”, [Online: web] Accessed 14Feb.2018.URL: https://web.archive.org/web/20171010161225/http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/BMIintro-1011.pdf.

*Ministry of external Affairs (2007) Government of India, *Newsletter of Ministry of external Affairs*: 4th meeting of India- Kazakhstan joint working group on counter terrorism 3 May 2017.

*Ministry of External Affairs (2016) Government of India, Ministry of External Affairs, *India – Kazakhstan Relations*, New Delhi, July, 2016.

Morgenthau, H. J., and K. Thompson. (1992), “*Politics among nations*,” brief edition.

*Official site of the President of the republic of Kazakhstan (2017), Third modernization of Kazakhstan Global competitiveness, newsletter official site of the President of the republic of Kazakhstan [Online web] Accessed 4 May 2018. URL: <http://www.president.kz/en>.

Panasyuk, M. V., Gafurov, I. R., & Novenkova, A. Z. (2013). “Influence of international transport and logistics systems on economic development of the region”, *World Applied Sciences Journal*, 27:135–139.

Panchal, Salil (2017), "58 India companies in 2017, Forbes Global 2000' list", *India Forbes*, India [24 May 2017].

Patnaik, A. (2004), "Russian minority in Central Asia", *World Focus*, 25 (3): 430-433

*PIB Government of India Ministry of Defence (2016), Government of India, "*India – Kazakhstan joint exercise "PRABAL DOSTYT-16"*", [Online web] Accessed 27 May 2018 URL: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=14959>

*PIB Government of India Ministry of Defence (2017), Government of India, "*India – Kazakhstan joint exercise "PRABAL DOSTYT-16"*", [Online web] Accessed 27 May 2018 URL: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=14959>

Piddock, Charles (2007), *Kazakhstan*, Milwaukee, WI: World Almanac Library.

*PM's Statement prior to his departure for Kazakhstan to attend the CICA Summit" (2002), annual report of the Indian Ministry of External Affairs, [Online web] URL: <http://meaindia.nic.in/speech /2002/06/02spc01.html>.

*PMO.Office. (2002), "PM's Statement Prior to his departure for Kazakhstan to attend the CICA Summit", [Online: web] Accessed 23 May 2018 URL: <http://pibarchive.nic.in/archive/releases98/lyr2002/rjun2002/02062002/r020620021.html> .

Prembetov, D.S. and S. Mukashev (2016), "Terrorism in Central Asia and Kazakhstan." *Global Media Journal*, S3 (22): 1-5.

Press trust of India (2009), "India hands overs strategic highway to Afghanistan", *The Hindu*, New Delhi, [23 January2009].

Press trust of India (2015), “India to renew contract with Kazakhstan for uranium supply”, *The Indian Express*, New Delhi, and [6 July, 2015].

Press trust of India (2015), “India, Kazakhstan sign five key agreements”, *The Hindu*, New Delhi, [8 July 2015].

Press trust of India (2017), “India, Kazakhstan agree to amend tax treaty”, *The Economic Times*, New Delhi, [6 January 2017].

PTI, (2017), “Enhance Connectivity without Infringing on their Sovereignty, Modi tells SCO nations”, *The Hindu*, Astana, 9 June 2017.

Rajagopaln, R.P. (2008) “Indo- Us Nuclear Deal, implications for India and the global N-Regime”, *IPCS Special Report*, (6): 1-4.

*Report of the FICCI (2011), “India- energy security” [Online: web] Accessed 17 Feb. 2018. URL: [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Indias_energy_security/\\$FILE/India's_energy_security.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Indias_energy_security/$FILE/India's_energy_security.pdf) .

Review trade ties (2010), *Kazakh-Indian business*, 1 (5): 28.

Riedel (2008), “Terrorism in India and the Global jihad”, Brookings”, *Quatr tribune*, 30 Nov. 2008.

Roy, M. S. (2002), “India-Kazakhstan: Emerging ties”, *Strategic Analysis*, 26(1): 48-64.

Roy, Oliver (1994), “*The New Central Asia: The Creation of Nations*”, New York: New York University Press.

Roy, S. M. (2014). *The Shanghai Cooperation Organization: India Seeking New Role in the Eurasian Regional Mechanism*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.

Rudenko, Y. I. (2006), “Modern Corridors of Transport along the Silk Roads between Central and South Asia”, *Central Asia*: 12.

Saltanat, N. (2009), “India –Kazakh trade and economic relations”, in Arun Mohanty and Sumant Swain (eds.) *Contemporary Kazakhstan the Way Ahead*, New Delhi: Axis Publications.

Sarkar, B. and Shams-Ud-Din. (2003) “*Afghanistan and Central Asia in the New Great Game*”. New Delhi, Lancer's Books.

*SCRF (2018) Vladimir Putin held meeting with the permanent members of Security Council. Official site, [Online web] Accessed 6 May 2018. URL: <http://www.scrf.gov.ru/>, Accessed on May 6 2018.

*SDPI 2016, “China Pakistan Economic Corridor, A Chinese Dream Being Materialized through Pakistan”, [Online: web] Accessed 4 June 2018 URL: [https://sdpi.org/publications/files/China-Pakistan-Economic-Corridor-\(Shakeel-Ahmad-Ramay\).pdf](https://sdpi.org/publications/files/China-Pakistan-Economic-Corridor-(Shakeel-Ahmad-Ramay).pdf)

Sengupta, Anita, “India and Central Asia”, *World Focus*, (21): 189-193.

Sharma, A.S. (2009), “India –Kazakhstan Relations, 1991-2008”, in Arun Mohanty and Sumant Swain (eds.) *Contemporary Kazakhstan the Way Ahead*, New Delhi: Axis Publications.

Sharma, A.S.(2010), *India and Central Asia, Redefining Energy and Trade links* , New Delhi , PENTAGON PRESS.

Show. "(2017), "Uranium production in the world by the country [online: web] Accessed 1 April 2018 URL <https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/uranium-producing-countries/>.

Sorbelia, P. and Goldini (2017), "What all the fuss about terrorism in Central Asia?" [Online web] Accessed 20 May 2018 URL: <https://thediplomat.com/2017/08/whats-all-the-fuss-about-terrorism-in-central-asia>.

Stobdan, P. (2008), "India and Kazakhstan should share complementary objectives", *Strategic Analysis*, 33(1):1-7.

Suhag, P.S. (2017), *India's membership in shanghai cooperation organization: An Appraisal*, New Delhi, Defence studies & Analyses.

Tibb, P.S. (2009), "India –Kazakh trade and economic relations", in Arun Mohanty and Sumant Swain (eds.) *Contemporary Kazakhstan the Way Ahead*, New Delhi: Axis Publications.

Tong, D. Q., Wang, J. X., Gill, T. E., Lei, H., & Wang, B. (2017). "Intensified dust storm activity and Valley fever infection in the southwestern United States", *Geophysical Research Letters*, 44(9), 4304-4312.

Vaidyanath, R. (1967), *The Formation of Soviet central Asian Republics: A study in soviet Nationalities policy 1917-1936*, New Delhi : People's publishing house.

WISE (2015), "Uranium mining", [online: web] 8 April 2018 Accessed URL: <https://www.wiseinternational.org/nuclear-energy/uranium-mining>.

WNN, (2015), “Kazakhstan agrees to supply uranium to India”, [Online: web] Accessed 4 April 2018 URL: <http://www.world-nuclear-news.org/UF-Kazakhstan-agrees-to-supply-uranium-to-India-0807156.html>.

*Worldview release video (2014) “The strategic important of Caspian Sea”. [Online web] Accessed on 03 May URL: <https://worldview.stratfor.com/article/strategic-importance-caspian-sea>. Accessed on: 3 May 2018.

Yenikeyeff, S.M. (2008), “*Kazakhstan’s Gas Export markets and export Routes*”, oxford: oxford Institute for energy

Yenikeyeff, S.M. (2008), *Kazakhstan’s Gas Export markets and export Routes*, oxford: oxford Institute for energy.

Zakir Hussain (2009), “India and Kazakhstan: New Ways Ahead”, [Online web] Accessed 18 May 2018 URL: http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/IndiaandKazakhstan_ZHussain_180209